रजिस्ट्री सं॰ डी(डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1977/पौष 25, 1898
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1977/PAUSA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 30th November, 1976 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
468.	का॰ आ॰ 699(अ), दिनांक 1 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	सीमेंट नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 1976।
	S.O. 699(E), dated 1st Nov. 1976.	Ministry of Industry	Cement Control (Fourth Amendment) Order, 1976.
469.	का॰आ॰ 700(अ), दिनांक 1 नवम्बर, 1976	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं॰ 56/75-I के दिनांक 31-1-75 में संशोधन।
	S.O. 700(E), dated 1st Nov. 1976.	Election Commission of India	Amendment to Notfn. No. 56/75-I of 31-1-75.
470.	का॰आ॰ 701(अ), दिनांक 2 नवम्बर, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृत करना।
	S.O. 701(E), dated 2nd Nov. 1976.	Min. of Information and Broadcasting.	Approval of Films specified in Schedule thereto.
471.	का॰आ॰ 702(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 1976	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	धनकर (तृतीय संशोधन) नियम, 1976।
	S.O.702(E), dated 3rd Nov. 1976.	Central Board of Direct Taxes	Wealth-tax (Third Amendment) Rules, 1976

1	2	3	4
472.	का० आ० 703 (अ)/18ई/आई० डी० आर० ए०/76. दिनांक 3 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स सेन रेलेह लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत।
	S.O.703(E)/18E/IDRA/76, dated 3rd Nov. 1976.	Ministry of Industry	Take over of the management of the industrial undertaking of M/s Sen Raliegh Ltd, Calcutta by Sh. M. K. Modwel.
	का० आ० 704(अ)/18ई०/आई०डी०आर०ए०/76, दिनांक 3 नवम्बर, 1976	—तदैव—	श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज, (लगस) प्रा० लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत।
	S.O. 704(E)/18E/IDRA/76, dated 3rd Nov. 1976.	-Do-	Take over of the management of M/s. Ancillary Industries (Lugs) Private Ltd., Calcutta by Shri M. K. Modowel.
	का० आ० 705(अ)/ 18ई०/आई०डी०आर०ए०/76, दिनांक 3 नवम्बर, 1976	—तदैव—	श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स सेन और पण्डित इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत।
	S O. 705(E)/18E/IDRA/76, dated 3rd Nov. 1976.	-Do-	Take over of the management of M/s. Sen and Pandit Industries Ltd., Calcutta by Shri M K. Modwel
	का०आ० 706 (अ)/18 ई०/आई०डी०आर०ए०/76, दिनांक 3 नवम्बर, 1976	—तदैव—	श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज (फोर्जिंग्स) प्रा० लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत।
	S.O. 706(E)/18E/IDRA/76, dated 3rd Nov. 1976.	-Do-	Take over of the management of M/s. Ancillary Industries (Forgings) Private Ltd., Calcutta by Shri M.K. Modwel.
	का० आ० 707 (अ)/18 ई०/आई०डी०आर०ए०/76 दिनांक 3 नवम्बर, 1976	—तदैव—	श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज (क्रेंक्स) प्रा० लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत।
	S.O. 707(E)/18E/IDRA/76, dated 3rd Nov. 1976	-Do-	Take over of the management of M/s. Ancillary Industries (Cranks) Private Limited, Calcutta by Shri M.K. Modwel
473.	का० आ० 708(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1976	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन श्री बलवन्त सिंह के मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के विषय में।
	S O. 708 (E), dated the 4th November, 1976.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Reference from the President under Section 8A(3) read with Section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951 regarding the case of Shri Balwant Singh.
474.	S.O. 709(E), dated the 5th November, 1976.	Ministry of Home Affairs	Corrigendum in S O 620(E), dated the 18th September, 1976.
475.	का०आ० 710(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	'ए' प्रमाणपत्र का प्रदर्शन इस अधिसूचना की 5-11-76 से 2 मास की अवधि में रोक दिया जाना।
	S.O. 710(E), dated the 5th November, 1976.	Ministry of Information and Broadcasting.	Suspension of 'A' certificate for a period of two months w.e.f. 5th Nov. 76.
476.	का०आ० 711(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 518 (ई), दिनांक 1 अगस्त, 1976 द्वारा नियुक्त जांच आयोग केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
	S.O. 711(E), dated 5th Nov 1976.	Ministry of Commerce	Appointment of Commission of Inquiry in the Ministry of Commerce (Dept. of Export Production) by Notification No. S. O. 518 (E) dated the 1st Aug 1976 shall submit its report to the Central Govt.
477.	का० आ० 712 (अ) (मो) आ०, 1968/ए०एम० (213), दिनांक 5 नवम्बर, 1976	—तदैव—	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करना।
	S.O. 712(E) (C) O, 1968. A.M. (213), dated 5th Nov 1976.	-Do-	Further amendment to the exports (Control) Order, 1968.
478.	का० आ० 713(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	गोआ शिपयार्ड लि० वास्को-डा-गामा औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को छ: मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 713(E), dated 5th Nov. 1976.	Ministry of Labour	Prohibition of any strike in connection with any industrial dispute in the Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama for a period of six months.

1	2	3	4
	का०आ० 714(अ), दिनांक 5 नवम्बर, 1976 S.O. 714(E), dated 5th Nov. 1976.	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour	गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डा-गामा, गोआ के लिए नियोजन लागू करना। Declaration of employment in Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama, Goa.
479	का०आ० 715(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 1976 S.O. 715(E) dated 10th Nov. 1976.	राजस्व और बैंकिंग विभाग Deptt of Revenue and Banking	मगध ग्रामीण बैंक बिहार राज्य के औरंगाबाद नवादा और गया जिलों में 10-11-76 से कारोबार करेगा। Operation of Magadh Gramin Bank in the district of Aurangabad, Nawada and Gaya in the State of Bihar w.e.f. 10-11-76.
	का०आ० 716(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 1976 S.O. 716(E), dated 10th Nov. 1976	—तदैव— -Do-	मगध ग्रामीण बैंक का मुख्यालय गया होगा। Magadh Gramin Bank shall have its Head Office at Gaya.
	का०आ० 717(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 1976 S.O 717(E), dated 10th Nov. 1976	—तदैव— -Do-	ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में मगध ग्रामीण बैंक अधिसूचित करना। Magadh Gramin Bank will be called as an institution under sub. sec.(1) of Sec. 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976.
	का० आ० 718(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 1976 S.O 718(E), dated 10th Nov 1976.	भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India	मगध ग्रामीण बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरी अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में समाविष्ट करना। Inclusion of Magadh Gramin Bank, Gaya in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.
480	का० आ० 719(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 1976 S.O. 719(E), dated 10th Nov. 1976	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय Min. of Education and Social Welfare.	केन्द्रीय सरकार द्वारा कापीराइट का पुनर्गठन करना। Reconstitution of Copyright Board by the Central Govt.
481.	का० आ० 720(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 1976 S.O. 720(E), dated 11th Nov. 1976	—तदैव— -Do-	श्री जी० राम चन्द्रन, सचिव को तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करना। Appointment of Sh. G. Rama Chandra, Secy., Min. of Fin. as member of the U.G. Comn.
482.	का० आ० 721(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1976 S.O. 721(E), dated 12th Nov. 1976	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Min. of Agricultural and Irrigation	केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के लिए सदस्य नियत करना। Consisting of members in the Central Seed Certificate Board by the Central Govt.
483	का० आ० 722(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1976 S.O. 722(E), dated 12th Nov. 1976	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes	दान कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976। Gift-Tax (Second Amendment) Rules, 1976.
484.	का० आ० 723 (अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1976 S.O. 723(E), dated 12th Nov. 1976.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Min. of Law, Justice and Company Affairs.	दिल्ली की स्टेट बार काउन्सिल के लिए 12-11-76 से अध्यक्ष निर्देशित करना। Nomination of Chairman of the State Bar Council of Delhi w.e.f. 12-11-76.
	का० आ० 724(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1976 S.O 724(E) dated 12th Nov 1976.	—तदैव— -Do-	भारतीय बार काउंसिल के लिए 12-11-76 से सदस्य नियुक्त करना। Appointment of member of the Bar Council of India w.e.f. 12-11-76.
485.	का० आ० 725(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 1976 S.O. 725(E), dated 12th Nov. 1976	राजभाषा विभाग Deptt of Official Language.	सर्वसाधारण के लिए राष्ट्रपति 11-11-76 से आदेश करना। Order made by the President of 11-11-76 for General Information.
486.	का० आ० 726(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1976 S.O. 726(E), dated 13th Nov. 1976	राजस्व और बैंकिंग विभाग Deptt of Revenue and Banking	कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक उड़ीसा राज्य के जिला कोरापुट में अपना कारोबार करेगा। Operation of Koraput-Panchabati Gramya Bank in the district of Koraput in the State of Orissa.

1	2	3	4
	का० आ० 727(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1976	राजस्व और बैंकिंग विभाग	कोरापुट जिले के जेपोर में कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।
	S.O 727(E), dated 13th Nov. 1976	Deptt. of Revenue and Banking	Koraput-Panchabati Gramya Bank have its Head Office at Joypore in the district of Koraput.
	का० आ० 728(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1976	—तदैव—	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करना।
	S.O. 728(E), dated 13th Nov. 1976.	-Do-	Koraput-Panchbati Gramya Bank will be called as an institution under Sub-Sec.(1) of Sec. 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976.
	का० आ० 729(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 1976	भारतीय रिजर्व बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर को समाविष्ट किया जाना।
	S.O. 729(E), dated 13th Nov. 1976.	Reserve Bank of India	Inclusion of Koraput-Panchbati Gramya Bank, Joypore in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.
	का० आ० 730(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करना।
487.	S.O. 730(E), dated 13th Nov. 1976.	Ministry of Labour.	Prohibition of any strike in connection of any Industrial dispute in Salem district of Tamil Nadu State under the Defence and Internal Security of India Rules, 1971.
	का० आ० 731(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1976	भारतीय निर्वाचन आयोग	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश करना।
488.	S.O. 731(E), dated 15th Nov. 1976.	Election Commission of India.	Order made by the Election Commission of India.
	का० आ० 732(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1976	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	धनकर (चौथा संशोधन) नियम, 1976।
489.	S.O. 732(E), dated 15th Nov. 1976.	Central Board of Direct Taxes.	Wealth-tax (fourth Amendment) Rules, 1976.
	का० आ० 733(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 35वां संशोधन आदेश 1976।
490.	S.O. 733(E), dated 15th Nov. 1976.	Ministry of Commerce	Exports (Control) 35th Amendment Order, 1976.
	का० आ० 734 (अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1976	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार, नवम्बर, 1976 के उन्नीसवें दिन को अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण अधिनियम, 1976 के प्रवीन नियत करना।
491.	S.O. 734(E), dated 16th Nov. 1976.	Min. of Home Affairs.	Central Govt. appoints 19th day of Nov., 1976 of enforcement of untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Act, 1976.
	का० आ० 735 (अ)/आई०डी० आर०ए०/29ख/75 दिनांक 16 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत धारा 10, 11, 11, क और 13 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन में छूट।
492.	S.O. 735(E)/IDRA/29B/75, dated 16th Nov. 1976.	Ministry of Industry.	Exemption of Sections 10, 11, 11A and 13 subject to certain conditions under Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
	का० आ० 736(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1976	—तदैव—	अधिसूचना सं० का० आ० 98(अ)/आई० डी० आर० ए०/29ख/73/1, 16 फरवरी, 1974 में औद्योगिक विकास (औद्योगिक विकास विभाग) में छूट।
493.	S.O. 736(E), dated 16th Nov. 1976.	-Do-	Further amendment of Notfn. No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 of 16-2-73 of Min. of Industrial Development (Deptt. of Industrial Development).
	का० आ० 737(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में फिल्मों की स्वीकृति।
494.	S.O. 737(E), dated 17th Nov. 1976.	Min. of Information and Broadcasting.	Approval of films specified in Col. 2 of the Schedule thereto.

1	2	3	4
	का० आ० 738(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 36वां संशोधन आदेश, 1976।
495.	S.O. 738(E) dated 17th Nov. 1976	Ministry of Commerce.	Exports (Control) 36th Amendment Order, 1976.
	का० आ० 739(अ)/18एफ०/आई० डी०आर०ए०/76, दिनांक 17 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की आदेश सं० का० आ० 13(अ), 3-1-74 में आगे संशोधन।
496.	S.O. 739(E)/18F/IDRA/76, dated 17th Nov. 1976.	Ministry of Industry.	Further amendment of Order No. S.O 13(E) of 3-1-74 of late Min. of Industrial Development
	का० आ० 740 (अ)/18 ए०/आई०डी०आर०ए०/76 दिनांक 17 नवम्बर, 1976	—तदैव—	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की आदेश सं० का० आ० 14(अ) 3-1-74 में संशोधन।
	S.O. 740(E)/18A/IDRA/76, dated 17th Nov. 1976.	-Do-	Amendment of Order No S.O. 14(E) of 3-1-74 of late Min. of Industrial Development.
	का० आ० 741(अ)/18 ए०/आई०डी०आर०ए०/76 दिनांक 17 नवम्बर, 1976	—तदैव—	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की आदेश सं० सामान्य 14(अ), 3-1-74 में और आगे संशोधन।
	S.O.741(E)/18A/IDRA/76, dated 17th Nov. 1976.	-Do-	Further amendment of Order No. S.O. 14(E) of 3-1-74 of late Min. of Industrial Development.
	का० आ० 742(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 1976	—तदैव—	श्री एस० एन० चट्टोपाध्याय ने मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी तथा मै० इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड से सम्बधित अभिरक्षक के पद कार्यभार 28-10-76 से श्री एन० आर० भार्गवा के लिए छोड़ दिया।
497.	S.O. 742(E) dated 18th Nov. 1976.	-Do-	Shri S. N. Chattopadhyay relinquished charge of the post of Custodian of M/s. Burn and Company Ltd. and M/s. Indian Standard Wagon Company Ltd. w.e.f. 28-10-76 in place of Sh. N.R. Bhargava.
	का० आ० 743(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 1976	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	आयना (हिन्दी), फिल्म को एक महीने के लिए 19-11-76 से निलम्बित करना।
498.	S.O. 743(E) dated 19th Nov. 1976.	Min. of Information & Broadcasting.	Suspension of film 'AAINA', (Hindi) for one month w.e.f. 19-11-76
	का० आ० 744(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 1976	—तदैव—	टटम्मा काला (तेलुगु) की फिल्म को दो माह के लिए 19-11-76 से निलम्बित करना।
499.	S.O. 744(E) dated 19th Nov. 1976.	-Do-	Suspension of film "Tatamma Kala" (Telugu) for two months w.e.f. 19-11-76.
	का० आ० 745(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	आयात (नियंत्रण) 10वां संशोधन आदेश, 1976।
500.	S.O. 745(E) dated 20th Nov. 1976.	Ministry of Commerce.	Imports (Control) 10th Amendment Order, 1976.
	का० आ० 746(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 1976	तदैव	ओकायती टी एस्टेट यूनिट के लिए पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करना।
501.	S.O. 746(E) dated 22nd Nov. 1976.	-Do-	Composition of a body of persons for full and complete investigation of Okayti Tea Estate unit.
	का० आ० 747(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 1976	—तदैव—	कुमाई टी स्टेट यूनिट के लिए पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के लिए व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करना।
	S.O. 747(E) dated 22nd Nov. 1976.	-Do-	Composition of a body of persons for full and complete investigation of Kumai Tea Estate Unit.
	का० आ० 748(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 1976	मंत्रिमण्डल सचिवालय	भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ अठारहवां संशोधन) नियम, 1976।
502.	S.O. 748(E) dated 22nd Nov. 1976.	Cabinet Secretariat.	Govt. of India (Allocation of Business) (118th Amendment) Rules, 1976.

1	2	3	4
	का० श्रा० 749(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	खुला सामान्य लाईसेंस सं० CIV
503.	S.O.749(E) dated 22nd Nov. 1976.	Ministry of Commerce.	Open General Licence No. CIV.
	का० श्रा० 750 (अ), दिनांक 23 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	तांबा (वैद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) संशोधन आदेश, 1976
504.	S.O. 750(E) dated 23rd Nov. 1976.	Ministry of Industry	Copper (Prohibition of use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Amendment Order, 1976.
	का० श्रा० 751(अ)/18 एफ०बी० आई०डी०आर०ए०/76, दिनांक 23 नवम्बर, 1976	-तदैव-	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) आदेश सं० का० श्रा० 726 (अ), दिनांक 27-11-72 में 2-11-77 तक में और आगे बढ़ाना।
505.	S.O.751(E)/18FB/IDRA/76. dated 23rd Nov. 1976.	-Do-	Further extension of late Min. of Indl. Development (Deptt. of Indl. Development) Order No. S.O. 726(E) of 27-11-72 upto 2-11-77.
	का० श्रा० 752(अ), दिनांक 24 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	मध्य प्रदेश की सभी कपड़ा मिलों में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करना।
506.	S.O. 752(E) dated 24th Nov. 1976.	Ministry of Labour.	Prohibition of any strike or lock-out in connection with any industrial dispute in all Textile Mills in the State of Madhya Pradesh for a period of six months with immeditate effect.
	का० श्रा० 753(ई)18 ए०ए०/आई०डी०आर०ए०/76, दिनांक 25 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव के उपक्रम का प्रबन्ध महाराष्ट्र स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड को निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना।
507.	S.O. 753(E)/18AA/IDRA/76 dated 25th Nov. 1976.	Ministry of Industry.	Central Govt. authorises Maharashtra State Textile Corporation Ltd. to take up M/s. Pulgaon Cotton Mill Ltd., Pulgaon on certain conditions.
	का० श्रा० 754(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम 1971, के अधीन रेल सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करना।
508.	S.O. 754(E) dated 26th Nov. 1976.	Ministry of Labour	Prohibition of any strike in connection with any Industrial Dispute in the Railway Services in India under Defence and Internal Security India Rules, 1971.
	का० श्रा० 755(अ)/आई०डी०आर०ए०/10, दिनांक 26 नवम्बर, 1976	उद्योग मंत्रालय	अनुसूची में वर्णित उपक्रमों को निर्दिष्ट करना।
509.	S.O. 755(E)/IDRA/10, dated 26th Nov. 1976.	Ministry of Industry.	Specification of class of undertakings mentioned in the Schedule thereto.
	का० श्रा० 756 (अ), दिनांक 27 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय] तामिलनाडु राज्य में प्रवृत्त होगा।
510.	S.O. 756(E) dated 27th Nov. 1976.	Ministry of Labour.	Enforcement of Chapter IV (except Secs. 44 and 45) and Chapter V and VI [except Sub-Sec.(1) of Sec. 76 and Sections 77, 78, 79 and 81] of Employees' State Insurance Act, 1948 w.e.f. 28-11-76 in the State of Tamil Nadu.
	का० श्रा० 757(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 1976	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में अधिसूचना का० श्रा० सं० 61 (अ) और यथा संशोधित अधि० सं० 56/75-I 31-1-75 में संशोधन।
511.	S.O. 757(E) dated 30th Nov. 1976.	Election Commission of India.	Amendment to Notfn. No. S. O. 61(E)/56/75-I of 31-1-75 of Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.
	का० श्रा० 758(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	न्यासी बोर्ड द्वारा, भविष्य निधि संचयनों, अभिदायों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को वाद्य कर निर्गमों के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के अन्तर्गत विनिहित करना।
512.	S.O. 758(E) dated 30th Nov. 1976.	Ministry of Labour.	Accumulation of contributions, interest and other receipts of employees under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 by the Board of Trustees.

1	2	3	4
	का० आ० 759 (अ), दिनांक 30 नवम्बर, 1976	श्रम मंत्रालय	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के अंश में निधि की राशियों के नमूने विनिहित करना।
	S.O. 759(E), dated 30th Nov., 1976	Ministry of Labour	Patterns of investment of monies of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952
	का० आ० 760(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 1976	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित विषय के बारे में जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना।
513.	S.O. 760(E), dated 30th Nov. 1976.	Min of Health and Family Planning.	Appointment of a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public-importance.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

ENFORCEMENT DIRECTORATE

(FOREIGN EXCHANGE REGULATION

New Delhi, the 18th December, 1976

CORRIGENDUM

S.O. 139.—In this Department Notification dated 1st June, 1976 Published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26th June, 1976, the following corrections shall be carried out :—

At page 2133, Part (B) at Sl. No. 3, Col. 2, read "C/o Shri Sanib Maricar" for "C/o Shri Sabhib Maricar".

" " " " " " " " " read "Malaysia" for "Malasia".

" " 2134, " line 1 of the preamble after word "any other officer of enforcement" add "authorised".

" " 2143 at Sl. No. 10, Col. 2, read "44, Ezro Street, Calicut" for "44, Ezra St. Calcutta".

" " " " " 12, the name of the Party should be read as "A.G. Cherian" in place of "A.H. Cherian".

" " 2144 in the heading of Table read "7-2-73 to 6-5-73" for "2-7-73 to 6-5-73".

" " 2147 at Sl. No. 3, Col. 4 read "Rs. 4000/-" for "Rs. 10,000/-".

" " " " " " 5 " read "Rs. 15,000/-" for "Rs. 15,10,000/-".

" " " " " " 11 " 2 read "Ludhiana" for "Ludhiara".

" " 2150 " " " 4 " 2 read "M. Ringwala" for "Mringwala".

" " 2151 " " " 21 " 4 read "Rs. 1000/-" for "Rs. 10,000/-".

" " " " " " 26 " 5 read "US $ 2445" for "U. S.S./2, 445/-"

[No. T-19/31-Coord/75]

R. N. CHOPRA, Asstt. Director

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1976

का० आ० 140—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कमार हट्टी कम्पनी लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 119/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 22/35/72-एम० 2]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 28th December, 1976

S.O. 140.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Kamarhatty Company Ltd., under the said Act (Certificate of Registration No. 119/70).

[No. 22/35/72-M. II]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1976

का० आ० 141—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स साउथ इन्डिया स्टील एंड शुगर्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1081/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 2/48/75-एम० 2]

New Delhi, the 29th December, 1976

S.O. 141.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notified the cancellation of the Registration of M/s. South India Steel and Surags Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 1081/75).

[No. 2/48/75-MII]

का० आ० 142—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3)

के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव ब्यूरो लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1089/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 2/29/75-एम० 2]

S.O. 142:—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. The Security and Detective Bureau Ltd. under the said Act (Certificate of Registration No. 1089/75).

[No. 2/29/75-M. II]

का० आ० 143:—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दी डानमिल कम्पनी लिमिटेड का कथित धारा के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र संख्या 641/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 9/566/70-एम० 2]

एम० सी० वर्मा, उप सचिव

S.O. 143.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. The Dawn Mills Company Limited, under the said Act (Certificate of Registration No. 641/70).

[No. 9/566/70-M. II]

M. C. VARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

आयकर आयुक्त कार्यालय, विदर्भ एवम् मराठवाडा, नागपुर ;

नागपुर, 15 नवम्बर, 1976

का० आ० 141 —चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय में यह लोक हित में आवश्यक और जरूरी है कि उन व्यतिक्रमी करदाताओं के नाम और पते प्रकाशित किए जाएं जिनका उल्लेख इसके आगे व्यतिक्रमी करदाताओं के रूप में किया गया है और जिन्होंने 31 मार्च, 1976 तक 9 मास से अधिक समय से 25,000/- या उससे अधिक आयकर जमा नहीं किया है।

2 और चूंकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 में प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी सभी अन्य शक्तियों से, जो इस बारे में सरकार को समर्थ करती है, केन्द्रीय सरकार ने अपने तारीख 9-6-1969 के आदेश सं० 1/1/69-आई० टी० (बी०) के द्वारा सभी आयकर आयुक्तों को इस बात का प्राधिकार और निर्देश दिया है कि वे ऐसे व्यतिक्रमी कर दाताओं के नाम और पते प्रकाशित करें।

3 अत मैं, आयकर आयुक्त, विदर्भ एवं मराठवाडा नागपुर, एतद्द्वारा अब विदर्भ एवम् मराठवाडा, प्रभार के 31 मार्च, 1976 तक वित्तीय वर्ष 1975-76 में सम्बन्धित वर्ष के व्यतिक्रमी करदाताओं के नाम तथा पते प्रकाशित कर रहा हूं।

(i) भाग 'क' के लिए है ·	कर-रकम जो 9 मास से लेकर एक वर्ष 3 मास तक की अवधि से जमा नहीं कराई गई है।
(ii) भाग 'ख' के लिए है .	कर-रकम जो एक वर्ष 3 मास से लेकर 2 वर्ष 3 मास तक की अवधि से जमा नहीं कराई गई है।
(iii) भाग 'ग' के लिए है ·	कर-रकम जो 2 वर्ष 3 मास से अधिक समय से जमा नहीं कराई गई है।

(iv) सारी रकम जमा न कराने के लिए।

1. श्री ए० एम० शेशिन, वर्धा (3) 1612418 और (4) 1612118

2 मैसर्स अबाजी ट्रेडर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (1) 405327 और (4) 405327

3 श्री भावसभाई, नागपुर (1) 7000 (2) 38000 (3) 84000 और (4) 129000

4 श्री ए० ए० हाजी, अमरावती (3) 30072 और (4) 30072

5 मैसर्स अविरी णाप, नागपुर (3) 149191 और (4) 149191

6 श्री बनवारी लाल लोहया (हि० अ० प०), कामठी (1). 11133 (2) 21572 (3) 997882 और (4) 1030587

7 मैसर्स बिडी एनाईट एंड टोबाको प्रोडक्टस (प्रा०) लि०, कामठी (1) 2000 (2) 60000 (3) 6000 और (4) 68000

8 श्री मोहिराज तेजमल सचेती, मलकापुर (2) 37940 और (4) 37940

9. श्री भगीरथ प्रसाद कानूराम, परभणी (2) 75150 और (4) 75150

10. मैसर्स बलराम मोलूराम (हि० अ० प०), तुमसर (3) 1817641 और (4) 1817641

11. मैसर्स भारत मार्शनिग एंड ट्रेडिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, विशाखा-पत्तनम (3) 35547 और (4) 35547

12 मैसर्स बगमल प्रल्हादराय बोलेश्वर, अकोला (3) 446050 और (4) 446050

13. श्री चन्द्रकान्त मोर (हि० अ० प०), तुमसर (1) 15000 (2) 358000 (3) 1274000 और (4) 1647000

14. कप्टन बादली शमशेरजंग बहादुर राणा द्वारा एजेंट मैसर्स आर० बी० श्रीराम एंड कम्पनी (प्रा०) लि०, विशाखापटनम् (3) 56761 और (4) 56761

15 मैसर्स डिलर्स एंड कम्पनी (प्रा०) लि०, जयपुर (2) 60120 (3) 2196180 और (4) 2258300

16 श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर (3) 574618 और (4) 574618

17 मैसर्स दुर्गाप्रसाद श्रीराम (हि० अ० प०), तुमसर (3) 1020789 और (4) 1020789

18 श्री फकरुद्दीन मो० अली, नागपुर (3) 406000 और (4) 406000

19 स्व० श्री फतेचन्द मोर, द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री राम-नारायण मोर, तुमसर (2) 296000 (3) 172900, और (4) 2025000

20. मैसर्स गुरुघाट, माइन्स, तुमसर (3) 1614392 और (4) 1614392

21 मैसर्स गोवर्धन दास गोपिकिशन (पं० फ०), गोंदिया (3) 470822 और (4) 478022

22. श्री घासिलाल सुखलाल जयपुरिया (हि० अ० प०), तुमसर (3) 108227 और (4) 108227

23. श्री गुलाबदास रामबिलास अगरवाल, नागपुर (3) 790655 और (4) 790655

24. स्व० श्री हातिमभाई, द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री माबीर हुसैन, नागपुर (1) 6000 (2) 38000 (3) 89000 और (4) 123000

25. मैसर्स जयपुरिया ब्रदर्स, तुमसर (3) 1621379 और (4) 1624379

26. श्री जयनारायण नन्दकिशोर, द्वारा एजेन्ट मेसर्स आर० पी० श्रीराम एंड कम्पनी (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम (3) 31464 और (4) 31464

27. मैसर्स जानकी जनरल स्टोर्स (पं० फ०), नागपुर (3) 35967 और (4) 35967

28 मैसर्स के० एम० एम० हमनजी एंड सन्स (प० फ०) नागपुर (1) 3000 (2) 102000 और (4) 105000

29. मैसर्स के० मूसा मोह० (अपं० फ), अन्सारी वार्ड, गोंदिया (3) 80622 और (4) 80622

30. श्रीमती कृष्णादेवी लोईया, कामठी (3) 72000 और (4) 72000

31. डा० कचुमल जेठानन्द, नागपुर (2) 75617 (3) 45189 और (4) 120806

32 मैसर्स लोईया ब्रदर्स (पं० फ०), कामठी (1) 12000 (2) 9000 (3) 76000 और (4) 97000

33. मैसर्स लक्ष्मी लाइम फैक्टरी (अपं० फ०), राजूर (3) 117168 और (4) 117168

34. श्री मदन मोहन जयपुरिया, तुमसर (3) 87093 और (4) 87093

35. श्री मोहम्मिन अली फजल हुसैन, भोपाल (3) 37513 और (4) 37513

36. श्री मंतपे डी० डब्ल्यू०, नागपुर (3) 62842 और (4) 62842

37. मैसर्स निजामाबाद बिडी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, कामठी (1) 9000 (2) 79000 (3) 360000 और (4) 448000

38. मैसर्स नागपुर ग्लास वर्क्स लिमिटेड, नागपुर (2) 20282 (3) 57742 और (4) 78024

39. स्व० श्री नरसिंगदास मोर, द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री चन्द्र कान्त मोर, तुमसर (2) 6000 (3) 3114000 और (4) 3120000

40. श्री नारायणदास पुरणलाल माहोटी (हि० अ० प०), लातूर (3) 58767 और (4) 58767

41 नागपुर आरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन लि०, नागपुर (3) 167790 और (4) 167790

42 नागपुर विशाल ग्राहक सहकारी संस्था लि , नागपुर (3) 133877 और (4) 133877

43. श्रीमती निर्मलाबाई सोलंब, नागपुर (3) 97796 और (4) 97796

44. श्री प्रल्हाद रामगोपाल खोनेश्वर, अकोला (3) 159016 और (4) 159016

45. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (हि० अ० प०), तुमसर (1) 153716 (2) 878636 (3) 616773 और (4) 1649125

46. मेसर्स आर० पी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद एंड फतेचन्द नरसिंगदास (एक्स-पोर्ट) फर्म, तुमसर (1) 812705 (3) 383205 और 1195910

47. श्री रामेश्वरदास रामदास, जयपुर (1) 2690 (3) 707323 और (4) 740013

48 मेसर्स रामकृष्णा रामनाथ अगरवाल (प्रा०) लि०, नागपुर (1) 3774 (2) 61353 (3) 1096583 और (4) 1161610

49 मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ (बिडी) प्रा० लि०, नागपुर (1) 1800 (2) 33282 (3) 757323 और (4) 792405

50. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ एंड सन्स (अ० फ०), कामठी (1) 5000 (2) 34000 (3) 494000 और (4) 533000

53. मैसर्स रामाकृष्णा रामनाथ (हि० अ० प०), कामठी (1) 71300 (2) 1416987 (3) 226145 और (4) 1714432

57 श्री रमाकांत लोईया (हि० अ० प०), कामठी (1) 24000 (2) 3000 (3) 943000 और (4) 970000

53 मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्रा०) लि०, तुमसर (3) 26876087 और (4) 26876087

54 मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ लोईया एंड सन्स, कामठी (1) 582000 (2) 278000 (3) 945000 और (4) 1805000

55. श्री रामनारायण मोर (हि० अ० प०), तुमसर (1) 30000 (2) 489000 (3) 2066000 और (4) 2585000

56. श्री राधाकिशन लोईया (हि० अ० प०), कामठी (2) 16000 (3) 1548000 और (4) 1664000

57. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ (प० फ०), कामठी (2) 16000 (3) 243000 और (4) 2449000

58. श्री रामेशचन्द्र लोईया, कामठी (3) 101000 और (4) 101000

59. मैसर्स रामबिलास मुरलीधर एंड बलराम तोलूराम (पं० फ०), तुमसर (3) 154472 और (4) 154472

60. मैसर्स आर० एस० गोपीकिशन, अगरवाल (शिपर्स) प्रा० लि०, तुमसर (3) 1517549 और (4) 1517549

61. श्री आर० एस० जी० एल० जयपुरिया, तुमसर (3) 85367 और (4) 85367

62. श्री रामकुमार रामगोपाल बोहरा, द्वारा एजेन्ट मेसर्स आर० पी० श्रीराम एंड कम्पनी (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम (3) 242057 और (4) 242057

63. मैसर्स रामबिलास गुलाबदास (हि० अ० प०), तुमसर (3) 3577337 और (4) 3577337

64. श्री राजीव गोर, तुमसर (3) 51452 और (4) 52452

65. मैसर्स रामचन्द्र रामरतन (अपं० फ०), अमरावती (3) 51560 और (4) 51560

66. श्री आर० एम० लाधा (व्य०) अमरावती, (3) 44196 और (4) 44196

67. स्व० श्रीमती सुगनीदेवी सराफ द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर (1) 35845 (2) 313275 (3) 799559 और (4) 1138679

68. श्री श्रीकांत मोर, तुमसर (1) 13000 (2) 6000 (3) 63000 और (4) 72000

69. मसर्स सुवर्णा ट्रांसपोर्ट कं० (प्रा० लि०), बुलढाणा (समापनाधीन) (3) 96999 और (4) 96999

70. श्रीमती सुधादेवी लोईया, कामठी (3) 35000 और (4) 35000

71. श्री सन्तोषकुमार अगरवाल, तुमसर (3) 328102 और (4) 328102

72. स्व० श्रीराम दुलाराय, द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर (3) 575520 और (4) 575520

73. श्री उमाशंकर लोईया (हि० अ० प०), कामठी (1) 41000 (2) 92000 (3) 107000 और (4) 240000

74. मेसर्स उमाशंकर दुर्गाप्रसाद सराफ (हि० अ० प०), तुमसर (3) 777636 और (4) 777636

75. मेसर्स बिट्ठलदास दुर्गाप्रसाद सराफ (हि० अ० प०), काठमांडू, नेपाल (3) 753716 और (4) 753716

76. श्री ही जी० कोल्हटकर, नागपुर (3) 38152 और (4) 38152

[फा० सं० वसूली (64)/76-77]

के० एन० अनन्तराम अय्यर, आयुक्त,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, VIDARBHA AND MARATHWADA, NAGPUR

Nagpur, the 15th November, 1976

S.O. 144.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and address hereinafter specified relating to tax defaulters who were in default of payment of income-tax of Rs. 25,000 and above for the periods exceeding 9 months as on 31-3-1976.

2. And whereas in exercise of the powers conferred by Section 237 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government by its order F. No. 1/1/69-II(D) dated the 9th June, 1969 hereby authorised and directed to all commissioners of Income-tax to publish the names and addresses of such tax defaulters.

3. Now, therefore I, Commissioner of Income-tax, Vidarbha and Marathwada Nagpur hereby publish the names and addresses of the tax defaulters in Vidarbha and Marathwada Charge as on 31-3-1976 relating to financial year 1975-76.

(i) is for Part 'A'.—Amount in default for periods exceeding 9 months but not exceeding 1 year and 3 months.

(ii) is for Part 'B'.—Amount in default for period of 1 year and 3 months and above but not exceeding 2 years and 3 months.

(iii) is for Part 'C'.—Amount in default for periods of 2 years 3 months and above.

(iv) is for total amount in default.

1. Shri A. S. Dixit, Wardha (ii) 1612418 and (iv) 1612418.

2. M/s. Ambaji Traders (P) Ltd., Calcutta (i) 405327 and (iv) 405327.

3. Shri Adambhai, Nagpur (I) 7000 (ii) 38000 (iii) 84000 and (iv) 129000.

4 Shri A. A. Haji, Amraoti (iii) 30072 and (iv) 30072.

5. M/s. Abidi Shop, Nagpur (iii) 14191 and (iv) 149191.

6. Shri Banwarilal Loiya (HUF), Kamptee (i) 11133 (ii) 21572 (iii) 997882 and (iv) 1030587.

7. M/s. Bidi Allied & Tobacco Products (P) Ltd., Kamptee (i) 2000 (ii) 60000 (iii) 6000 and (iv) 68000.

8. Shri Bhioraj Tejmal Sancheti, Malkapur (ii) 37940 and (v) 37940.

9. Shri Bhagirath Prasad Kaluram, Prabhani (ii) 75150 and (iv) 75150.

10. M/s. Balaram Toluram (HUF), Tumsar (iii) 1817641 and (iv) 1817641.

11. M/s. Bharat Mining & Trading Co. (P) Ltd., Visakhapatnam (iii) 35547 and (iv) 35547.

12. M/s. Bagmal Pralhadrai Kholeshwar, Akola (iii) 446050 and (iv) 446050.

13. Shri Chandrakant Mor (HUF), Tumsar (i) 1500 (ii) 358000 (iii) 127400 and (iv) 1647000.

14. Capt. Dadli Shamsherjang Bahadur Rana through Agent M/s. R. B. Shreeram & Co. (P) Ltd., Visakhapatnam (iii) 56761 and (iv) 56761.

15. M/s. Dealers & Co. (P) Ltd., Jaipur (ii) 60120 (iii) 2196180 and (iv) 2256300.

16. Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar (iii) 574618 and (iv) 574618.

17. M/s. Durgaprasad Shreeram (HUF), Tumsar (iii) 1020789 and (iv) 1020789.

18. Shri Fakruddin Mohd. Ali, Nagpur (iii) 406000 and (iv) 406000.

19. Late Shri Fatechand Mor, through L/H Shri Ramnarayan Mor, Tumsar (ii) 296000 (iii) 1729000 and (iv) 2025000.

20. M/s. Gudrughat Mines, Tumsar (iii) 1614392 and (iv) 1614392.

21. M/s. Gowardhandas Gopikisan (R.F.), Gondia (iii) 470822 and (iv) 470822.

22. Shri Ghasilal Suwalal Jaipuria (HUF), Tumsar (iii) 108227 and (iv) 108277.

23. Shri Gulabdas Rambilas Agarwal, Nagpur (iii) 790655 and (iv) 790655.

24. Late Shri Hatimbhai, through L/H Shri Sabhir Hussain, Nagpur (i) 6000 (ii) 38000 (iii) 79000 and (iv) 123000.

25. M/s. Jaipuria Brothers, Tumsar (iii) 162479 and (iv) 1624379.

26. Shri Jainarayan Nandkishore, through Agent M/s. R. B. Shreeram & Co. (P) Ltd., Visakhapatnam (iii) 31464 and (iv) 31464.

27. M/s. Janki General Stores (R. F.), Nagpur (iii) 35967 and (iv) 35967.

28. M/s. K.S.M. Hasonjee & Sons (RF), Nagpur (I) 3000 (iii) 102000 and (iv) 105000.

29. M/s. K. Moosa Mohd. (URF), Ansari Ward, Gondia (iii) 80622 and (iv) 80622.

30. Smt. Krishnadevi Loiya, Kamptee (iii) 72000 and (iv) 72000.

31. Dr. Kachumal Jethanand, Nagpur (iii) 75617 (iii) 45189 and (iv) 120806.

32. M/s. Loiya Brothers (RF), Kamptee (i) 12000 (ii) 9000 (iii) 76000 and (iv) 97000.

33. M/s. Laxmi Lime Factory (URF), Rajur (iii) 117168 and (iv) 117168.

34. Shri Madan Mohan Jaipuria, Tumsar (iii) 87093 and (iv) 87093.

35 Shri Mohsin Ali Fazal Hussain, Bhopal (iii) 37513 and (iv) 37513.

36. Shri Mandpe D. W., Nagpur (iii) 62842 and (iv) 62842.

37. M/s. Nizamabad Bidi Mfg. Co. (P) Ltd., Kamptee (i) 9000 (ii) 790000 (iii) 360000 and (iv) 448000.

38. M/s. Nagpur Glass Works Ltd., Nagpur (ii) 20282 (iii) 57742 and (iv) 78024.

39. Late Shri Narsinghdas Mor, through L/H Shri Chandrakant Mor, Tumsar (ii) 6000 (iii) 3114000 and (iv) 3120000.

40. Shri Narayanlal Puranlal Lahoti (HUF), Latur (iii) 58767 and (iv) 58767.

41. Nagpur Orange Growers Association Ltd., Nagpur (iii) 167790 and (iv) 167790.

42. Nagpur Vishal Grahak Sahakari Sanstha Ltd., Nagpur (iii) 133877 and (iv) 133877.

43. Smt. Nirmalabai Solao, Nagpur (iii) 97796 and (iv) 97796.

44. Shri Pralhad Ramgopal Kholeshwar, Akola (iii) 159016 and (iv) 159016.

45. M/s. R. B. Shreeram Durgaprasad (HUF), Tumsar (i) 153716 (ii) 878636 (iii) 616773 and (iv) 1649125.

46. M/s. R. B. Shreeram Durgaprasad & Fatehchand Narsinghdas (Export) Firm, Tumsar (i) 812705 (iii) 383205 and (iv) 1195910.

47. Shri Rameshwardas Ramdas, Jaipur (i) 32690 (iii) 707323 and (iv) 740013.

48. M/s. Ramkrishna Ramnath Agarwal (P) Ltd., Nagpur (i) 3774 (ii) 61253 (iii) 1096583 and (iv) 1161610.

49. M/s. Ramkrishna Ramnath (Bidi) Pvt. Ltd., Nagpur (i) 1800 (ii) 33282 (iii) 757323 and (iv) 792405.

50. M/s. Ramkrishna Ramnath & Sons (URF), Kamptee (i) 5000 (ii) 34000 (iii) 494000 and (iv) 533000.

51. M/s. Ramkrishna Ramnath (HUF), Kamptee (i) 71300 (ii) 1416987 (iii) 226145 and (iv) 1714432.

52. Shri Ramakant Loiya (HUF), Kamptee (i) 24000 (ii) 3000 (iii) 943000 and (iv) 970000.

53. M/s. R. B. Shreeram Durgaprasad (P) Ltd., Tumsar (iii) 26876087 and (iv) 26876087.

54. M/s. Ramkrishna Ramnath Loiya & Sons, Kamptee (i) 582000 (ii) 278000 (iii) 945000 and (iv) 1805000.

55. Shri Ramnarayan Mor (HUF), Humsar (i) 30000 (ii) 489000 (iii) 2066000 and (iv) 2585000.

56. Shri Radhakisan Loiya (HUF), Kamptee (ii) 16000 (iii) 1548000 and (iv) 1564000.

57. M/s. Ramkrishna Ramnath (RF), Kamptee (ii) 16000 (iii) 2449000 and (iv) 2449000.

58. Shri Rameshchandra Loiya, Kamptee (iii) 101000 and (iv) 101000.

59. M/s. Rambilas Murlidhar & Balaram Toluram (RF), Tumsar (iii) 154472 and (iv) 154472.

60. M/s. R. S. Gopikisan Agarwal (Shippers) Pvt. Ltd., Tumsar (iii) 1517549 and (iv) 1517549.

61. Shri R.S.G.L. Jaipuria, Tumsar (iii) 85367 and (iv) 85367.

62. Shri Ramkumar Ramgopal Bohara, through Agent M/s. R. B. Shreeram & Co. (P) Ltd., Visakhapatnam (iii) 242057 and (iv) 242057.

63. M/s. Rambilas Gulabdas (HUF), Tumsar (iii) 3577337 and (iv) 3577337.

64. Shri Rajiv Ishwardas Mor, Tumsar (iii) 51452 and (iv) 51452.

65. M/s. Ramchandra Ramratan (URF), Amravati (iii) 51560 and (iv) 51560.

66. Shri R. M. Ladha (indl), Amravati (iii) 44196 and (iv) 44196.

67. Late Smt. Sugnidevi Saraf, through L/H Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar (i) 25845 (ii) 313275 (iii) 799559 and (iv) 1138679.

68. Shri Shrikant Mor, Tumsar (i) 13000 (ii) 6000 (iii) 63000 and (iv) 82000.

69. M/s. Suwarna Transport Co. (P) Ltd., Buldhana (in liquidation) (iii) 96999 and (iv) 96999.

70. Smt. Sudhadevi Loiya, Kamptee (iii) 35000 and (iv) 35000.

71. Shri Santoshkumar Agarwal, Tumsar (iii) 328102 and (iv) 328102.

72. Late Shreeram Daularam, through L/H Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar (iii) 575520 and (iv) 575520.

73. Shri Umashankar Loiya (HUF), Kamptee (i) 41000 (ii) 92000 (iii) 107000 and (iv) 240000.

74. M/s. Umashankar Durgaprasad Saraf (HUF), Tumsar (iii) 777636 and (iv) 777636.

75. M/s. Vithaldas Durgaprasad Saraf (HUF), Kathamandu (Nepal) (iii) 753716 and (iv) 753716.

76. Shri V. G. Kolhatkar, Nagpur (iii) 38152 and (iv) 38152.

[F. No. Recy(64)/76-77]

K. N. ANANTHARAMA AYYAR, Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात, का कार्यालय, मद्रास

आदेश

मद्रास 19 अक्टूबर, 1976

रद्द करने का आदेश

का० आ० 145.—मुस्थापित आयतकों की श्रेणी के अन्तर्गत सर्वश्री मिश्रीमल अमलाजी, नं० 6, कासी चेट्टी लेन (ऊपरी मंजिल) मद्रास-1 को निम्नलिखित तीन लाइसेंस जारी किए गए थे :—

लाइसेंस का विवरण:—

1 पुस्तकें तथा पत्रिकाओं के लिए 1490/- रुपए के लिए लाइसेंस स० पी०/ई०/0244585/सी०/एक्स एक्स/58/एम०/41-42, दिनांक 6-3-76

2. गर्भ निरोधक रबड़ के लिए 2116/-रुपए के लिए लाइसेंस स० पी०/ई/0244586/सी०एक्स एक्स/58/एम/41-42, दिनांक 6-3-76

3. घड़ियों के पुर्जों के लिए 1250/- रुपए के लिए लाइसेंस स० पी०/ई०/0244587/सी०एक्स एक्स/58/एम०/41-42, दिनांक 6-3-76

उन्होंने उक्त लाइसेंसों की सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंसों की सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां उन्होंने प्राप्त नहीं की है क्योंकि डाकखाना प्राधिकारियों द्वारा वे किसी अन्य व्यक्ति को बांट दी गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि पूर्वोक्त लाइसेंसों की सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है तथा आवेदक को इन लाइसेंसों की सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

पूर्वोक्त तीन लाइसेंसों की मूल सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद् द्वारा रद्द की जाती हैं।

[फाइल स० आई० टी० सी०/23672/एम० आई० एम० सी०/डी यू पी सी आ० पी० वाई/76-77]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

Madras, the 19th October, 1976

S.O. 145.—M/s. Sha Misrimal Aslaji, No. 6, Kasi Chetty Lane (upstairs) Madras-1, were granted the following three licences under Estd. Importers Category.

LICENCE PARTICULARS

1. P/E/0244585/C/XX/58/M/41-42 dated 6-3-1976 for Rs. 1490 for Books and Periodicals.
2. P/E/0244586/C/XX/58/M/41-42 dated 6-3-1976 for Rs. 2116 for Rubber Contraceptives.
3. P/E/0244587/C/XX/58/M/41-42 dated 6-3-1976 for Rs. 1250 for Parts of Watches.

They have applied for duplicate of Customs and Exchange Control copies of the licences on the ground that the original Customs copy/Exchange Control copy of the above licences have not been received by them as the postal authorities have delivered them to a wrong person.

In support of their contention the applicants have filed an affidavit. I am satisfied that the original customs/exchange control purposes copies of licences mentioned above have been lost and that the duplicate Customs/Exchange Control Purposes copy of the licences should be issued to the applicant.

The original Customs/Exchange Control purposes Copies of the above three licences are hereby cancelled.

[File No. JTC/23672/Misc./Dup. copy/76-77]

आदेश

मद्रास, 22 नवम्बर, 1976

का० आ० 146 .—सर्वश्री सिंह ट्रेडिंग कम्पनी, मैनुफैक्चरिंग डिवीजन, 1-9, डा० विक्रम साराभाई इन्सट्रोनिक इस्टेट, अडयार, मद्रास-600020 को अप्रैल मार्च 76 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति वा० 1 के परिशिष्ट 38 के अन्तर्गत पैरा 16 में यथा अनुमेय अप्रैल-मार्च 1976 की अवधि के लिए 98,865.00 रुपए के संघटकों/माल के आयात के लिए आयात ला० सं० पी०/एस/1823319/सी०/एक्स एक्स/58/एम०/41-42 दि० 17-2-76 प्रदान किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त ला० की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि ला० की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति उक्त लाइसेंस के मद्दे 18,710.00 रुपए की सीमा तक आंशिक उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

यह सन्तुष्टि होने के बाद कि ला० स० पी०/एस०/1823319/सी/एक्स/एक्स/58/एम०/41-42 दि० 17-2-76 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है, यह निश्चय किया गया है कि फर्म को 80,155.00 रुपए की सीमा तक बचे हुए मूल्य का उपयोग करने के लिए अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाए।

ला० सं० पी०/एस०/1823319/सी०एक्स एक्स/58/एम०/41-42 दि० 17-2-76 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को अप्रयुक्त मूल्य की सीमा तक एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

[मिसिल सं० इलिक्ट 112/ए० एम०/76एस०एस० आई०-2से जारी]

आर० कुमारवेलु, उप मुख्य नियंत्रक, कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

ORDER

Madras, the 22nd November, 1976

S.O. 146.—M/s. Singh Trading Company, Manufacturing Division, 1—9, Dr. Vikram Sarabhai Instronic Estate, Adyar, Madras-600020 were granted Import Licence No. P/S/1823319/C/XX/58/M/41-42 dated 17-2-1976 for Rs. 98,865 for the period April-March 1976 for import of the Components/Materials as allowed in para 16 under Appendix 38 of the ITC Policy for April-March 76—Volume I.

The firm have applied for issue of Duplicate copy of the Customs copy of the above licence on the ground that the original customs copy of the licence has been lost/misplaced after having been partially utilised to the extent of Rs. 18,710 against the said licence. In support of their contention, the firm have filed an affidavit.

Having been satisfied that the Customs copy of the original licence No. P/S/1823319/C/XX/58/M/41-42 dated 17-2-76 has been lost/misplaced, it has been decided to issue duplicate licence to the firm to utilise the balance value to the extent of Rs. 80,155.

The original Customs copy of the Licence No. P/S/1823319/C/XX/58/M/41-42 dated 17-2-1976 is hereby cancelled to the extent of the unutilised value.

[File No. Elect/112/AM 76/SSI-2]

R. KUMARAVELU,
Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1976

का० आ० 147:—सर्वश्री मन्शाहन जनरल इंडस्ट्रीज मार्डन इंडस्ट्रियल इस्टेट बहादुर गढ़ को यू० के० से 38445 रुपए (अड़तीस हजार चार सौ पैतालीस रुपए मात्र) के लिए प्रयोगशाला और रीजेन्ट रसायन, क्रोमाइन तथा फिल्टर कागज का आयात करने के लिए लाइसेंस सं० पी/एम०/1821835/आर० एम० एल/55/डी०/41-42 दिनांक 30-6-75 प्रदान किया गया था।

2. पार्टी ने यह बताया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उस को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। पार्टी ने अप्रयुक्त मूल्य अर्थात 38445/- रुपए (अड़तीस हजार चार सौ पैंतालीस मात्र) के लिए उपर्युक्त मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुरोध किया है। पार्टी ने उक्त बयान के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रिया विधि पुस्तक 1976-77 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 की धारा 9 (सी० सी०) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस की उपर्युक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो को रद्द करने का आदेश देता हूं।

आवेदक को अब नियम एवं क्रिया विधि पुस्तक 1976-77 के पैरा 320 (4) की व्यवस्थाओं के अनुसार यू० के० के लिए 38445 (अड़तीस हजार चार सौ पैतालीस रुपए मात्र) के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या एम/एस/4/ए एम०-70/एयू एच एल/सी एल ए०]

के० आर० धीर, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य, नियंत्रक

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports (Central) Licensing Area

ORDER

New Delhi, the 27th December, 1976

S.O. 147.—M/s. Sunshine General Industries, Modern industrial Estate Bahadurgarh were granted licence No. P/S/1821835/R/ML/55/D/41-42 dated 30-6-75 for Rs. 38445 (Rs. Thirty eight thousand four hundred and forty five only) on UK for import of Laboratory and Reagent Chemicals Bromine and Filter Paper.

2. The party have intimated that the exchange control copy of the above said licence has been been lost/misplaced after having been utilised for a value of Rs. Nil and have requested for cancellation thereof. Party have also requested to issue duplicate Exchange Control copy of the same for the unutilised value of Rs. 38445 (Rupees Thirty eight thousand four hundred and forty five only). The party have filed an affidavit in support of above statement as required vide para 320 of ITC Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77.

3. In exercise of the power conferred on me under section 9(CC) of Import Control Order 1955 dated the 7th December, 1955, I order the cancellation of the aforesaid Exchange Control Purposes copy of the licence.

4. The applicant is now being issued duplicate Exchange Control copy of the aforesaid licence for Rs. 38445 (Rs. Thirty eight thousand four hundred and forty five only) on UK in accordance with provision of para 320(4) of the Hand Book of Rules and Procedure 1976-77.

[No. S/S-4/AM-76/AU-HH/CLA]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller for Jt. Chief Controller.

उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय,

(विदेश व्यापार विभाग)

अहमदाबाद, 12 नवम्बर, 1976

रद्द करने का आदेश

का० आ० 148.—सर्वश्री इलेक्ट्रिक ब्रुश मैनुफैक्चरिंग कम्पनी 5-22-27 उधव रोड, जी० वी० एम० एम०ए० वासाहाट लि०, उधव, अहमदाबाद-21 को 18414 रुपए के लिए "इलेक्ट्रो-ग्रेफाइट हार्ड कार्बन और ग्रेफाईट ग्रेड कार्बन ब्लाक" का आयात करने के लिए लाइसेंस सं० पी/एस/1838436 दिनांक 23-10-75 प्रदान किया गया था।

उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस (केवल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति) की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक-शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस पी/एस/1838136 दिनांक 23-10-75 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानास्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि उपर्युक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

[फा०सं० 212/ईयू/10181/एस०-7(6)/एएम-76/एस एसआई/5157/5639

डी० डी० सूजा, उप-मुख्य नियंत्रक

Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports

(Department of foreign trade)

Ahmedabad, the 12th November, 1976

CANCELLATION ORDER

S.O. 148.—M/s. Electric Brush Mfg. Co 5-22-27 odhav road, G.V.M.S.A. Vasahat Ltd, Odhav, Ahmedabad-21 has been granted licence No. P/S/1838436 Lt. 23-10-75 for Rs. 18414 (Rs. Eighteen thousand four hundred and fourteen only) for import of 'Electro-Graphite hard carbon and Graphite grade carbon block".

They have applied for duplicate copy of the said licence (Exchange Purpose copy only) on the ground that the original Exchange control copy has been lost/misplaced without having been registered with custom authority Bombay.

In support of their claim applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that Exchange control copy of licence No. P/S/1838436 dt. 23-10-75 has been lost/misplaced and direct that the duplicate of said Exchange control copy of the licence should be issued to applicant.

The original Exchange Control copy of licence is treated as cancelled herewith.

[F. No. 212/EU/10181/S. 7(6)/AM. 76/SSI/5157/5639]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller.

नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1976

का०आ० 149.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-4098 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, को 1975-12-16 से रद्द कर दिया गया है क्यों कि IS 1361-1959 को IS : 7452-1974 द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	लाइसेंस संख्या और तिथि (2)	लाइसेंसधारी का नाम और पता (3)	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया (4)	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक (5)
1.	सीएम/एल-4098 19-74-12-30	सर्वश्री अहमदाबाद स्टीलक्राफ्ट एण्ड रोलिंग मिल्स, ओधव अहमदाबाद-22 इनका कार्यालय गुप्ता चैम्बर्स, सारंग पुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-2 में है।	औद्योगिक इमारतों के लिए इस्पात की खिड़कियों के सेक्शन टी-3 और एफ-8	IS : 13-61-1959 औद्योगिक इमारतों के लिए इस्पात की खिड़कियों की विशिष्टि

[सं० सी एम डी/55 : 4098]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1976-12-21

S.O. 149.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L 4098 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1975-12-16 on account of supersession of IS : 1361-1959 by IS : 7452-1974 :—

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-4098 1974-12-30	M/s. Ahmedabad Steelcraft & Rolling Mills, Odhav, Ahmedabad-22 having thier office at Gupta Chambers, Outside Sarangpur Gate, Ahmedabad-2	Steel Windows Sections T-3 & F-8 for Industrial Bulldings	IS : 1361—1959 Specification for steel windows industrial building.

[No. CMD/55 : 4098]

का०आ० 150—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-11-20 में एसओ 4390 दिनांक 1976-10-27 के अधीन प्रकाशित तत्कालीन उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना के अधिक्रमण स्वरूप भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्वों पर मुहर लगाने की फीस मे कुछ परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन मुहर लगाने की फीस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 1976-04-01 से लागू होगी :—

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व (350 से 1200 साइज तक)	IS : 2906-1969 जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्वों की विशिष्टि (350 से 1200 मिमि साइज के) (पहला पुनरीक्षण)	एक स्लूस वाल्व (i) 350 मिमि से 600 मिमि साइज तक (ii) 700 मिमी साइज और उससे ऊपर के लिए	रु० 2.50 रु० 5.00

[संख्या सी एम डी/13 : 10]

ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S.O. 150.—In supersession of the then Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 4390 dated 1976-10-27, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-11-20, the Indian Standards Institution,hereby, notifies that the marking fee for sluice valves for water works purposes has been revised. The revised rate of marking fee, details of which is given in the following schedule, shall come into force with effect from 1976-04-01 :—

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. & Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	5
1.	Sluice valves for water works purposes (350 to 1200 size)	I S : 2906—1969 Specification for sluice valves for water works purposes (350 to 1200 mm size) (first revision)	One Sluice Valve (i) 350 mm to 600 mm size (ii) 700 mm size and above	 Rs. 2.50 Rs. 5.00

[No. CMD/13 : 10]

A. B. RAO, Dy. Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1976

का० आ० 151/आई० डी० आर० ए०/6/5.—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा० एस० के० सरकार, उपाचार्य, भौतिकी विभाग, विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय (यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइन्स) 92 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र मार्ग कलकत्ता-700009 को इस विभाग के 16 अप्रैल 1975 के आदेश द्वारा गठित उपकरण उद्योग विकास परिषद का उसकी शेष अवधि के लिए सदस्य इस आदेश की तारीख से तुरन्त प्रभावशील रूप में नियुक्त करती है।

[सं० आई० एम० ई०-3(4)/74]

सी० मल्लिकार्जुनन, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1976

S.O. 151/IDRA/6/5.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints with immediate effect from the date of this order, Dr. S. K. Sarkar, Reader, Department of Physics, University College of Science, 92, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-700009, to be a member of the Development Council for Instruments Industry for the rest of its term, constituted vide this Department's order dated the 16th April, 1975.

[No. IME-3(4)/74]

C. MALLIKARJUNAN, Dy. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० आ० 152.—केन्द्रीय सरकार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 89) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री यू० के० मुखोपाध्याय लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय कलकत्ता को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त संदाय आयुक्त की सहायता करने के लिए तुरन्त नियुक्त करती है।

[सं० इण्ड (2)-8(67)/76]

रा० मल्लिकार्जुनन, उप-सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 24th December, 1976

S.O. 152.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976 (89 of 1976), the Central Government hereby appoints with immediate effect Shri U. K. Mukhopadhyay, Deputy Iron and Steel Controller, Office of the Iron and Steel Controller, Calcutta, to assist the Commissioner of Payments, in addition to his existing duties.

[No. Ind. II-8(67)/76]

R. MALLIKARJUNAN, Dy. Secy.

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1976

का० आ० 153.—यतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5672 तारीख 28-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रुद्रसागर जी० जी० एस० नवम्बर 2 के चारों तरफ पाइपलाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—मेमेकाबीनगांव

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्तियेरे
रूपहिबील . .	682 ख		4	55
	682 घ		5	08
	681 ख		5	08
	680 ख		6	69
	674 ख		0	54
	675 ख		3	88
	678 ख		3	21
	795 ग		2	94
	71 ख		5	89
	787 ख		0	67

[सं० 12020/5/75-एल एण्ड एल-II]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 27th November, 1976

S.O. 153.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5672 dated 28-11-75 under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the competent Authority has under Sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Naturad Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline Around RDS. GGS No. 2.

State : Assam Distt.: Sibsagar Taluk : Meteka Bongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rupohibil . .	682 Kha	0	4	55
	682 Gha	0	5	08
	681 Kha	0	5	08
	680 Kha	0	6	69
	674 Kha	0	0	54
	675 Kha	0	3	88
	678 Kha	0	3	21
	795 Kha	0	2	94
	71 Kha	0	5	89
	787 Kha	0	0	67

[No. 12020/5/75L&LII]

का० आ० 154.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5669 तारीख 28-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विनिहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी संघर्षों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 1 से गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—आटखेल

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टी एरे
गोलिकी ग्रान्ट नम्बर 1 .	4 ग	0	1	34
	3 ग	0	0	54
	2 ग	0	0	94
	77 ग	0	7	76

[सं० 12020/5/75-एल एण्ड एल-I]

S.O. 154.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5669 dated 28-11-75 under Su-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the competent Authority has under Sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the power conferred by sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki GGS No. 1 to Geleki GGS No. 2

State : Assam Dist. : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Geleki Grant No. 1	4 Ga	0	1	34
	3 Ga	0	0	54
	2 Ga	0	0	94
	77 Ga	0	7	76

[No. 12020/5/75-L&L-I]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1976

का० आ० 155—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० ..... तारीख ..... द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघर्षों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एन के-73 और 74 से एन के एल तक भूमि के उपयोग का अधिकार

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कादी

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टेयर	एरे	सेन्टियर
1	2	3	4	5
सूरज	721	0	07	50
	720	0	07	00
	584	0	04	50

[सं० 12016/2/76-एल एण्ड एल/प्रोडक्शन]

New Delhi, the 6th December, 1976

S.O. 155.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No.....dated under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acequire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances

SCHEDULE

R.O.U. from NK-73 & 74 to R.O.U. NKL

State : Gujarat District : Mehsana Taluka:Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Suraj	721	0	07	50
	720	0	07	00
	584	0	04	50

[No. 12016/2/76-L&L Prod]

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1976

शुद्धि-पत्र

का० आ० 156.—पेट्रोलियम मंत्रालय दिनांक 5-6-1976 पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 . मेहसाना ।

पेट्रोलियम पाइप लाइन अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला मेहसाना में व्यधन क्षेत्र के-72 से जी० जी० एस-III में भूमि के उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिये पैट्रोलियम मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12016/2/75-एल एण्ड एल दिनांक 31-12-75 और संख्या 12016/2/75-एल एण्ड एल दिनांक 20-5-1976 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से नीचे दी गई अनुसूची को पढ़ें :—

पढ़ें			के लिये		
गांव	तालुका	जिला	गांव	तालुका	जिला
अम्बवपुरा	कादी	मेहसाना	अम्बवपुरा	कलोल	मेहसाना

[संख्या 12016/2/75-एल एण्ड एल/प्रोडक्शन]

New Delhi, the 16th December, 1976

ERRATUM

S.O. 156.—Ministry of Petroleum, New Delhi, dated 5-6-1976, Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962, District : Mehsana.

In schedule appended to the Government Notification Ministry of Petroleum, Department of Petroleum, New Delhi No. 12016/2/75-L & L dated 31-12-1975, issued under section 3(1) and Notification No. 12016/2/75-L & L dated 20-5-1976 issued under section 6(1) of petroleum pipelines Act, 1962, for the acquisition of right of user for laying pipeline from d.s.K-72 to G.S-III in Gujarat State, District Mehsana :—

Read			For		
Village	Taluka	District	Village	Taluka	District
Ambavpura	Kadi	Mehsana	Ambavpura	Kalol	Mehsana

[No. 12016/2/75-L&L/Prod.]

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1976

का० आ० 157:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के शिवसागर जिले में गलेकी से जोरहाट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः; अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गोलेकी—जोरहाट तक पाईप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—गधुली बजार

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्तर	ऐरे	सेन्टी ऐरे
1	2	3	4	5
वेउधाई गांव . .	58 ख		7	89
	59 ख		5	48
	61 ख		3	21
	70 ख		2	14
	75 ख		1	07
	62 ख		5	48
	63 ख		0	54
	71 ख		2	81
	159 ख		5	48
	72 ख		2	27
	74 ख		5	89
	157 ख		5	48
	158 ख		3	75
	212 ख		2	01
	213 ख		3	75
	214 ख		3	75
	216 ख		3	88
	218 ख		5	48
	336 ख		1	34
	217 ख		3	21
	219 ख		1	47
	328 ख		2	81
	264 ख		6	96
	265 ख		8	70
	266 ख		0	40
	327 ख		0	27
	340 ख		3	21
	347 ख		4	55
	267 ख		0	40
	271 ख		6	42
	272 ख		10	17
	277 ख		0	54
	337 ख		10	84
	316 ख		0	27
	325 ख		2	41
	317 ख		1	07
	573 ख		2	01
	326 ख		12	31
	329 ख		2	94
	331 ख		1	61
	338 ख		1	61
	333 ख		0	54
	334 ख		3	21
	335 ख		1	07
	576 ख		2	01
	558 ख		3	75
	564 ख		2	68
	569 ख		2	14
	561 ख		0	27
	562 ख		1	34
	563 ख		4	28
	571 ख		1	74
	565 ख		2	68
	566 ख		1	87
	580 ख		2	01
	576 ख		2	68
	568 ख		2	01
	578 ख		1	61
	570 ख		2	14
	572 ख		3	34
	574 ख		2	68
	575 ख		2	68
	577 ख		2	27
	579 ख		1	74
	581 ख		3	21
	582 ख		1	87
	583 ख		2	68
	585 ख		2	68
	586 ख		2	68
	587 ख		2	14
	588 ख		1	87

[सं० 12020/5/76-प्रोडक्शन]

New Delhi, the 18th December, 1976

S.O. 157.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki to Jorhat in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed here to :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Geleki—Jorhat Trunk Pipeline

State : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Godhuli Bazar

Village	Survey No.	Hector	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Deodhal Gaon .	58 Kha	..	7	89
	59 Kha	..	5	48
	61 Kha	..	3	21
	70 Kha	..	2	14
	75 Kha	..	1	07
	62 Kha	..	5	48
	63 Kha	..	0	54
	71 Kha	..	2	81
	159 Kha	..	5	48
	72 Kha	..	2	27
	74 Kha	..	5	89
	157 Kha	..	5	48
	158 Kha	..	3	75
	212 Kha	..	2	01
	213 Kha	..	3	75
	214 Kha	..	3	75
	216 Kha	..	3	88
	218 Kha	..	5	48
	336 Kha	..	1	34
	217 Kha	—	3	21
	219 Kha	..	1	47
	328 Kha	..	2	81
	264 Kha	..	6	96
	265 Kha	..	8	70
	266 Kha	..	0	40
	327 Kha	..	0	27
	340 Kha	..	3	21
	347 Kha	..	4	55
	267 Kha	..	0	40
	271 Kha	..	6	42
	272 Kha	..	10	17
	277 Kha	..	0	54
	337 Kha	..	10	84
	316 Kha	..	0	27
	325 Kha	..	2	41
	317 Kha	..	1	07
	573 Kha	..	2	01
	326 Kha	..	12	31
	329 Kha	..	2	94
	331 Kha	..	1	61
	338 Kha	..	1	61
	333 Kha	..	0	54
	334 Kha	..	3	21
	335 Kha	..	1	07
	576 Kha	..	2	01
	558 Kha	..	3	75
	564 Kha	..	2	68
	569 Kha	..	2	14
	561 Kha	..	0	27
	562 Kha	..	1	34
	563 Kha	..	4	28
	571 Kha	..	1	74
	565 Kha	..	2	68
	566 Kha	..	1	87
	580 Kha	..	2	01
	567 Kha	..	2	68
	568 Kha	..	2	01
	578 Kha	..	1	61
	570 Kha	..	2	14
	572 Kha	..	3	34
	574 Kha	..	2	68
	575 Kha	..	2	68
	577 Kha	..	2	27
	579 Kha	..	1	74
	581 Kha	..	3	21
	582 Kha	..	1	87
	583 Kha	..	2	68
	585 Kha	..	2	68
	586 Kha	..	2	68
	587 Kha	..	2	14
	588 Kha	..	1	87

[No. 12020/5/76-Prod.]

का०आ० 158.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि असम के शिवसागर जिले में लकवा कूप नम्बर एल एम एफ से लेकवा न. 1 जी०जी०एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः; अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

लकवा कूप नम्बर एल० एम० एफ० (LMF) से लकवा जी०जी० एस० नं० 1 तक की पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—शिलाकुटी

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी-ऐरे
1	2	3	4	5
नरा गांव .	569 ख	0	1	34
	73 ख	0	2	81

1	2	3	4	5
नरा गाव (जारी)	570 ख	0	2	68
	519 ख	0	0	40
	566 ख	0	4	55
	520 ख	0	0	91
	525 ख	0	4	01
	577 ख	0	3	08
	524 ख	0	2	81
	567 ख	0	0	94
	568 ख	0	1	87

[सं० 1220/14/76-प्राउक्शन-I]

S.O 158.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Lakwa Well No. LMF to Lakwa GGS No 1 in Sibsagar Dist, Assam Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed here to ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipline from Lakhwa well No LMF to Lakwa GGS No 1

State Assam Dist. Sibsagar Taluk Silakuti

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Nara Gaon	569 Kha	0	1	34
	573 Kha	0	2	81
	570 Kha	0	2	68
	519 Kha	0	0	40
	566 Kha	0	4	55
	520 Kha	0	0	94
	525 Kha	0	4	01
	577 Kha	0	3	08
	524 Kha	0	2	81
	567 Kha	0	0	94
	568 Kha	0	1	87

[No 12020/14/76-Prod -I]

का० आ० 159—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के जिला शिवसागर में रुद्रसागर कूप नं० 54 से रुद्रसागर जी० जी० एस नं० -1 तक के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन सन एव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अब अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ,

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपमण्डल अधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में उस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 54 से रुद्रसागर जी० जी० एस नं० 1 तक की पाइप लाइन,

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—जकाइचुक,

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टी-एरे
1	2	3	4	5
नामदंगीया बंगाली	603 ख	—	2	01
	604 ख	—	5	35
	605 ख	—	2	94
	580 ख	—	0	67

[सं० 12020/4/76—प्रोडक्शन-I]

S.O. 159.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 54 to Rudrasagar GGS No 1 in Sibsagar Dist, Assam Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed here to ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Rds well No 54 to Rds GGS No 1

State Assam Dist Sibsagar Taluk Jokaichuk

Villagge	Survey No	Hector	Are	Centiare
Namdongia Bongali	603 Kha		2	01
	604 Kha		5	35
	605 Kha		2	94
	580 Kha		0	67

[No 12020/4/76-Prod-I]

का० आ० 160.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के जिला शिवसागर में गलेकी से जोरहाट तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है,

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप उप-मण्डल अधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गेलिकी—जोरहाट ट्रंक पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—गधूली बजार

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी ऐरे
अभई पूरीया नरा . .	220 ख	—	13	11

[सं० 12020/4/76-प्रोडक्शन-II]

S.O. 160.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki to Jorhat in Sibsagar District, Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Geleki-Jorhat Trunk Pipeline.

State:Assam District : Sibsagar Taluk : Godhuli Bazar

Village	Survey No.	Hector	Are	Centiare
Abhoipuria nora .	220 Kha	..	13	11

[No. 12020/4/76-Prod-II]

का० आ० 161.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के शिवसागर जिले में लकवा कूप नं० एल० एम० एफ० से लकवा जी० जी० एस नं० 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

लकवा कूप नम्बर एल० एम० एफ (LMF) से लकवा जी० जी० एस नं० 1 तक की पाइप लाइन ।

राज्य असम जिला शिवसागर तालुक . शिमालुगुरी

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी-ऐरे
सालापथार . .	155 ख	0	1	07
	166 ख	0	2	27
	86ख	0	2	14
	87 ख	0	2	41
	148ख	0	1	74
	157 ख	0	1	07
	158 ख	0	1	20
	107 ख	0	2	27
	218 ख	0	3	21
	72 ख	0	1	47

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी-ऐरे
सोला पथार	106 ख	0	2	01
	217 ख	0	2	68
	219 ख	0	2	41
	150 ख	0	1	47
	156 ख	0	1	07
	167 ख	0	2	01
	163 ख	0	1	47
	74 ख	0	1	87
	164 ख	0	1	47
	151 ख	0	1	74
	165 ख	0	1	47
	149 ख	0	2	68
	147 ख	0	1	74
	221 ख	0	2	14
	108 ख	0	1	20
	84 ख	0	0	54
	91 ख	0	2	54
	220 ख	0	2	81
	71 ख	0	1	47
	201 ख	0	5	08
	73 ख	0	1	47
	146 ख	0	2	27
	205 ख	0	0	27
	223 ख	0	2	14
	222 ख	0	1	87

[सं० 12020/14/76-प्रोडक्शन-II]

S.O. 161.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Lakwa Well No. LMF to Lakwa GGS No. 1 in Sibsagar District, Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Lakwa well No. LMF to Lakwa GGS No.1

State : Assam	Dist. : Sibsagar	Taluk : Silakuti		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Solapathar	155 Kha	0	1	07
	166 Kha	0	2	27

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Solapathar	86 Kha	0	2	14
	87 Kha	0	2	41
	148 Kha	0	1	74
	157 Kha	0	1	07
	158 Kha	0	1	20
	107 Kha	0	2	27
	218 Kha	0	3	21
	72 Kha	0	1	47
	106 Kha	0	2	01
	217 Kha	0	2	68
	219 Kha	0	2	41
	150 Kha	0	1	47
	156 Kha	0	1	07
	167 Kha	0	2	01
	163 Kha	0	1	47
	74 Kha	0	1	87
	164 Kha	0	1	47
	151 Kha	0	1	74
	165 Kha	0	1	47
	149 Kha	0	2	68
	147 Kha	0	1	74
	221 Kha	0	2	14
	108 Kha	0	1	20
	84 Kha	0	0	54
	91 Kha	0	2	54
	220 Kha	0	2	81
	71 Kha	0	1	47
	201 Kha	0	5	08
	73 Kha	0	1	47
	146 Kha	0	2	27
	205 Kha	0	0	27
	223 Kha	0	2	14
	222 Kha	0	1	87

[No. 12020/14/76-Prod.-II]

का०आ० 162.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि असम के जिला शिवसागर में गेलिकी से जोरहाट तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादो के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अत: अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उप-मण्डल अधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

गेलिकी—जोरहाट ट्रंक पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—गोधूली बाजार,

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी ऐरे
गधूली बजार चाउदांग गाव	35क		3	34
	36ख		0	80
	32ख		15	25
	271ख		3	75
	272ख		1	34
	468ख		3	48
	796ख		13	92
	800ख		2	81
	806ख		10	57
	450ख		6	69
	455ख		11	37
	805ख		4	01
	464ङ		3	08
	464छ		1	74
	465ख		4	41
	467क		2	81
	801ख		0	13

[सं० 12020/4/76-प्रोडक्शन-III]

S.O. 162.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki to Jorhat in Sibsagar District, Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz., the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Geleki—Jorhat Trunk Pipeline

State : Assam Distt. : Sibsagar Taluk : Godhli Bazar

Village	Survey No.	Hector.	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Godhuli Bazar	35 Kha	..	3	34
Chowdang Gaon	36 Kha	..	0	80
	32 Kha	..	15	25
	271 Kha	..	3	75
	272 Kha	..	1	34
	468 Kha	..	3	48
	796 Kha	..	13	92
	800 Kha	..	2	81
	806 Kha	..	10	57
	450 Kha	..	6	69
	455 Kha	..	11	37
	805 Kha	..	4	01
	464 Unga	..	3	08
	464 Cha	..	1	74
	465 Kha	..	4	41
	467 Ka	..	2	81
	801 Kha	..	0	13

[No. 12020/4/76-Prod. III]

का० आ० 163—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के जिला शिवसागर में गेलिकी से जोरहाट तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइप-लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उप-मण्डल अधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

गेलिकी—जोरहाट ट्रंक पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—गोधूली बाजार

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टी ऐरे
लालीमछिगा चापारि	113ख		1	87
	115ख		2	14
	209ख		16	19
	210ख		1	47
	212ख		4	01
	212ग		3	34
	239ख		8	16
	114ख		7	22
	238ख		8	70

[सं० 12020/4/76 प्रोडक्शन-IV]

S.O. 163.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki to Jorhat in Sibsagar District, Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Geleki—Jorhat Trunk Pipeline

State—Assam Dist—Sibsagar Taluka—Godhuli Bazar

Village	Survey No.	Hector	Are	Centiare
Lalimchiga	113 Kha	—	1	87
Chapari	115 Kha	..	2	14
	209 Kha	..	16	19
	210 Kha	..	1	47
	212 Kha	—	4	01
	212 Ga	—	3	34
	239 Kha	—	8	16
	114 Kha	—	7	22
	238 Kha	—	8	70

[No. 12020/4/76-Prod. IV]

का० आ० 164.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम के जिला शिवसागर मे गेलिकी से जोरहाट तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादो के परिवहन के लिए पाइप-लाइन तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उप-मण्डल अधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत्।

अनुसूची

गेलिकी—जोरहाट ट्रंक पाइप लाइन

राज्य—असम जिला—शिवसागर तालुक—गधुलीबजार

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	एरे	सेन्टीएरे
हातीमुरीया घरफलीया गाव	1590 ख		0	40
	1681 ख		9	23
	1682 ख		4	28
	1683 ख		2	94
	1738 ख		2	94
	1681 ख		2	41
	1686 ख		2	94
	1685 ख		5	22
	1689 ख		1	20
	1691 ख		6	15
	1692 ख		6	15
	1693 ख		4	01
	1697 ख		17	13
	1702 ख		1	20
	1728 ख		0	27
	1729 ख		18	86
	1740 ख		18	33
	1730 क		24	62
	1741 ख		0	94
	1742 ख		4	28
	1743 ख		3	34
	1690 ख		3	75
	1733 ख		6	96

[सं० 12020/4/76 प्रोडक्शन —V]

S.O. 164.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki to Jorhat in Sibsagar District, Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Geleki—Jorhat Trunk Pipeline

State—Assam Dist.—Sibsagar Taluka—Godhuli Bazar

Village	Survey No	Hector	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Hatimuria Ghor-	1590 Kha	—	0	40
folia Gaon	1681 Kha	—	9	23

1	2	3	4	5
	1682 Kha	—	4	28
	1683 Kha	—	2	94
	1738 Kha	—	2	94
	1684 Kha	—	2	41
	1686 Kha	—	2	94
	1685 Kha	—	5	22
	1689 Kha	—	1	20
	1691 Kha	—	6	15
	1692 Kha	—	6	15
	1693 Kha	—	4	01
	1697 Kha	—	17	13
	1702 Kha	—	1	20
	1728 Kha	—	0	27
	1729 Kha	—	18	86
	1740 Kha	—	18	33
	1730 Kha	—	24	62
	1741 Kha	—	0	94
	1742 Kha	—	4	28
	1743 Kha	—	3	34
	1690 Kha	—	3	75
	1733 Kha	—	6	96

[No. 12020/4/76-Prod. V]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1976

का० आ० 165.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में व्यधन क्षेत्र एस० एन० ए० से डब्ल्यू० एम० आई० सन्थल 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया, कोयाली/वीरमगम पाइपलाइन प्रोजैक्ट, "डोली" 33-बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत्।

अनसूची

कूप सं० एस० एन० ए० से डब्ल्यू० एच० आई० सेन्थल-4 तक पाईप लाईन बिछाना

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण सं०	हैक्टर ए	आर ई सेन्टियर
1	2	3	4 5
सन्थल	634	0	04 68
	866/1	0	10 80
	867	0	04 75
	872	0	07 75
	873	0	04 68
	874	0	06 00
	824	0	01 20
	822	0	14 88
	825	0	02 16
	819	0	13 00
	787/2	0	02 50
	817/1	0	10 80
	789	0	00 84
	790/2	0	12 72
	816	0	07 20
	884	0	02 75
	885	0	07 20
जोलना	1241	0	23 50
	1240	0	09 60
	1238	0	15 00
	1233	0	07 20
	1234	0	18 00
इशपुरा	509/4	0	15 60
	509/1	0	09 00

[सं० 12016/5/76-एल० एंड एल-I]

New Delhi, the 21st December, 1976

S.O. 165.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SNA to WHI Santhal-4 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation, Salaya-Koyali/Viramgam pipeline project, "Doli", 33-B, Harihar Society, Kalavad Road, Rajkot;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from Well No. SNA to WHI Santhal-4

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Santhal	634	0	04	68
	866/1	0	10	80
	867	0	04	75
	872	0	07	75

1	2	3	4	5
	873	0	04	68
	874	0	06	00
	824	0	01	20
	822	0	14	68
	825	0	02	16
	819	0	13	00
	787/2	0	02	50
	817/1	0	10	80
	789	0	00	84
	790/2	0	12	72
	816	0	07	20
	884	0	02	75
	885	0	07	20
Jotana	1241	0	23	50
	1240	0	09	60
	1238	0	15	00
	1233	0	07	20
	1234	0	18	00
Ijpura	509/4	0	15	60
	509/1	0	09	00

[No. 12016/5/76-L&L-I]

का० आ० 166.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे व्यक्षम क्षेत्र एस० सी० ए० एस० डी० एम० से एस० बी एच० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयाजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत., अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड सलाया-कोयाली वीरमगम पाइपलाइन प्रोजैक्ट, "डोली"—33-बी, हरिहर सोसाइटी, कलावद रोड राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

व्यक्षम क्षेत्रो एस० सी० ए०, एस० डी० एम० से एस० बी० एच० तक पाईप लाईन बिछाना

राज्य : गुजरात जिला . मेहसाना तालुका · मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण न०	हैक्टर	ए. आर.ई: सेन्टियर	
1	2	3	4	5
मेहसाना . .	1995/16/1	0	03	25
	1995/54	0	03	25
	1995/11	0	14	60
	1995/10	0	10	80
	2000/1	0	03	00
	2028	0	33	00
नागलपुर	404/11	0	19	50
	404/10	0	11	80
	404/8	0	21	00
	404/7	0	09	00
	404/3	0	03	60
	404/4	0	15	60
कुकस	ब्लोक सं०			
	322/पी	0	06	00

[सं० 12016/5/67—एस० एण्ड एल-II]

S.O. 166.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SCA, SDM to SBH in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise, of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation, Salaya-Koyali/Viramgam pipeline project, "Doli", 33-B Harihar Society, Kalavad Road, Rajkot ;

And every making such an objection shall also state state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from Dril Sites SCA, SDM to SBH

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Mehsana	1995/16/1	0	03	25
	1995/54	0	03	25
	1995/11	0	14	60
	1995/10	0	10	80
	2000/1	0	03	00
	2028	0	33	00
Nagalpur	404/11	0	19	50
	404/10	0	11	80
	404/8	0	21	00
	404/7	0	09	00
	404/3	0	03	60
	404/4	0	15	60
Kukas	Block No.			
	322/P	0	06	00

[No. 12016/5/76-L&L-II]

का० आ० 167.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में व्यधन क्षेत्र एस० डी० जी० से एस० डी० एफ० तक एस० बी० डब्ल्यू० जी० जी० एस० सोभासन तक जाने वाली लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलाया-कायाली/मथुरा, पाइपलाइन प्रोजैक्ट, "डोली"—33-बी हरिहर सोसाइटी, कलावडरोड, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनसूची

आर० डी० यू० व्यधन क्षेत्र एस० डी० जी० से व्यधन क्षेत्र एस० डी० एफ० से एस० आर० डब्ल्यू० जी० जी० एस० सोभासन-1 जोड़ने वाली लाइन तक।

राज्य—गुजरात जिला मेहसाना तालुका मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	एआर ई	सेन्टियर
हेबुवा	50	0	07	50
	कार्ट ट्रैक्ट	0	01	00
	72	0	05	40
	71	0	03	75
	73	0	07	00
	74	0	08	75
	91	0	06	50
	कार्ट ट्रैक्ट	0	00	60
	86	0	06	67
	88	0	01	20
	290	0	07	75
	98	0	01	00

[सं० 12016/5/76-एल०एंड एल-III]

S.O. 167.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SDG to SDF line connecting with SBW-GGS Sobhasan-1 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of he powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation, Salaya-Koyali/Mathura, Pipeline Project, "Doli" 33-B, Harihar Society, Kalavad Road, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. From D.S. SDG to D.S. SDF Line Connecting with SBW—GGS Sobhasan-1

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	50	0	07	50
	Cart-track	0	01	00
	72	0	05	40
	71	0	03	75
	73	0	07	00
	74	0	08	75
	91	0	06	50
	Cart-track	0	00	60
	86	0	06	67
	88	0	01	20
	290	0	07	75
	98	0	01	00

[No. 12016/5/76-L&L-III]

का० आ० 168—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में व्यधन क्षेत्र एस० बी० जेड से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० सोभासन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मलाया-कायाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजैक्ट, "डोली"—33-बी, हरिहर सोसाइटी, कलावद रोड राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

'अनुसूची'

आर० ओ० यू० अघन क्षेत्र एस० बी० जेड से जी० जी० एस०-कम-सी० टी० एफ० सोभासन तक

राज्य : गुजरात	जिला :	मेहसाना	तालुका :	मेहसाना
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	ए आर ई	सेन्टियर
पुनासन	126	0	03	50

[स० 12016/5/76-एल० एण्ड एल० (4)]
टी० पी० सुब्रह्मनियन, अवर सचिव

S.O. 168.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. SBZ to GGS-cum-CTF Sobhasan in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project "Doli" 33-B Harihar Society, Kalavad Road, Rajkot;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. From D.S. SBZ to GGS-cum-CTF Sobhasan

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Punasan	126	0	03	50

[No. 12016/5/76-L&L-IV]
T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1976

शिथिलीकरण आदेश

खान का नाम — झाकरा बुकबुका कोलियरी

स्वामी का नाम — सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

निरीक्षण की तारीख — 30 अक्तूबर, 1975

का०आ० 169.—भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम 133 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के,

(1) नियम 118 (क),

(2) नियम 119 (1) (क),

(3) नियम 118 (ग),

(4) नियम 123 (7), और

(5) नियम 130

के उपबन्ध झाकरा बुकबुका कोलियरी में यू० एस० एम० आर० मेक 3.3 के० वी० विद्युत् उत्खनित्र (एक्सकेवेटर), माडल ई० के० जी० 4.6 बी० सीरियल नं० 715 के साथ निम्नलिखित साधित्र के उपयोग की बाबत शिथिल किए जाएंगे।

(1) एक उत्खनित्र, मेक यू० एस० एम० आर० वोल्टेज 3.3 के० वी० ए० पी० एम० 100, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी 15 एम० वी० ए०, टाइप 2 के० वी० एम० -6 टी, सीरियल नं० 1344, 3 फेज, 50 सी०/एस० पर माउण्ट किया गया एक कन्ट्रोल पैनल।

(2) एक स्क्विरल केज ए०सी० इन्डक्शन मोटर मेक यू०एस०एस० आर०, 3.3, के० वी०, 250 के० डब्ल्यू०, 3-फेज, 50 सी०/एस०, टाइप ए० डी०/11-34 टी०, सीरियल नं० 5212

(3) एक ट्रान्सफार्मर मेक यू० एस० एस० आर०, 40 के० वी० ए०, 3300/230 वी०, टाइप टी० एम०-40/33, जिसमें तेल के साथ प्राकृतिक शीतलन होता हो, सीरियल नं० 466524, 3-फेज, 50 सी०/एस०

(4) 300 मीटर फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल, 4-कोर, 3.3 के० वी० ग्रेड, पृथक-पृथक स्क्रीन सरक्षित, साइज 3×25+1×10 वर्ग मि०मी०, कापर कण्डक्टर, जो दो ओवर करेण्ट रिले (इनवर्स) टाइप सी० डी० जी०, और एक अर्थफाल्ट रिले (इनवर्स) टाइप सी० डी० जी०, सीरियल नं० 3350/74 से युक्त टाटा मेरलिन-गेरिन, 3.3 के० वी० एयर सर्किट ब्रेकर द्वारा नियन्त्रित हो।

मेसर्स सेण्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की झाकरा बुकबुका विवृत्त खान में उस सीमा तक कि (1) नियम 118(क) के शिथिलीकरण में सुवाह्य मोटर (250 के० डब्ल्यू०, 3.3 के० वी०) का जो उत्खनित्र मे जनित्र को चलाता हो, 3.3 के० वी० पर उपयोग किया जा सकता है; (2) नियम 119(1) (क) के शिथिलीकरण मे, 40 के० वी० ए०, 3300/230 वी०, 3-फेज ट्रांसफार्मर, उसके सहयुक्त उपस्कर सहित, जो उच्च वोल्टता पर ऊर्जा का उपयोग कर रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले सुवाह्य उत्खनित्र पर संस्थापित किए जाने के कारण स्थिर साधित्र नहीं होगा, क्योंकि वह भी सुवाह्य समझा जाएगा; (3) नियम 118(ग) के शिथिलीकरण में, 40 के० वी० ए०, 3300/230 वी०, 3-फेज ट्रांस्फार्मर से, जिसका सेकेण्डरी का न्यूट्रल विद्युत् रोधी हो, उत्खनित्र के भीतर प्रकाश करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु, प्राशयित प्रदाय का 125 वोल्ट सिस्टम उपयोग में लाया जा सकेगा, (और इस प्रकार सिस्टम की वोल्टता फेज और विद्युत् रोधी न्यूट्रल के बीच प्राप्त होती है, जो कि फेजों के बीच, जैसा कि नियम 118(ग) में अनुध्यात है, और प्रदाय के 125-वोल्ट सिस्टम का विशेष रूप से विशेष ध्यान रखा जाता है); (4) नियम 130 के शिथिलीकरण मे, 40 के० वी० ए० 3300/230 वाल्ट, 3-फेज ट्रांस्फार्मर का न्यूट्रल प्वाइंट विद्युत् रोधी रह सकता है; और (5) नियम 123(7) के शिथिलीकरण मे, लम्बाई में 300 मीटर से अनधिक फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल का सुवाह्य मशीन के साथ उपयोग किया जा सकेगा; शिथिलीकरण निम्नलिखित शर्तों पर होगा:—

1. फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल को 3.3 के० वी० प्रदाय में भू-क्षरण (अर्थ लीकेज) सरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल को 3.3 के० वी० प्रदाय को नियंत्रित करने वाले सर्किट ब्रेकर की ओवर-करेण्ट ट्रिपें उत्खनित्र पर संस्थापित जनित्र सेट को चलाने वाले 3.3 के० वी० मोटर की रेटिंग के अनुरूप होंगी।

3. उत्खनित्र के अन्दर संस्थापन और वाईरिंग (तार का लगाया जाना) भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के सुसंगत उपबंधों, विशेष रूप से नियम 115-117, 121, 124, 125(1), 125(4) और 125(8) के अनुरूप होंगे।

4. फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल को विद्युत् प्रदाय सिस्टम और मशीन से, समुचित रूप से सन्तर्मित कनेक्टर बक्सों या पूर्णतः बन्द सुरक्षित साधित्र द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

5. उत्खनित्र तथा फ्लेक्सिबिल ट्रेलिंग केबिल को सम्यक् सावधानी के साथ काम में लाया और हथाला जाएगा जिससे कि किसी भी प्रकार के वैद्युत् दोष से होने वाले या प्रयोग में होने वाले खतरे से बचा जा सके। उच्च वोल्टता सर्किट का, जिसमें चालन-मोटर सम्मिलित है, विद्युत् रोधी प्रतिरोध किसी भी समय 10 मेगओहम से कम नहीं होगा।

6. उत्खनित्र के प्रचालकों को किसी सक्षम वैद्युत् इंजीनियर के अधीन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें सक्षमता और सम्यक् सावधानी के साथ उत्खनित्र के प्रचालन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा जिससे कि खतरे से बचा जा सके।

परन्तु पूर्वोक्त शिथिलीकरण उतने समय के लिए विधिमान्य होगा, जितने समय तक उक्त मशीन खान में उपयोग में हो, तथा मशीन के खान से बाहर निकाले जाने के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार को, संबंधित सर्किल के उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत्) की मार्फत, सम्यक् सूचना दी जाएगी।

[सं० ई० एल० 2-6(13)/75]

एम० एस० एस० शास्त्री, उप-निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 22nd December, 1976

RELAXATION ORDER

Name of Mine :	Dakra Bukbuka Colliery.
Name of Owner :	Central Coal Fields Ltd.
Date of Inspection :	30th October, 1975.

S.O. 169.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Central Government hereby directs that the provisions of:—

(i) Rule 118(a),

(ii) Rule 119(1)(a),

(iii) Rule 118(c),

(iv) Rule 123(7), and

(v) Rule 130

of the Indian Electricity Rules, 1956, shall be relaxed in respect of the use of the following apparatus in conjunction with one U.S.S.R. make 3.3 KV Electric Excavator, Model EKG 4 6 B. Sl. 715 at Dakra Bukbuka Colliery.

(1) One control panel mounted on the Excavator Make USSR voltage 3.3 KV, Amps 100, Rated Rupturing capacity 15 MVA, Type 2 KB-M-6T, Sl No. 1344, 3-phase, 50 c/s.

(2) One Squirrel cage A.C. Induction motor Make USSR, 3.3 KV, 250 KW, 3-phase, 50 c/s, Type Ad-113-4T, Sl. No. 5212,

(3) One transformer, Make USSR, 40 KVA, 3300/230 V, Type TM-40/33, natural cooling with oil, Sl. No. 466524, 3-phase, 50 c/s,

(4) 300 Metres of flexible trailing cable, 4-core, 3.3 KV grade, individually screen protected, size $3 \times 25 + 1 \times 10$ sq. mm., copper conductor, controlled by one Tata Merlin-Gerin, 3.3 KV air circuit breaker fitted with two over-current Relay (inverse) type CDG, and one earth fault relay (inverse) type CDG, Sl. No. 3350/74.

In Dakra Bukbuka open cast Mine of M/s. Central Coal Fields Ltd. to the extent that (i) in relaxation of Rule 118(a), the portable motor (250 KW, 3.3 KV) driving the generator set in the excavator may be used at 3.3 KV., (ii) in relaxation of Rule 119(1)(a) one 40 KVA, 3300/230 V, 3-phase transformer with its associated equipment using energy at high voltage may not be a fixed apparatus as being installed on the portable excavator moving from place to place, the same having a portable sense; (iii) in relaxation of Rule 118(c), the 125 Volts system of supply intended for use for lighting purposes within the excavator from 40 KVA, 3300/230 V, 3-phase, transformer, the transformer having the neutral of the secondary insulated, and as such the voltage of the system being obtained between a phase and insulated neutral and not between phases as contemplated in Rule 118(c), the 125-volts systems of supply is specially considered may be used; (iv) in relaxation of Rule 130 the neutral point of 40 KVA 330/230 Volt, 3-phase transformer may remain insulated and (v) in relaxation of Rule 123(7), the flexible trailing cable not exceeding 300 Metres in length may be used with the portable machine and the relaxations shall be subject to the following conditions :—

1. The 3.3 KV supply to the flexible trailing cable should be provided with earth leakage protection.

2. The over-current trips of the circuit breaker controlling 3.3 KV supply to the flexible trailing cable shall be in keeping with the rating of the 3.3 KV motor driving the generator set installed on the Excavator.

3. The installations and wirings inside the Excavator shall comply with the relevant provisions of the Indian Electricity Rules, 1956, in particular, Rules, 115—117, 121, 124, 125(1), 125(4) and 125(8).

4. The flexible trailing cable should be connected to the electric supply system and the machine by properly constructed connector boxes or totally enclosed safe apparatus.

5. The Excavator along with the flexible trailing cable shall be worked and handled with due care so as to avoid danger arising out of any electrical defect or in the use. The insulation resistance of the high-voltage circuit including the driving motor shall at no time be less than 10 Megohm.

6. The operators of the Excavator shall be trained sufficiently under a competent electrical engineer and authorised by him for operating the excavator with competency and due care to avoid danger.

Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for such time as the said machine is in use in the mine and due information shall be given to the Central Government through the Deputy Director of Mines Safety (Electrical) of the Circle concerned as soon as the machine is taken out of the mine.

[No. EL. II-6(13)/75]

M. S. S. SHASTRY,, Dy. Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० आ० 170.—कोयला क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 681 तारीख 27 जनवरी, 1976 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 780.00 एकड़ (लगभग) या 315.65 हैक्टेयर (लगभग) माप की भूमि अर्जित की जानी चाहिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 780.00 एकड़ (लगभग) या 315.65 हैक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित की जाती है।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण उपायुक्त रांची (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में, या सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

डाकरा खण्ड

उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड

ड्राइंग सं० राजस्व /22/76

तारीख 14-4-76

समस्त अधिकार (जिसमें अर्जित भूमि दर्शित है)

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	टिप्पण
1.	विश्रामपुर	बरमू	15	रांची	भाग
2.	बकबका	"	14	"	"

कुल क्षेत्र 780.00 एकड़ (लगभग)
या 315.65 हैक्टेयर (लगभग)

विश्रामपुर ग्राम में अर्जित प्लाट सं०:—

1, 2 (आंशिक), 3 से 17, 20, से 97, 98 (आंशिक), 99 से 223, 224 (आंशिक), 225, 226, 227 (आंशिक), 228 (आंशिक, 229, (आंशिक), 230 (आंशिक), 231 से 275, 276 (आंशिक), 277 (आंशिक), 278 से 292, 293 (आंशिक), 294 (आंशिक) 295 (आंशिक), 300 (आंशिक), 301 (आंशिक), 305 (आंशिक) 306 से 355, 356 (आंशिक), 357, 358 (आंशिक), 359 (आंशिक), 360, 361 (आंशिक), 362 (आंशिक), 366 (आंशिक), 616 और 617।

बकबका ग्राम में अर्जित प्लाट सं०

1 (आंशिक) और 7 (आंशिक)।

सीमा वर्णन

क—ख रेखा विश्रामपुर ग्राम के प्लाट सं० 2 और 356 से होकर जाती है (जो करकटा कोलियरी की पट्टाधृत सीमा के साथ सामान्य सीमा है)।

ख—ग रेखा विश्रामपुर ग्राम के प्लाट सं० 356, 98, 358, 359, 98, 361, 366, 362, 366, 305, 301, 293, 300 और 295 तथा बकबका ग्राम के प्लाट सं० 1 और 7 से होकर जाती है (जो के० डी० कोलियरी की पट्टाधृत सीमा के साथ-साथ सामान्य सीमा है)।

घ—ङ रेखा बकबका ग्राम के प्लाट सं० 7 और 1 तथा विश्रामपुर ग्राम के प्लाट सं० 294, 293, 277, 276, 230, 227, 224, 228 और 229 से होकर जाती है (जो डकारा-बकबका कोलियरी की पट्टाधृत सीमा के साथ-साथ सामान्य सीमा है)।

ङ०—च रेखा मेनाभुवा नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और तब दामोदर नदी से होकर विश्रामपुर और चुरी ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है (जो मानकी कोलियरी की पट्टाधृति के साथ सामान्य सीमा है)।

च—छ रेखा दामोदर नदी या देवनद नदी की केन्द्रीय रेखा के साथ-साथ जाती है (जो थाना बरमू, जिला रांची के विश्रामपुर और थाना टंडवा, जिला हजारीबाग के बन्टी, और थाना बरमू, जिला रांची के विश्रामपुर और थाना टंडवा जिला हजारीबाग के कुटकी ग्राम की सामान्य सीमा है)।

छ—क रेखा दामोदर नदी से होकर जाती है (जो विश्रामपुर और करकट ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा है)।

[सं० 19(1)/75-सी० एल०]

चन्द्रधर त्रिपाठी, निदेशक

(Department of Coal)

New Delhi, the 29th December, 1976

S.O. 170.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) S.O. No. 681 dated the 27th January, 1976, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification ;

And whereas the competent authority has, in pursuance of section 8 of the said Act, made his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 780.00 acres (approximately) or 315.65 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 780.00 acres (approximately) or 315.65 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto are hereby acquired ;

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ranchi (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

DAKARA BLOCK

(NORTH KARANPURA COALFIELD)

Drg. No. Rev/22/76

Dated 14-4-1976

(Showing lands acquired)

All Rights

Serial No.	village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Bishrampur	Burmu	15	Ranchi	Part	
2.	Bukbuka	,,	14	,,	,,	
		Total area 780.00 acres (approximately) or 315.65 hectares			,,	

Plot numbers acquired in village Bishrampur :—1, 2(part), 3 to 17, 20 to 97, 98(Part), 99 to 223, 224(Part), 225, 226 227(Part), 228(Part), 229(Part), 230(Part), 231 to 275, 276(Part), 277(Part), 278 to 292, 293(Part), 294(Part), 295(Part), 300(Part), 301(Part), 305(Part), 306 to 355, 356(Part), 357, 358(Part), 359(Part), 360, 361(Part), 362(Part), 366(Part), 616 and 617.

Plot number acquired in village Bukbuka :—1(Part) and 7(Part).

BOUNDARY DESCRIPTION

A-B line passes through plot numbers 2 & 356 of village Bishrampur (which forms common boundary with the lease hold boundary of Karkata Colliery).

B-C-D lines pass through plot numbers 356, 98, 358, 359, 98, 361, 366, 362, 366, 305, 301, 293, 300 & 295 of village Bishrampur and plot numbers 1 and 7 of village Bukbuka (which forms common boundary with the lease hold boundary of K. D. Colliery).

D-E line passes through plot numbers 7 & 1 of village Bukbuka and plot numbers 294, 293, 277, 276, 230, 227, 224, 228 & 229 of village Bishrampur (which forms common boundary with the lease hold boundary of Dakara-Bukbuka Colliery.

E-F line passes along the left bank of Sonabuba Nadi and then through Damodar River along the part common boundary of villages Bishrampur & Churi (which forms common boundary with the lease hold of Manki Colliery).

F-G line passes along the part Central line of Damodar River or Deonad Nadi (which forms common boundary of village Bishrampur of thana Burmu, Distt. Ranchi and Benti of thana Tandwa, Distt. Hazaribagh, Bihrampur of thana Burmu Distt. Ranchi and Kutki of thana Tandwa Distt. Hazaribagh).

G-A line passes through Damodar River (which forms part common boundary of villages Bishrampur and Karkata).

[No. 19(1)/75-CL]

C. D. TRIPATHI, Director

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1976

(पुरातत्व विज्ञान)

का० आ० 171.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है :—

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् दो मास के भीतर, उक्त प्राचीन स्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक प्राचीन का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले प्लाट की संख्या
1	2	3	4	5	6
बिहार	गया	राजस्व थाना सं० 358	ग्राम बकरौर पुलिस-थाना बोध गया परगना मेहरे अंचल बोध गया।	प्राचीन स्तूप और अन्य अवशेष जिसे उस स्थान पर सुजाता गढ़ कहा गया है।	पुनः उद्धृत स्थित रेखांक में यथा वर्णित सर्वेक्षण प्लाट सं० 363 364, 379, सर्वेक्षण प्लाट सं० 380; 371 और 379 के भाग और सर्वेक्षण प्लाट सं० 380 और 381

	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पण
	7	8	9	10
सर्वेक्षण प्लाट सं०	एकड़	डिसमिल	उत्तर :—सर्वेक्षण प्लाट सं० 382।	(1) सर्वेक्षण प्लाट सं० 363: बकरौर के त्रिवेणी। महतो पुत्र गनौरी महतो।
363		11	पूर्व :—सर्वेक्षण प्लाट सं० 349 नाला	(2) सर्वेक्षण प्लाट सं० 364 बकरौर के ननकू महतो पुत्र राम केशर महतो।

	7		8	9	10
364	0	17	दक्षिण :—सर्वेक्षण प्लाट सं० 361, 362, 365, 368 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 370, 371 और 379 और ग्राम के शेष। पश्चिम :—भाग सर्वेक्षण प्लाट सं० 384 ग्राम सड़क।	(3) सर्वेक्षण प्लाट सं० 369: बकरौर के सियाराम महतो पुत्र शंकर महतो। (4) सर्वेक्षण प्लाट संख्या 370: बकरौर के मुखलाल महतो पुत्र दुखी महतो। (5) सर्वेक्षण प्लाट सं० 371 : बकरौर के स्वर्गवासी जोगी महतो की विधवा पत्नी मंहगी। (6) सर्वेक्षण प्लाट संख्या 379: बकरौर के मुखलाल महतो पुत्र दुखी महतो। (7) सर्वेक्षण प्लाट संख्या 380: बकरौर के खेन महतो पुत्र बिगन महतो। (8) सर्वेक्षण प्लाट संख्या 381 :- बिहार सरकार।	
369	0	09			
370 (पा)	0	05			
371 (पा)	0	$03\frac{1}{4}$			
379 (पा)	0	$08\frac{1}{2}$			
380	0	37			
381	2	39			
	3-एकड़	$29\frac{3}{4}$			

[सं० 2/36/73-एम०]
एम० एस० देशपाण्डे, महानिदेशक

प्राचीन स्तूप और दुसरे खंडहरों का स्थल मानचित्र, स्थानीय रूप से जो सुजाता गढ़ नाम से प्रसिद्ध, बकरोर, जिला— गया

DEPARTMENT OF CULTURE

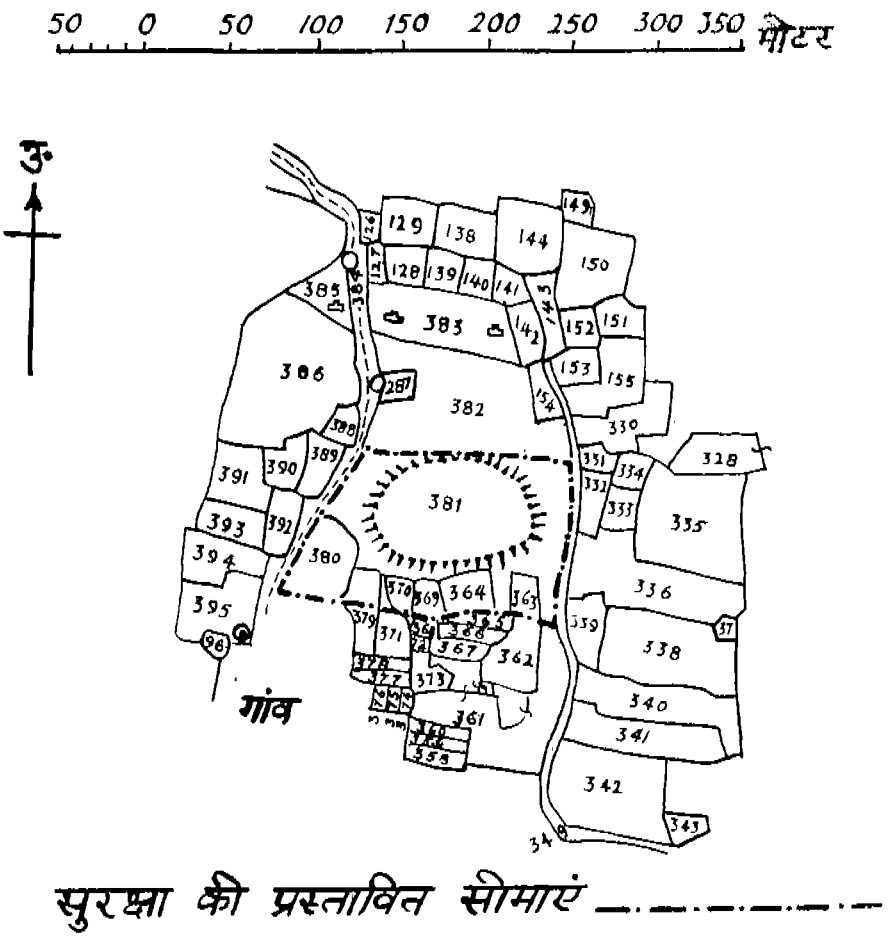

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 22nd November, 1976

(ARCHAEOLOGY)

S.O.171.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule attached hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said ancient monument will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	Dist.	Tehsil	Locality	Name of ancient Monument	Revenue Plot numbers to be included under Protection
1	2	3	4	5	6
Bihar	Gaya	Revenue Thana number 358	Village Bakraur P.S. Bodh Gaya Pargana Meher Anchal Bodh Gaya.	Ancient stupa and other remains locally known as Sujata Garh.	Survey plot numbers 363, 364, 369, parts of survey plot numbers 370, 371 & 379, Survey plot numbers 380 and 381 as shown in the site plan reproduced.

Area 7		Boundaries 8	Ownership 9	Remarks 10
Survey plot number	Ac. Dec.	North :—Survey plot number 382.	(1) Survey plot number 363:—Triveni Mahato S/o Ganauri Mahato of Bakraur.	
363	0—11	East :—Survey plot number 349, Nala.	(2) Survey plot number 364—Nanku Mahato S/o Ram Keshar Mahato of Bakraur.	
364	0—17	South :—Survey plot numbers 361, 362, 365, 368 and remaining portions of Survey plot numbers 370, 371 and 379 and village.	(3) Survey plot number 369:—Siya Ram Mahato, S/o Shankar Mahato of Bakraur.	
369	0—09	West:—Survey plot number 384 village Road.	(4) Survey plot number 370:—Mukhlal Mahato S/o Dukkhi Mahato of Bakraur.	
370 (P)	0—05		(5) Survey plot number 371:—Widow Mahngi W/o Late Jogu Mahato of Bakraur.	
371 (P)	0—03½		(6) Survey plot number 379:—Mukhlal Mahato S/o Dukkhi Mahato of Bakraur.	
379 (P)	0—08½		(7) Survey plot number 380:—Rewat Mahato S/o Viggan Mahato of Bakraur.	
380	0—37		(8) Survey plot number 381:—Government of Bihar.	
381	2—39			
	3—29½ acres			

[No. 2/36/73-M]

M. N. DESHPANDE, Director General Ex.Officio Jt. Secy.

SITE-PLAN OF ANCIENT STUPA AND OTHER REMAINS, LOCALLY KNOWN AS SUJATA GARH, BAKRAUR, DISTRICT GAYA

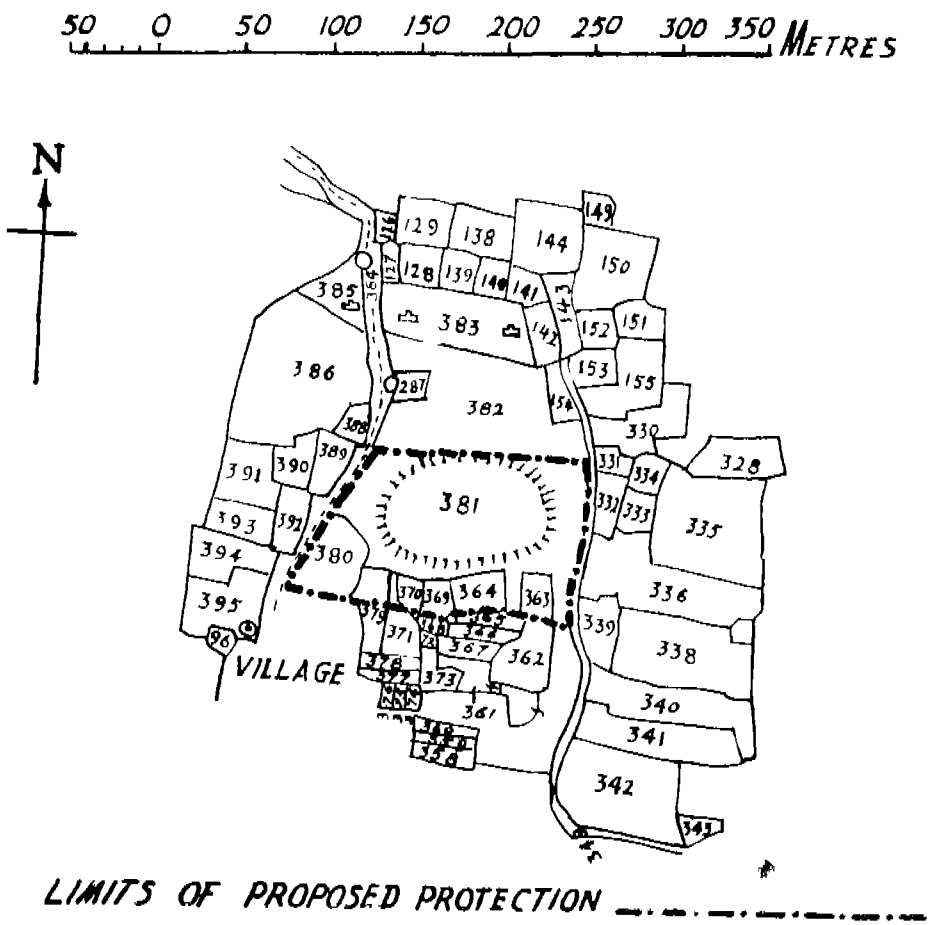

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1976

का० आ० 172:—केन्द्रीय सरकार, राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री भवानी प्रसन्न बनर्जी को श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त के स्थान पर राजघाट समाधि समिति का गैर-पद धारी सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मत्रालय की अधिसूचना स० 19/2/62-डब्ल्यू० 1, तारीख 22 अगस्त, 1962 मे निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात्।

उक्त अधिसूचना मे, क्रम स० 2 के सामने गैर पदधारी सदस्य से सबधित प्रविष्टियो मे "श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त, सचिव, गान्धी स्मारक निधि, दिल्ली" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"श्री भवानी प्रसन्न बनर्जी,

6 फीरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली"

[स० 25012/(3)/72—डब्ल्यू० 3]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 10th December, 1976

S.O. 172.—In exercise of the powers conferred by clause (C) of sub-section (1) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), the Central Government hereby nominates Shri Bhabani Prasanna Banerji as a non-official member of the Rajghat Samadhi Committee vice Shri Devendra Kumar Gupta and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962, namely :—

In the said notification, in the entries relating to non-official members, against serial No 2 for the words "Shri Devendra Kumar Gupta, Secretary, Gandhi Smarak Nidhi Delhi" the following shall be substituted, namely :—

"Shri Bhabani Prasanna Banerji,

6, Ferozeshah Road, New Delhi"

[No 25012(3)/72-W3]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1976

का० आ० 173—राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री कृष्ण कृपलानी, सदस्य राज्य सभा को स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह तालिब के स्थान पर राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप मे निर्वाचित किया गया है। अत अब केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मत्रालय की अधिसूचना स० 19/2/62 डब्ल्यू-1, तारीख 22 अगस्त, 1962 मे निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना मे, प्रविष्टि, "श्री निरजन सिंह तालिब" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"श्री कृष्ण कृपलानी"

[स० 25012 (3)/72—डब्ल्यू० 3]

आर० एल० अहलूवालिया, उप सचिव

New Delhi, the 13th December, 1976

S.O. 173—Whereas in pursuance of clause (d) of sub-section (1), of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), Shri Krishna Kriplani, a member of the Rajya Sabha, has been elected as a member of the Rajghat Samadhi Committee vice late Shri Niranjan Singh Talib Now, therefore, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No 19/2/62-WI dated the 22nd August, 1962 namely —

In the said notification, for the entry Shri Niranjan Singh Talib", the following entry shall be substituted namely —

"Shri Krishna Kriplani".

[No 25012(3)/72-W3]

R L AHLUWALIA, Dy Secy

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1976

का० आ० 174—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने भूमि एव विकास कार्यालय, निर्माण एव आवास गैर शहरी विकास मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आधीन नीचे दी गई अनुसूची मे निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया और अब यह भूमि डायरैक्टरेट शिक्षा दिल्ली प्रशासन दिल्ली स्थानान्तरित की जाती है।

अनुसूची

सैक्टर 12, आर० के० पुरम, नई दिल्ली मे स्थित भूखण्ड स० 1 साईट स० 109 को अधिसूचना स० एस० ओ० 4719 दिनांक 21-8-1975 के अनुसार एल० डी० ओ० प्लाट स० 2392 मे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लगभग 4 36 एकड भूमि के भाग को दिखाया गया है।

उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है —

उत्तर सरकारी भूमि जो स्टीफनसन कोलम्बस स्कूल को अलाट की गई है।

दक्षिण सडक

पूर्व — सरकारी भूमि जो पुलिस स्टेशन व उनके स्टाफ क्वार्टर के लिये अलाट की गई है।

पश्चिम —दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिये अलाट की गई भूमि।

[सं० एस० एण्ड एस० 33(12)/75 ए० एस० ओ० (1)]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 10th November, 1976

S.O 174.—In pursuance of the provisions of Sub-Section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the Schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing & Urban Development, Government of India, New Delhi for further transfer to the Directorate of Education, Delhi Administration, Delhi.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 4 36 Acres, situated in Sector-12, R. K Puram, bearing Site No 109 of Notification No S O 4719 dated 21-8-1975 under section 22 Sub-Section (i) of D D. Act, 1957 shown in the plan L D O No 2392

The above piece of land is bounded as follows —

North : Government land allotted to St Colombus School

South : Road.

East : Government land allotted for Police Station & for Staff Quarters.

West : Land allotted for Delhi Public School.

[No. S&S 33(12)/75-ASO(I)]

H. N FOTEDAR, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 175.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स पी० दावाराजुलु नायडु एण्ड सन्स, 24, नार्थ बीच रोड, मद्रास-600001 के प्रबंधतंत्र से संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एस० सिंगारवेलु, होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स पी० दावाराजुलू नायडु एण्ड सन्स, मद्रास के प्रबंधतंत्र का उपाबंध में उल्लिखित कर्मकारों को 10 मई, 1976 से निलम्बन में रखना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

उपाबन्ध

I. डाक पर्यवेक्षक :

1. श्री के० आर० वारादाराज
2. श्री पी० ए० जोठेश्वरन
3. श्री आर० थानिकाचल्लाम
4. श्री टी० नागाराजुलु
5. श्री आर० विक्टर
6. श्री एन० आर० कृष्णामूर्ति

II. गियर फोरमैन :

1. श्री डी० बालकृष्णन
2. श्री एम० एस० प्रकासम

III. डाक लिपिक :

1. श्री के० वीरा राघवन
2. श्री पी० थिरूवेन्गदम
3. श्री एस० श्री रामुलु
4. श्री पी० जेयाराम
5. श्री एम० रामामूर्ति
6. श्री टी० जे० चिट्टि बाबु
7. श्री एस० बी० रामचन्द्रन
8. श्री के० एल० सुब्रामानियम
9. श्री पी० एस० विनयगाम
10. श्री के० मुनुस्वामी

IV. गियर मजदूर :

1. श्री के० ओलगानाथन
2. श्री डी० पलानीस्वामी
3. श्री आर० वी० दोराईस्वामी
4. श्री के० पलानी
5. श्री जी० चिन्नाथाम्बी

[संख्या एल-33011(2)/76-डी० IV (ए)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd December, 1976

ORDER

S.O. 175.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. P. Davarajooloo Naidu and Son, 24, North Beach Road, Madras-600001 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs. P. Davarajooloo Naidu and Son, Madras are justified in placing the workmen mentioned in Annexure hereto under suspension with effect from 10th May, 1976 ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

ANNEXURE

I. DOCK SUPERVISORS :

1. Shri K. R. Varadaraj
2. Shri P. A. Jotheeswaran
3. Shri R. Thanickachallam
4. Shri T. Nagarajulu
5. Shri R. Victor
6. Shri N. R. Krishnamoorthy

II. GEAR FOREMEN :

1. Shri D. Balakrishnan
2. Shri M. S. Prakasam

III. DOCK CLERKS :

1. Shri K. Veeraraghavan
2. Shri P. Thiruvengadam
3. Shri S. Sri Ramulu
4. Shri P. Jeyaram
5. Shri M. Ramamurthy
6. Shri T. J. Chitti Babu
7. Shri S. B. Ramachandran
8. Shri K. L. Subramaniam
9. Shri P. S. Vinayagam
10. Shri K. Munuswamy

IV. GEAR MAZDOORS

1. Shri K. Olaganathan
2. Shri D. Palaniswamy
3. Shri R. V. Doraiswamy
4. Shri K. Palani
5. Shri G. Chinnathambi.

[No. L-33011(2)/76-D. IV(A)]

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 1976

आदेश

का० आ० 176.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कांटिनेन्टल शिपिंग एण्ड क्लियरिंग एजेन्सी मद्रास के प्रबंधतंत्र से संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगावेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स कांटिनेन्टल शिपिंग एण्ड क्लियरिंग एजेन्सी, मद्रास के प्रबंधतंत्र की, श्रीमति एस० ध्रुवकुमारी टंकक के नाम को कम्पनी की नामावली से काटने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष की हकदार है ?

[संख्या एल-33012(3)/76-डी० IV (ए)]

नंद लाल अधिकारी डेस्क,

New Delhi, the 4th December, 1976

ORDER

S.O. 176.—Whreas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists beween the employers in relation to the management of Messrs. Continental Shipping and Clearance Agency, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and Clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. Continental Shipping and Clearing Agency, Madras in striking off the name of Shrimati S. Dhuruvakumari, Typist, from the rolls of the Company is justified ? If not, to what relief is she entitled ?

[No. L-33012(3)/76-D. IV(A)]
NAND LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० आ० 177.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1970, तारीख 28 मई, 1968 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 2, बम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरणों में केन्द्रीय सरकार श्री जतीन्द्र नारायण को 20-12-1976 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० एस-11020/7/76/डी० 1 ए० (i)]

New Delhi, the 24th December, 1976

S.O. 177.—Whreas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court No. 2, Bombay, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1970 dated the 28th May, 1968 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby appoints Shri Jatinder Narain as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from the 20th December, 1976.

[No. S-11020/7/76/D.I(A)(i)]

का० आ० 178.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1971, तारीख 28, मई, 1968 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधो के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री जतीन्द्र नारायण को 20-12-1976 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० एस० 11020/7/76-डी०I ए० (ii)]

एल० के० नारायणन, डैस्क अधिकारी

S.O. 178.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 2 Bombay constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1971 dated the 28th May, 1968 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby appoints Shri Jatinder Narain, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from the 20th December, 1976.

[F. No. S. 11020/7/76/DIA(ii)]
L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1976

का० आ० 179 वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम 1972 के खण्ड 8 के उपखण्ड (2) के साथ पठित वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 (1963 का 37) की धारा (8) की उपधारा (5) के खण्ड (ज) के द्वितीय परन्तुक और चतुर्थ परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि—

(i) किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जिस की पालिसी 30 जून, 1974 को प्रवृत्त है, 30 सितम्बर, 1974, 31 दिसम्बर, 1974, 31 मार्च, 1975, 30 जून, 1975, 30 सितम्बर, 1975, 31 दिसम्बर 1975, 31 मार्च, 1976, 30 जून, 1976, 30 सितम्बर, 1976 और 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के बारे में सन्देह अग्रिम प्रीमियम की रकम शून्य होगी; और (ii) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही के

पश्चात्वर्ती किसी तिमाही के दौरान पहली बार नियोजक बनता है और जिसके लिए वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) स्कीम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार पालिसी लेना अपेक्षित है, अग्रिम प्रीमियम की रकम, केवल प्रथम तिमाही के लिए उसकी मजूरी बिल के प्रति एक सौ रुपये पर तीन पैसे होगी बशर्ते कि (न्यूनतम रकम आठ रुपये हो) जिसमें उसके लिए पालिसी लेना अपेक्षित है और पश्चात्वर्ती तिमाहियों के लिए अग्रिम प्रीमियम की रकम शून्य होगी।

[सं० एस० 19025/17/71—पैक]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

New Delhi, the 28th December, 1976

S.O. 179.—In exercise of the powers conferred by the second proviso and the fourth proviso to clause (h) of sub-section (5) of section 8 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963 (37 of 1963) read with sub- clause (2) of clause 8 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme, 1972, the Central Goverment hereby directs that—

(i) In the case of an employer having a policy in force on the 30th June, 1974, the amount of the advance premium payable in respect of the quarters ending on the 30th September, 1974, 31st December, 1974, 31st March 1975, 30th June, 1975, 30th September, 1975, 31st December, 1975, 31st March 1976, 30th June, 1976, 30th September, 1976, and 31st December, 1976 shall be nil, and

(ii) in the case of a person, who becomes an employer for the first time during any quarter subsequent to the quarter ending on the 30th June 1974 and is required to take out a policy of insurance in accordance with the provisions of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Scheme, 1972, the amount of advance premium shall be three paise per one hundred rupees of his wages bill subject to a minimum of eight rupees, for the first quarter only in which he is required to take out the policy and the amount of advance premium for the subsequent quarters shall be nil.

[No. S-19025/17/71/Fac.]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy

New Delhi, the 31st December, 1976

S.O. 180.—In pursuance of section 17 of the ndustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Cental Bank of India, Ambala Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th December, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGI. D.No. 63 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Chandigarh.

AND

Its workman as represented by CBIEU, Haryana Regd. Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H. L. Chhibber for the management.

S/Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra—for the workman.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/136/74-LRIII dated the 23rd April, 1975 with the following terms of reference:—

"Is the management of Central Bank of India, Ambala Division, justified in not designating Shri Vas Dev, Peon as Daftry with effect from the 15th March, 1974? If not, to what relief is the workman entitled?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L. Chhibber on behalf of the management and by S/shri R. K. Joshi & A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976

D. D. GUPTA, Presiding Officer

[No. L-12012/136/74-LR. III/D II. A.]

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 181.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन बैंक, मद्रास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारवेलु, बी० ए० बी० एल० होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इंडियन बैंक, मद्रास के प्रबन्धतन्त्र की बैंक के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों के बीच हुए तारीख 19-10-66 के द्विपक्षीय समझौते के पैरा 17.4 के उपबन्धों के अनुसार अपनी दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित शाखाओं में नियोजित अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को जूतों की परम्परागत पूर्ति को सीमित और कम करने का प्रस्ताव रखने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सख्या एल-12011/20/76-डी० 2 ए०]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1976

S.O. 181.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Bank, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec. 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the Presiding Officer of which shall be Shri T. N. Singaravelu, B.A.B.L. with Headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Indian Bank Madras in proposing to restrict and reduce the conventional supply of shoes to Subordinate Staff employed in their Delhi & New Delhi Branches in accordance with the provisions of para 17.4 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 between the Bank Managements and their workmen is justified? If not to what relief are the said workmen entitled.

[No. L-12011/20/76-D. II. A]
R. P. NARULA, Under Secy.

का० आ० 182.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3351 तारीख 8 सितम्बर, 1976 में निम्नलिखित शुद्धि करती है, अर्थात्.—

उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची के नीचे स्पष्टीकरण 5 में "80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत" पद के स्थान पर "70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत" पद रखे जाएंगे।

[सं० एस 32019/7/75/डब्ल्यू० सी० (न्यू० म०)]

टी० एस० शंकरन, अवर सचिव

S.O. 182.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following corrections in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3351, dated the 8th September, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th September, 1976 namely :—

In Explanation 5 below the Schedule annexed to the said notification for the expression "80 per cent and 70 per cent" the expression "70 per cent and 80 per cent" shall be substituted.

[No. S-32019/7/75-WC(MW)]
T. S. SANKARAN, Additional Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 183.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कार्बोरुण्डम यूनिवर्सल लिमिटेड, बाक्साईट माईन्स, डाकघर भाटिया (जिला जामनगर) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० यू० शाह होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या एक वर्ष में दस दिन की आकस्मिक छुट्टी और दस त्यौहारिक छुट्टियों की मंजूरी के लिए श्रमिकों की मांग न्यायोचित है? यदि हां तो सम्बन्धित कर्मकार कितनी आकस्मिक छुट्टी और त्यौहारिक छुट्टियों के हकदार है।

[संख्या एल-43011(2)/76-डी-4(बी)]

New Delhi, the 23rd November, 1976

ORDER

S.O. 183.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Carborundam Universal Limited, Bauxite Mines, Post Office Bhatia (District Jamnagar) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. U. Shah shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workers for grant of ten days casual leave and ten festival holidays in a year is justified ? If so, the quantum of casual leave and festival holidays the concerned workmen are entitled ?

[No. L-43011(2)/76-D-IV(B)]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 184.—मैसर्स चोगुले एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मोर्मुगाव बन्दरगाह (गोवा) के माईन एंड पेल्लेटाइजेशन प्लांट, पाले के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों सर्वश्री नारायण एम० नायक, फिटर, ए० एम० हामजा, रिगर, अब्दुल युसूफ, ग्रीजर जिस का प्रतिनिधित्व चोगुले कर्मचारी यूनियन करती है, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उक्त आवेदन में उपवर्णित और इस से उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित विषयों के बारे में उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स चौगुले एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मोर्मुगाव बन्दरगाह (गोवा) के माइन एंड पेल्लेटाइजेशन प्लांट, पाले के प्रबन्धतन्त्र की, सर्व श्री, नारायण एस० नायक, फिटर ए० एम० हामजा, रिगर, अब्दुल युसुफ, ग्रीजर को 20-11-1976 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल०-26013/5/76-डी०-4(बी०)]

New Delhi, the 9th December, 1976

ORDER

S.O. 184.—Whereas the employers in relation to the management of Mine and Palletisation Plant, Pale of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa) and their workmen Sarvashri Narayan S. Naik, Fitter, A. M. Hamza, Rigger, Abdul Yusuf, Greaser, represented by the Chowgule Employees' Union have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Bombay constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mine and Palletisation Plant, Pale of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa), in dismissing Sarvashri Naryan S. Naik, Fitter, A. M. Hamza, Rigger, Abdul Yusuf, Greaser, with effect from 20-11-1976 is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-26013(5)/76-D-IV(B)]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 185.—मैसर्स भानाखप माइका माइनिंग कम्पनी की भानाखप माइका माइन, डाकघर सिगेर (जिला नवादा) के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व अबरख मजदूर पंचायत, डाकघर झुमरीतलैया, जिला हजारीबाग करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 21 दिसम्बर 1976 को मिला था, प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : (1) श्री ओम प्रकाश तेबरीवाल, प्राधिकृत प्रतिनिधि भानाखप माइका माइनिंग कं० डाकघर सिगेर, जिला नवादा

(2) श्री शिव नारायण झा, एजेन्ट, भानाखप माइका माइन, डाकघर सिगर, जिला नवादा।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले (1) श्री भनेश्वर सिंह, महासचिव, अबरख मजदूर पंचायत, डाकघर झुमरीतलैया, जिला हजारीबाग।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एस० बी० सिंह, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हजारीबाग के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(i) विनिर्दिष्ट विवाद्यक विषय — क्या मैसर्स भानाखप माइका माइनिंग कं० के प्रबन्धतन्त्र द्वारा 30 सितम्बर, पहली अक्तूबर और 2 अक्तूबर, 1976 की मजदूरी का भुगतान न करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। (1) भानाखप माइका माइनिंग कं० डाकघर सिगेर, जिला नवादा। (2) अबरख मजदूर पंचायत, डाकघर झुमरितलैया, जिला हजारीबाग।

(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्वलित है या यदि कोई संघ प्रस्तुत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम। (1) अबरख मजदूर पंचायत।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या। 109

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या। 109

2 हम यह करार भी करते है कि मध्यस्थ के बहुमत विनिश्चय हम पर आबद्धकर होंगे।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

1. नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्ता० ओ० पी० तेबरीवाल, 22-11-1976 हस्ता० शिवनारायण झा, 22-11-76

2 कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्ता० भुनेश्वर सिंह, 22-11-76

साक्षी

(1) हस्ता० अपाठ्य
(2) हस्ता० अपाठ्य

[सं० एल०-28013(2)/76-डी० 4(बी०)]

New Delhi, the 29th December, 1976

ORDER

S.O. 185.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhanakhap Mica Mine of Messrs Bhanakhap Mica Mining Company, Post Office Singer (District Nawadah) and their workmen represented by the Abrakh Mazdoor Panchayat, Post Office Jhumritelaiya, District Hazaribagh;

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 21st December, 1976.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Name of the parties

Representing Employer : (1) Shri Omprakash Tebriwal, Authorised Representative Bhanakhap Mica Mining, Co., P.O. Singer, District Nawadah.

(2) Shri Shiv Narayan Jha, Agent, Bhanakhap Mica Mine, P.O. Singer, Distt. Nawadah.

Representing workmen : (1) Shri Bhaneshwar Singh, General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat, P.O. Jhumritelaiya, Distt. Hazaribagh.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri S. B. Singh, Asstt., Labour Commissioner (Central) Hazaribagh.

(i) Specific matter in dispute : Whether the management of M/s. Bhanakhap Mica Mining Co. is justified in not paying the wages for 30th Sept., 1st Oct. and 2nd Oct., 1976 ? If not to what relief the workmen are entitled?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved. (1) Bhanakhap Mica Mining Co., P.O. Singer, Distt. Nawadah.
(2) Abrakh Mazdoor Panchayat, P.O. Jhumritelaiya, Distt. Hazaribagh.

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union. If any representing the workmen or workman in question. (1) Abrakh Mazdoor Panchayat.

(iv) Total number of workmen employed in the Undertaking affected. 109

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 109

2 We further agree that the majority decisions of the arbitrator be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties

1. Representing the employer : Sd/- O. P. Tebriwal, 22-11-76
   : Sd/- Shiv Narayan Jha, 22-11-76

2. Representing workmen : Sd/- Bhaneshwar Singh, 22-11-76

Witness :

1. Sd/- Illegible
2. Sd/- Illegible

[No. L-28013(2)/76-D-IV(B)]

आदेश

का० आ० 186—मैसर्स भानाखप माइका माइनिंग कम्पनी की भानखप माइका माइन, डाक घर सिंगेर (जिला नवादा) के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिन का प्रतिनिधित्व अबरख मजदूर पंचायत, डाक घर झुमरी तिलैया, जिला हजारी बाग, करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 21 दिसम्बर, 1976 को मिला था, प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले (1) श्री ओम प्रकाश तेबरीवाल, प्राधिकृत प्रतिनिधि, भानाखप माइका माइनिंग कं०, डाक घर सिंगेर, जिला नवादा

(2) श्री शिव नारायण झा, एजेंट, भानाखप माइका माइनिंग कं०, जिला नवादा।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : (1) श्री भनेश्वर सिंह, महासचिव, अबरख मजदूर पंचायत, डाक घर झुमरी तिलैया, जिला हजारीबाग

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एस० बी० सिंह, सहायक श्रमायुक्त (के०) हजारीबाग के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :—

(1) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय : क्या भानाखप माइका माइनिंग कं० के प्रबन्धतन्त्र द्वारा कर्मकरों को 15 अगस्त, 1976, जो साप्ताहिक छुट्टी के दिन अर्थात् रविवार को पड़ता है, की मजदूरी का भुगतान न करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापनों या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। (1) भानाखप माइका माइनिंग कं०, डाक घर सिंगेर, जिला नवादा। (2) अबरख मजदूर पंचायत, डाकघर झुमरी तलैया, जिला हजारीबाग।

(3) कर्मकार का, यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्वलित है, या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम; (1) अबरख मजदूर पंचायत।

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या: 109

(5) विवाद द्वारा प्रभावित संख्या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्रायक्कलित संख्या : 109

2. हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ के बहुमत विनिश्चय हम पर आबद्धकर होंगे।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

1. नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्त० ओ०पी० तेबरीवाल, 22-11-76
हस्त० शिवनारायण झा, 22—11—76

2 कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले हस्त० भुनेश्वर सिंह 22—11—76

साक्षी:

(1) हस्त० अपाठ्य

(2) हस्त० अपाठ्य

[संख्या एल-28013/1/76-डी०-4(बी०)]

भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

ORDER

S.O. 186.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bhanakhap Mica Mine of Messrs Bhanakhap Mica Mining Company, Post Office Singer (District Nawadah) and their workmen represented by the Abrakh Mazdoor Panchayat, Post Office Jhumritelaiya, District Hazaribagh.

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 21st December, 1976.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Name of the Parties

Representing Employer : (1) Shri Omprakash Tebriwal, Authorised Representative, Bhanakhap Mica Mining Co., P.O. Singer, Distt. Nawadah.

(2) Shri Shiv Narayan Jha, Agent, Bhanakhap Mica Mining Co., P.O. Singer, Distt. Nawadah.

Representing Workmen : (1) Shri Bhaneshwar Singh, General Secretary, Abrakh Mazdoor Panchayat, P.O. Jhumritelaiya, Distt. Hazaribagh.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri S.B. Singh, Asstt. Labour Commissioner (C), Hazaribagh.

(i) Specified matter in dispute : Whether the management of Bhanakhap Mica Mining Co. is justified in not paying the wages to the workmen for 15th August, 1976 which falls on weekly holiday i.e. Sunday. If not to what relief the workmen are entitled ?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishments; or undertaking involved. : (1) Bhanakhap Mica Mining Co., P.O. Singer, Distt. Nawadah.
(2) Abrakh Mazdoor Panchayat, P.O. Jhumritelaiya, Distt., Hazaribagh.

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute on the name of the Union, if any representing the workman or workmen in question. (1) Abrakh Mazdoor Panchayat.

(iv) Total number of workmen employed in the Undertaking effected. 109

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. 109

2. We further agree that the majority decisions of the arbitrator be binding on us.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1976

आदेश

का० आ० 188 :—ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड, ब्यास प्राजैक्ट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार, श्री रतन लाल भारद्वाज के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 22 दिसम्बर, 1976 को मिला था, प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री मदन मोहन, कार्मिक अधिकारी, बी० सी० बी० ब्यास प्राजैक्ट, चण्डीगढ़

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री रतन लाल भारद्वाज, स्वयं श्रमिक, ग्राम धागांव, डाकघर पंजगेन, तेहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री वी० पी० गुप्ता, उप मुख्य श्रमायुक्त (के०), नई दिल्ली के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया गया है :

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय : "क्या प्रबन्धतन्त्र की ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड, ब्यास प्राजैक्ट, (पावर विंग) के भूतपूर्व कर्मचारी, श्री रतन लाल भारद्वाज की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। चीफ इंजीनियर (इलैक०) बी० सी० बी०, ब्यास प्राजैक्ट, एस० सी० ओ० 38, सैक्टर 26, चण्डीगढ़।

3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम — स्वयं कर्मकार

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : 1500

5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या : एक

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा। मध्यस्थ अपना पंचाट चार मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

ह०/- (मदन मोहन) कार्मिक अधिकारी, बी० सी०बी० ब्यास प्राजैक्ट, चण्डीगढ़

(रतन लाल भारद्वाज) कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाला,

साक्षी :

(1) ह्स्त० (योगेश कुमार)

(2) ह्स्त० (खुशी राम)

[संख्या एल० 42012(31)/76-डी० 2-बी०)]

हरबंस बहादुर, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st December, 1976

ORDER

S.O. 188.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Beas Construction Board, Beas Project and its workman Shri Rattan Lal Bhardwaj.

And, whereas the said employers and workman have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 22nd December, 1976.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)
BETWEEN :

Representing Employer—Shri Madan Mohan, Personnel Officer, B.C.B. Beas Project, Chandigarh.

Representing Workman—Shri Rattan Lal Bhardwaj, the workman himself Vill : Bagaun, P.O. Panjgain, Teh. Sadar Distt. Bilaspur (H.P.).

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial Dispute to the arbitration of Shri V. P. Gupta, Dy. Chief Labour Commissioner (C), New Delhi.

1. Specific matter in dispute :—

"Whether the action of the management in terminating the service of Shri Rattan Lal Bhardwaj, Ex-employee of Beas Construction Board, Beas Project (Power Wing) is justified ? If not to what relief the workman is entitled to."

2. Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved. — Chief Engineer, (Elect.), B.C.B. Beas Project S.C.O. 38, Sector 26, Chandigarh.

3. Name of the Union, if any, representing the workman in question. — Individual workman.

4. Total number of workmen employed in the undertaking. — 1500.

5. Estimated numbers of workmen effected or likely to be effected by the dispute. — One.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us. The arbitrator shall make his award within a period of four months or within such further time as is extended by mutual agreement by us in writing. In case

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing In case award is not made within the period aforementioned the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration

Signature of the parties

1 Representing the employer Sd/- O.P. Tebriwal, 22-11-76

Sd/- Shiv Narayan Jha, 22-11-76

2 Representing workmen : Sd/- Bhuneshwar Singh, 22-11-76

Witness .

1 Sd/- Illegible

2. Sd/- Illegible

[No L-28013/(1)76-D-IV-(B)]

BHUPENDRA NATH,
Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

का० आ० 187 —केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स, मद्रास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी टी० एन० सिंगारवेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इंडियन एयर लाइन्स, मद्रास के प्रबन्धतन्त्र की उनकी कैन्टीन में कार्य कर रहे निम्नलिखित 31 कर्मचारियों को उनके नियमित कर्मचारियों के बराबर स्टेटस, वेतन और भत्तों की श्रेणियों से वंचित करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं?

1 श्री जी० रामलिंगम
2 श्री एन० रघुनाथन
3 श्री के० एस० थिलाकन
4 श्री पी० राधाकृष्णन
5 श्री ए० सुब्बैयाह
6 श्री एम० पी० नायर
7 श्री वी० एस० कनकराज
8 श्री ए० माधवन
9 श्री सी० प्रभाकरण
10 श्री के० पंचाश्राम
11 श्री एस० मनुस्वामी
12 श्री आर० अरुमुगम
13 श्री पी० के० अय्याप्पन
14 श्री पी० के० सुधाकरण
15 श्री पी० वी० शान्मुघाम
16 श्री पी० के० कुंजन
17 श्री सी० चिन्नैयाह
18 श्री पी० कृष्णान्कुट्टी
19. श्री पी० के० बालन
20 श्री एम० के० पारथासरथी
21. श्री एम० के० अरविन्दाक्शन
22 श्री एम० मनि
23 श्री बी० जी० गुरुनाथन
24 श्री के० एस० एन० नायर
25 श्री एन० एलुमलाई
26. श्री वी० अरुमुघाम
27 श्री पी० वी० विजयान
28 श्री एम० नरसैयाह
29. श्री के० गोपिनाथन
30 श्री एस० येसु
31 श्री के० के० फ्रांसिज

[(संख्या एल-11011(8)/75-डी०-II(बी०)]

ORDER

New Delhi, the 8th December, 1976

S.O 187.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Airlines, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Indian Airlines, Madras in denying the status, grades of pay and allowances to the following Thirty-one employees working in their canteen on par with their regular employees, is justified ? If not, to what relief are these employees entitled ?

1 Shri G Ramalingam
2. Shri N. Raghunathan
3 Shri K. S. Thilakan
4 Shri P. Radhakrishnan
5. Shri A Subbiah
6 Shri M P Nair
7 Shri V. S Kanakaraj
8 Shri A. Madhavan
9 Shri C Prabhakaran
10. Shri K Panchaksharam
11. Shri S Munuswamy
12 Shri R Arumugam
13 Shri P K Ayyappan
14 Shri P K. Ayyappan
15. Shri P V Shanmugham
16 Shri P. K Kunjan
17 Shri C Chinniah
18 Shri P Krishnankutti
19. Shri P K Balan
20 Shri M K Parthasarathy
21 Shri M K Aravindakshan
22 Shri M Mani
23 Shri B G Gurunathan
24 Shri K S N Nair
25 Shri N Elumalai
26 Shri V Arumugham
27 Shri P V Vijavan
28 Shri M Narasiah
29 Shri K Gopinathan
30 Shri S Yesu
31. Shri K K. Francis.

[No L-11011(8)/75-D II (B)]

the award is not made within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/-	Sd/-
(Madan Mohan)	(Rattan Lal Bhardwaj)
Personnel Officer, B.C.B.	Representing workman.
Beas Project, Chandigarh.	

[No. L-42012(31)/76-D. II. B.]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer.

Witnesses :—

1. Sd/- (Yogesh Kumar)

2. Sd/- (Khushi Ram)

New Delhi, the 22nd December, 1976

S.O. 189.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Labour Court (Central) Guntur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Sitarampuram Limestone Mines of Kistna Cement Works of Associated Cement Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1976.

IN THE LABOUR COURT (CENTRAL) GUNTUR

Industrial Dispute No. 1 of 1976

This the 23rd day of October, 1976

BETWEEN :

Shri P. V. Unni Khannan — Workman.

AND

The Manager, Sitarampur Mines,
Piduguralla, Guntur District. — Management.

This dispute coming on for hearing on 23-10-1976 before me upon perusing the material papers on record and the memo filed by the workman the court passed the following :—

AWARD

The Government of India in its order dated 20-8-1976 referred the dispute between the workman Sri P. V. Unni Khannan and the management of Sitarampur Limestone Mines of Kistna Cement Works of Associated Cement Company Limited, of Piduguralla with the following issues :—

"Whether the action of the management of Kistna Cement Works of Associated Cement Company Limited, in terminating the services of Shri P. V. Unni Khannan, Watchman, employed in Sitarampuram Limestone Mines, Via Piduguralla, Palnad Taluk, Guntur District, as per their letter dated the 18th March, 1975, is justified. If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The claimant's case is briefly as follows :—

The claimant was working as a Watchman in the respondent management from 7-2-1974. One Wadood was the Security Officer and the immediate boss of the claimant. A few days after 7-2-1974, there was theft of a Radio in the quarters and the culprit happened to be the son of the above said Security Officer. The claimant took the owner of the Radio to the Manager at his request. An enquiry was held by the Manager regarding the theft, but the Security Officer managed to hush up the matter. Since then the Security Officer was highly prejudiced against the claimant. As a result the Security Officer issued a warning notice to the claimant on 15-6-1974 for an alleged trivial neglect of work, so that it would stand in the way of the claimant's confirmation. The Security Officer also managed to get the workman's probation extended by three months. Again on 22-10-1974 the management at the investigation of the Security Officer issued a charge sheet. An enquiry was conducted and the Manager wrongfully inflicted the punishment of (1) suspension for 2 days (2) the extension of probation for a further period of three months and (3) the transfer of the workman to Seetharampuram Mines. The workman joined the new post on 23-11-1974. He was due for confirmation on 7-2-1975. But on 20-2-1975 he was asked to appear before the Company's Medical Officer for a check up and he was declared to be fit by the Medical Officer verbally. But the management in connivance with the Security Officer Wadood issued a notice on 20-3-1975 terminating his services as a Watchman on medical grounds. The claimant who worked as Army motor driver from 1960 to 1973 was found medically fit even by the Army Medical Board. Subsequently he was found fit by the Medical Officers of the Madukkaral Cement Works, and the respondent-management while the claimant entered the service of the respondent-management. The claimant feels that the medical certificate now obtained by the management was fraudulently done at the instance of the Security Officer. Thus the order of termination is illegal and opposed to natural justice. Hence it is prayed that the order of termination may be set aside and the claimant may be reinstated with back wages.

3. It is true that the probation of the claimant was extended for a period of three months twice, as his work was not satisfactory. He was also warned once and suspended on another occasion. When the claimant was absenting himself often and was frequently visiting the dispensary, he was directed by the Agent of the Mines to appear before the company's Medical Officer for a check up. He was examined on 20-2-1975 by the Medical Officer and he submitted his report, which indicated that the workman was suffering from chronic disease of the skin which would prevent him from wearing socks and shoes, which are absolutely necessary for a Watchman. The report also indicated that the workman's right upper limb was operated earlier for dislocation, which prevents him from lifting heavy weights and engage himself in fire fighting, which he is expected to do. Hence his services were terminated. The management has the right to terminate the services of an employee as per the contract of service. The allegation that the Security Officer was responsible for his discharge is not correct. The allegation in the claimant statement that the workman was declared medically fit by the Medical Officer on 20-2-1975 is also denied. Hence there is no case for interfering with the order of the management and the dispute may be dismissed.

4 Even before any evidence was let in, in this dispute the claimant filed a memo in the court stating that he has no dispute with the respondent-management and that this court may pass a no dispute award. Hence in view of the memo filed by the workman, a no dispute award is passed and the reference is answered accordingly.

Dictated to the shorthand writer and transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of the Court, this the 23rd day of October, 1976.

G. S. ANAND,
JUDGE.

Appendix of Evidence.

No oral or documentary evidence adduced on either side.

G. S. ANAND, Judge.

[No. L-29011/8/76-D III B]

S O. 190.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of M/s Jaipur Udyog Ltd, Sawaimadhopur and their workman, which was received by the Central Government on the 16th December, 1976

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M P)

Case No C. G. I. T./LC(R)(5) of 1975

PARTIES

Employers in relation to the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workman represented through the Cement Mines Karamchari Sangh, Post Office Phalodi Quarry District Sawaimadhopur (Rajasthan)

APPEARANCE

For workman—Shri P C Pandey, Secretary of the Union

For employer—Shri Raman Lal Jain, Personnel Officer

INDUSTRY Cement DISTRICT Sawaimadhopur (Raj)
Dated November 15, 1976

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No L-29011/65/74-LR-IV Dated 10th February, 1975 The following question was referred to this Tribunal for adjudication —

"Whether the action of the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur in not promoting Shri Amar Singh, Assistant Tester, Phalodi Quarry, as Tester is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

After pleadings were completed and when the case reached the stage of evidence the parties came to terms and sent a Memorandum of Settlement dated 7-11-1976 by post duly signed by both the parties The management agreed to promote Shri Amar Singh from Grade 'C' to Grade 'B' of the prevalent Grades with effect from 22-7 1974 and it is further as after fixation in Grade 'B' his salary will be fixed by him one additional increment with effect from the aforesaid dated He will be designated as Tester' The Union has accepted that the claim of the workman has been fully settled It is also agreed between the parties thtat the Tribunal be requested to give its award in terms of the settlement

The reference is answered in terms of the settlement which shall form part of the Award Parties will bear their own costs

16-11-1976 S N JOHRI, Presiding Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT BETWEEN MANAGEMENT OF THE JAIPUR UDYOG LTD, SAWAIMADHOPUR AND THE WORKMAN REPRESENTED BY CEMENT MINES KARAMCHARI SANGH, PHALODI QUARRY IN THE MATTER OF INDUSTRIAL DISPUTES REGARDING SHRI AMAR SINGH, ASSTT TESTER

Whereas the Central Government, by an Order dated 10th February, 1975 referred to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, the following issue for adjudication —

"Whether the action of the management of Messrs Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur in not promoting Shri Amar Singh, Assistant Tester, Phalodi Quarry, as Tester is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

While the aforesaid case was pending before the said Hon'ble Industrial Tribunal, the matter was discussed between the parties and without prejudice to the contention of the parties, the following settlement was arrived at —

TERMS OF SETTLEMENT

(1) The management agrees to promote Shri Amar Singh from Grade 'C' to Grade B' of the prevalent grades with effect from 22-7-1974 After fixation in grade 'B' his salary will be fixed by grant of one additional increment with effect from the aforesaid date He will also be designated 'Tester'

(2) Shri Amar Singh and the applicant Union ie Cement Mines Karamchari Sangh agree that the claim on behalf of Shri Amar Singh has been fully settled on the basis of the above term (1) of this Agreement

(3) Both the parties agree that the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur should be requested to give its Award in terms of this settlement

Signed this 7th day of November 1976

For the Opposite Party
(The Jaipur Udyog Ltd)
1 Sd/- S L Bagda,
Superintendent (Quarries)
2 Sd/ Ved Leekha,
Sr Personnel Manager

For the applicant :
(Cement Mines Karamchari Sangh)
1 Sd/- Devi Lal Sandilya
General Secretary
2 Sd/ P C Pandey, Secy (Law)

WITNESS
Sd/-
1 Shri Nand Singh Hada 2 Sd/ Shri S L Sokhanda

Copy to Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur with the request to give its Award in Case No CGIT/LC(R)(5)/75 in terms of his Settlement between the parties

For Cement Mines Karamchair Sangh
Sd/- Devi Lal Sandilya,
General Secretary

For Jaipur Udyog Ltd,
Sd/- S D Bagda,
Superintendent (Q)

S N JOHRI, Presiding Officer

15-11-1976 [No L-29011/65/74-LRIV DIIIB]

S.O. 191.— In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Madras, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Kerala Minerals & Metals Ltd, Quilon and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1976

BEFORE THIRU T N SINGARAVELU, B A B L, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 29th day of November, 1976

Industrial Disputes No. 48 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between

the workmen and the Management of Kerala Minerals and Metals Limited, Quilon).

BETWEEN

The workmen represented by the General Secretary, Travancore Minerals Workers Union, Chavara Post Office, Quilon District, Kerala State.

AND

The Managing Director, Kerala Minerals and Metals Limited, Manailkulangara, Quilon, Post Office, Kerala State.

REFERENCE :

Order No. L-29011/33/75-D.O. III.B, dated 9-7-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Friday, the 19th day of November, 1976 upon persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N. Sreekantan Nair, M.P. President of the Union and of Thiru M. Ramachandran, for Menon and Menon, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration this Tribunal made the followirg Award :—

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen and the Management of Kerala Minerals and Metals Limited, Quilon and their workmen in respect of promotion of ore Thankappan Pillai. This reference has been made by the Government of India in its order No. L-29011/33/75-D.O. III.B, dated 9-7-1975 of the Ministry of Labour. The issue is as follows :

Whether the management of Kerala Minerals and Metals Limited was justified in removing with effect from 14th April, 1973 Shri Thankappan Pillai, Electrician from the adidtional charge of the duties of Mechanical Forman? If not, whether Shri Thankappan Pillai is eligible for confirmation to the post of Mechanical Foreman or is he entitled to any other benefit and from what date?

2. The Travancore Minerals Workers Union, Quilon has filed a claim statement as follows : Thiru Thankappan Pillai was working as Electrician in the Management Company which was then known as F.X.P. Minerals from 1958 to 1967. The Government of Kerala had taken over this concern and its is now incorporated as a Company under the name of Kerala Minerals and Metals Limited, Quilon. On 14-4-1967, the Government of Kerala, namely the management, put Thankappan in additional charge as Mechanical Foreman in a leave vacancy. There was some controversy with reference to the date of entry of Thankappan into service and the latter was claiming that he entered service in 1938 and therefore senior to the then incumbent. Thankappan was working as Mechanical Foreman from 20-4-1967 to 14-4-1973 when he was reverted to the post of Electrician. This reversion is unjustified and Thankappan should be reinstated as Mechanical Foreman with effect from 14-4-1973 with back wages.

3. The Management has filed a counter statement as follows. It is true that the Government of Kerala took over the Company from F.X.P. Minerals and was running it as a Departmental unit of the Government till the formation of the new Company with effect from 1-4-1972. During the period of direct Management by the State Government, all appointments and promotions were made under the orders of the Government. In 1965, a vacancy arose for the post of Mechanical Foreman and two candidates Thankappan and Albert made claim to that post. The Government ordered the appointment of Albert, as he was the seniormost technical hand. Later, the said Albert went on leave and the Government issued orders posting Thankappan in additional charge in the leave vacancy of Albert as a provisional arrangement. It was made clear in that order that it was only a provisional arrangement and that it will not entitle Thankappan to any preferential claim at the time of filling the permanent vacancy. Another claimant, one Pappoo, was aggrieved by the provisional order appointing Thankappan in additional charge and the said Pappoo filed a Writ Petition in the High Court of Kerala, which dismissed the application stating that the posting of Thankappan was only provisional and that it was not a substantive appointment. Meanwhile, there was agitation and strike by the workers of the Company in 1968 demanding revision of scales of pay, etc. The Government of Kerala appointed a Committee to go into that question in detail in consultation with all the Trade unions. The Committee submitted a detailed report and the Government in its turn had discussions on the recommendations of the Committee and entered into a long term agreement dated 19-1-1970 with the employees. The Agreement was comprehensive providing for recruitment and promotion for employees then in service of the Company. The Government also framed special rules for promotion and appointment in the Company with the consent of all parties.

4. The claims of Thankappan and Pappoo for the post of Mechanical Foreman were also referred to the above committee for consideration. The Committee found that both the candidates do not posses the requisite qualification, since Thankappan has passed only 5th Class with a Wiremens Certificate and Wiremen's Permit, and the other candidate Papoo was just a literate. The Committee recommended that the post should be filled up by direct recruitment of a qualified person. This report was discussed in detail at the Conference of the representatives of all the Unions and the Government issued final orders on 11-3-1970 directing the General Manager to take steps to recruit a fresh qualified person to the post of Mechanical Foreman and consequently the provisional arrangement putting Thankappan in additional charges was cancelled. The Union, in which Thankappan was a member, was also present at that meeting and they have also agreed to it. Therefore, it is not open to the Union to re-agitate that matter. Further, Thankappan filed a Writ Petition before the High Court of Kerala challenging the order of the Government and obtained an interim stay, by virtue of which he continued to hold additional charge of that post till 11-4-1973 when the Writ Petition was dismissed. Thereafter, the Company recruited a qualified person one Baby Kutty as Mechanical Foreman, but the latter has left the job and taken his appointment abroad. Therefore, the Management addressed the Kerala Public Service Commission to select and recommend a suitable candidate for the post of Mechanical Foreman and the Service Commission has submitted the name of the candidate. Meanwhile, this dispute has been referred to this Tribunal and therefore no orders of appointment have been passed. The allegations of bad faith, victimisation etc., put forward by the Union are all totally false and self-serving. The Petitioner Thankappan is only an Electrician of the Company and he has not the prescribed qualifications for the post of Mechanical Foreman. Further, there are seniors above Thankappan and therefore appointing him as Mechanical Foreman is out of question. The Management finally stated in its counter that the reference itself is illegal, because this question has been settled by the Agreement dated 19-1-1970 which is still in force. Therefore, the claim has to be dismissed with costs.

5. The Union is represented by its President Thiru N. Sreekantan Nair, M.P., while the Management is represented by learned counsel Thiru M. Ramachandran. Learned counsel for the Management contended at the outset that the reference itself is incompetent in as much as the very same issue has been the subject matter of the comprehensive Settlement between the parties Ex. W-10 dated 19-1-1970. Learned counsel pointed out from Ex. W-10 that all the Employees Union, seven in number, had a detailed and prolonged discussion with the Management, namely the Government of Kerala in the presence of the Secretary and Deputy Secretary to Government, Industries Department. Ex. W-10 is the printed booklet of the Conciliation Settlement and it is noticed therefrom that the question of appointment and promotion to the post of Mechanical Foreman was also considered. The Settlement dealing with "appointments" to the various classes and categories are mentioned at page 47 in Ex. M-10 (which is the same as Ex. W-10). It is clearly stated therein that the post of Mechanical Foreman (now in question) should be either by promotion from Class III of category (1) or by direct recruitment. At page 53 of the Settlement Ex. M-10, the qualifications for the Mechanical

Foreman are prescribed. In respect of promotion, it says that the promotee must hold a Diploma in Mechanical Engineering or an E.S.L.C. with Trade Test Certificate. For direct recruitment, the Settlement says that the appointee should have a Diploma in Mechanical Engineering with three years experience in a responsible position in a manufacturing concern.

6. Learned counsel for the Management urges that the worker in question Thankappan has studied only upto V Class with a Wireman's Permit and with a Wiremen's Certificate. It is conceded by the Union itself that the candidate does not possess the prescribed qualification for that post. It therefore follows that Thankappan is not eligible for promotion to the post of Mechanical Foreman for want of prescribed qualifications. Further, Thankappan was a member of Kerala Minerals Employees' Association at the time of Agreement in 1970 and Ex. M-10 shows that the said Association was a party to the Settlement. Therefore, the Union as well as its members, of whom Thankappan is one, are bound by the Settlement. He cannot now turn round and contend that by the virtue of his long experience he should be promoted as a Mechanical Foreman. This is contrary to the specific terms of the Agreement to which all the Unions were parties. Of course, Thankappan has conveniently resigned from that Union about two or three years ago and joined another Union, but that will not help him at all. The result is the dispute has been once for all settled by virtue of the Settlement Ex. M-10 and therefore this reference itself is incompetent and not maintainable.

7. In this connection, it may also be noticed from Ex. M-9 that the Rajkumar Committee had considered the demands of Thankappan for the post of Mechanical Foreman and the Committee has discussed all the aspects in detail in the presence of seven Labour Unions and the Management with the Deputy Secretary of Industries, Government of Kerala as the President. Clause (2) of Ex. M-9 deals with the appointment of Mechanical Foreman and it clearly reads that the recommendation of the Committee to recruit afresh a qualified person to the post of Mechanical Foreman was agreed to by all parties. As stated already, the Union which represented Thankappan also participated in that meeting and was a signatory to the same. It may also be added that the Committee framed special rules prescribing qualifications for the posts of the various categories and the Government approved the same by its G.O. Ex. M-11 dated 19-1-1970. The result is all the issues including the claim of Thankappan were settled under Ex. M-10 and there cannot be a further dispute in respect of the matter already settled by consent of all parties. Therefore, the reference itself is not valid and the claim of the Union has to be and is rejected.

8. Even on merits, the Union has no case. Admittedly, Thankappan does not possess the prescribed qualification for promotion and his educational qualification is only Vth Class, though by his long experience he has managed to acquire a Wiremen's Permit and Wiremen's Certificate. The main contention of the Union is that he was allowed to be in additional charge of that post for quite some time and therefore he may be promoted and appointed as a full member of that post. There is no substance in this argument after the Settlement under Ex. M-10 prescribing qualifications in the post of Mechanical Foreman. Just because Thankappan was in additional charge of that post for some time, he cannot claim any right to that post and this has been made clear even when he was provisionally posted in additional charge. Ex. M-3 is the order of Government of Kerala dated 7-12-67 putting Thankappan in additional charge of the duties of the Workshop Foreman in the leave vacancy of one Albert as a provisional arrangement. This Government Order further adds "that this arrangement will not entitle Thankappan to any provisional claim when the permanent vacancy of the post of Workshop Foreman is filled up". It is therefore clear that it was only a provisional arrangement and it will not help Thankappan.

9. That this posting of Thankappan in additional charge provisionally has been confirmed by the High Court of Kerala in the two Writ Petitions. Ex. M-8 is the Judgment of Kerala High Court in O.P. No. 5218 of 1967 holding that the appointment of Thankappan was only provisional. Ex. M-13 is the Judgement in O.P. No. 1375 of 1970 of Kerala High Court dated 8-2-1972, in which Thankappan himself was the Petitioner challenging appointment of one Albert. The High Court dismissed the petition observing that "it is clear misconception on his (Petitoner's) part, since he has not been promoted to that post. He was asked to take charge only as a provisional arrangement. It is made clear in Ex. P-1 itself that the arrangement would not entitle him to any preferential claims when the vacancy is filled up." It would appear from the Judgement that the Petitioner challenged the order and contended that the fixation of qualifications for that post was ultra vires of the Government. This argument too was rejected as untenable in as much as the Government of Kerala itself had taken over the Management. It would also appear that Thankappan obtained an interim stay from the High Court, which perhaps enabled him to hold on to that post in additional charge. But this will not at all help him in his claim to be appointed to that post under the rules.

10. It was then argued on behalf of the Union that some others have been appointed to some posts without prior qualifications, but that is all beside the point. After the comprehensive long term settlement in Ex. M-10 on 19-1-1970, all promotions and appointments are governed by the Settlement. An attempt was also made on behalf of the Union contending that Thankappan entered into service earlier to one Albert who was appointed as Mechanical Foreman and that the date of entry of Thankappan service in the registers is wrong. It is too late in the day to question the date of entry of service and in any event it is not relevant to this dispute. On the other hand, the Settlement Ex. M-10, which came ino existence at the instance of the Government after prolonged discussions with all the Unions, clearly states in Annexure VI that the date of entry into service of Thankappan was 10-7-1946. This has not been challenged by the Union which represented Thankappan at the time of the Settlement. Therefore, Thankappan is far junior to many others and he is also not qualified for the post of Mechanical Foreman. His claim is that he entered service in 1938 as against the entry of 1941 in his Service Book was never substantiated before any forum and therefore his entry into service is irrelevant for this dispute. The result of my discussion is that both on the question of law and on merits the Union has no case to support the claim of the workman for promotion. Consequently, the claim is rejected and an Award is passed in these terms with costs. Advocate's Fee Rs. 200/-.

Dated, this 29th day of November, 1976.

T. N. SINGARAVELU,

Presiding Officer.

WITNESSES EXAMINED

For workmen

W.W.1.—Thiru G. Raghavan Nair.

W.W.2.—Thiru N. Thangappan Pillai.

For Management

M.W.1—Thiru T. Shahul Hameed, Secretary.

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex. W-1/14-4-67.—Letter from the Government of Kerala to the Manager, F.X.P. Minerals, Chavara regarding claim by W.W.2 for the post of Foreman. (copy).

Ex. W-2/23-10-58.—Office order promoting W.W.2 as Electrician. (copy).

Ex. W-3/2-12-68.—Proceedings of the General Manager, F.X.P. Minerals, Chavara awarding Good Service Entry. (copy).

Ex. W-4/31-3-70.—Conduct and Character certificate issued to W.W.2 by the Works Manager, F.X.P. Minerals, Chavara. (copy).

Ex. W-5/10-12-71—Office order directing W.W.2 to hold additional charge of the Electrical Foreman during leave period. (copy).

Ex.W-6/5-7-61—Wireman's certificate of W.W.2. (copy).

Ex.W-7/ -8-75—Certificate of W.W 2 awarding Supervisors' Permit-Grade-B. (copy).

Ex.W-8—Copy of Paragraph 6 in Ex. P-2 before the Munsiff's Court, Karunagapally regarding entry into the service of the Company.

Ex.W-9/9-6-75—Printed Pamphlet in Malayalam issued by the Convenor, United Action Committee.

Ex.W-10/19-1-70—Memorandum of settlement between the Management of F.X.P. Minerals, Chawara and their workmen. (Printed copy).

Ex.W-11/12-8-75—Postal Acknowledgement.

Ex. W-12/ —Proceedings of the Conference held on 3-9-58 at the Government Secretariat before the Minister for Industries in respect of the Strike notice issued by the Minerals Company's Staff Association (copy).

Ex. W-13 —Service entry (10-7-1946) at page 65 in Annexure VI of Ex.W-10.

For Management

Ex.M-1/30-3-66—Government order stating that Thiru P. J. Albert Gensalvez will be appointed as Mechanical Foreman. (copy).

Ex.M-2/21-3-66—Letter from the Management to the Government giving particulars of services, scale of Pay and the qualification of the claimants for the post of Mechanical Foreman (copy)

Ex.M-3/7-12-67—Memo issued by the Management placing W.W.2 in additional charge of the duties of the workshop Foreman. (copy).

Ex.M-4/27-2-68— -do- (copy).

Ex.M-5/14-4-67—Same as Ex.W-1.

Ex.M-6/20-4-68—Memo requesting W.W.2 to take over charge of the duties of Workshop Foreman. (copy).

Ex.M-7/20-12-68—Government order on the charter of demands presented to the Government by the Labour Unions. (copy).

Ex.M-8/24-11-69—Judgement in O.P. No. 5218 of 1967 of the Kerala High Court (copy).

Ex.M-9—Minutes of meeting held on 9-1-70 between parties with the Deputy Secretary to Government. (copy).

Ex.M-10/19-1-70—Same as Ex.W-10.

Ex.M-11/19-1-70—Government order on the report of the Rajkumar Committee. (copy).

Ex.M-12/11-3-70—Government order in respect of individual issues. (copy).

Ex.M-13/8-2-72—Judgement in O.P. No 1375 of 1970 of the Kerala High Court. (copy).

Ex.M-14/4-1-73—Charter of demands made by the Union to the Management. (copy).

Ex. M-15/27-2-74—Memorandum of settlement between parties.

Ex.M-16/15-7-70—Government order giving clarification to Special rules for promotion and recruitment. (copy).

Ex.M-17/18-8-71—Letter from the Director of Training, Trivandrum to Thiru P.J. Motha. (copy).

Ex M-18/10-9-71—Government order according sanction to the General Manager to revert Tvl. C. K. Ramachandran Pillai and R. Radhakrishnan. (copy).

Ex.M-19/15-1-71—Office order promoting Thiru K. Pappoo as supervision. (copy).

Ex.M-20/4-8-72—Office order promoting Tvl. C. K. Ramachandran Pillai and R. Radhakrishnan as Supervisor. (copy).

T. N. SINGARAVELU, Industrial Tribunal.

Note : Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

[No. L-29011/33/75-DIIIB]

New Delhi, the 31st December, 1976

S.O. 192.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd December, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, AT CALCUTTA

Reference No. 10 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ningha Colliery, Ningha Sub Area of Messrs. Eastern Coal Fields Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Sri N. Das, Advocate, with Sri B. N. Lala, Asstt. C.P.O., Sri B. B. Prasad, Asstt. C.P.O., and Sri I. N. Srivastava, Sr. P.O.

On behalf of Workmen—Srj Lenin Roy, Advocate, with Miss Kabita Dutta, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

By Order No. L-19012/46/75/DIII(B), dated 25th February, 1976, the government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Ningha Colliery, Ningha Sub Area of Messrs. Eastern Coal Fields Limited, P.O. Kalipahari, District Burdwan and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the action of the management of Ningha Colliery of Eastern Coal Fields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, in not placing Shri Kripa Shankar Sharma, Clerk Grade III, in Clerical Grade II, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled and from what date?"

2. The parties field written statements; but when the Reference came up for hearing today they reported settlement of the dispute and requested the Tribunal to pass an Award in terms of the settlement.

3. The terms of settlement in writing are as follows :

"1. The management shall place Sri Kripa Sankar Sharma, the workman herein concerned in clerical grade II with effect from the date of the order of Reference i.e. 28th February, 1976.

2. The workmen agree that by this settlement the present dispute is finally settled and they shall not

claim any other relief whatsoever in the matter of the aforesaid dispute."

4. In the result, an Award is passed in favour of the workman, Shri Kripa Sankar Sharma, in terms of the above settlement.

Date, Calcutta, E. K. MOIDU, Presiding Officer
The 14th December 1976. [No. L-19012/46/75-D.III B]

V. VELAYUDHAN, Under Secy

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1977

का. आ. 193.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 10 जनवरी, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. अर्नाकुलम जिले के मुवात्तुपुजा तालुक में मनीद, मुलावूर, वेल्लूरकुन्नम, पिरावोम, मराडी, मुवात्तुपुजा, मजालूर, वालाकोम और अराकुजा के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

2. अर्नाकुलम जिले के कोठामंगलम तालुक में कोठामंगलम और एरामाल्लूर के राजस्व ग्राम ।

3. अर्नाकुलम जिले के कुन्नाथुनाड तालुक में किजहक्कम्बलम और एक्कारानाडनार्थ के राजस्व ग्राम ।

4. इडिक्की जिले के थोडुपुजा तालुक में थोडुपुजा राजस्व ग्राम ।

[सं. एस-38013/35/76-एच. आई]

एस. एस. सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 6th January, 1977

S.O. 193.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 6th January, 1977 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

1. The areas within the revenue villages of Maneed, Mulavoor, Velloorkunnam, Piravom, Marady, Muvattupuzha, Majalloor, Valakom and Arakuzha in Muvattupuzha Taluk in Ernakulam district.

2. The revenue villages of Kothamangalam and Eramalloor in Kothamangalam Taluk in Ernakulam district.

3. The revenue villages of Kizhakkambalam and Aikkaranad North in Kunnathunad Taluk in Ernakulam district.

4. The revenue village of Thodupuzha in Thodupuzha Taluk in Idikki district.

[No. S-38013/35/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd January, 1977

S.O. 194.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India Ambala Cantt and their workmen which was received by the Central Government on the 27-12-76.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID. No. 58 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Sector 17-B, Chandigarh;

AND

Its workman as represented by Central Bank of India Employees Union Haryana Regd. 146A, Lal Kurti, Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H. L. Chhibber—for the management
S/Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra—for the workman

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/109/74-LR III-D. II(A) dated the 10th February, 1975 with the following terms of reference.—

"Whether the action of the management of the Central Bank of India in denying Shri K. P. Sirpal, Clerk at the Ambala Cantonment Branch of the Bank the right to exercise his option for the post of Special Assistant on promotion is legal and justified? If not, to what relief is the workmen entitled?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L. Chhibber on behalf of the management and by S/Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976.

D. D. GUPTA, Presiding Officer
[F. No. L-12012/109/74-LR.III/D.II A]

New Delhi, the 4th January, 1976

S.O. 195.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-12-76.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID. No. 72 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Sector 17-B Chandigarh.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana Regd. 146A, Lal Kurti, Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H L. Chhibber—for the management.

Shri R. K. Joshi & Shri A. L. Chopra—for the workman

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/115/74-I.R. III dated the 25th February, 1975 with the following terms of reference —

Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in denying confirmation to Shri J. L. Chopra formerly clerk, Central Bank of India, Ambala City Branch with effect from 20th August, 1962 is legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L Chhibber on behalf of the management and by Shri R. K. Joshi & Shri A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976.

[F. No. 12012/115/74-LR. III/D.II.A]

D. D. GUPTA, Presiding Officer

S.O. 196.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispues Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-12-76.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID No. 73 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Chandigarh.

AND

Its workman as represented by Central Bank of India Employees Union Haryana (Regd), 146-A, Lal Kurti, Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H. L Chibber.—for the management

S/Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra—for the workman.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/81/75/DII/A dated the 12th August, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Chandigarh in denying promotion to Shri Kartar Singh, Daftri-cum-Peon, Adelat Bazar, Patiala of the said Bank as clerk is an act of discrimination and unfair labour practice ? If so to what relief is the workman entitled ?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L Chibber on behalf of the management and by Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976.

[F. No. L-12012/81/75-D. II. A]

D. D. GUPTA, Presiding Officer

S.O. 197.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th Dec., 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID No. 33 of 1975

BETWEEN

The management of Central Bank of India through their Zonal Manager, Zonal Office, Parliament Street, New Delhi.

AND

Their workmen as represented by the Central Bank Employees Union, Central Bank Bldg., Chandni Chowk, Delhi.

PRESENT :

None—for the management.

None—for the workmen.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/53/75-D. II/A dated the 9th July, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the Central Bank of India New Delhi, is justified in forcing Shri Krishna Nand Misra, Head Peon, to retire from service with effect from the 6th October, 1974 by not altering his date of birth on the basis of the proof produced by him ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The applicant averred that he was appointed as a member of the subordinate staff in the service of the respondent and was subsequently designated as a Jamedar (head peon) at Kashmere Gate Branch of the Bank. It was stated that the management forcibly retired him from service with effect from 6-10-74 by altering his date of birth. It was pleaded that the action of the management was unjustified in as much as the management had changed the dates of birth of several members of the subordinate staff. It was, therefore, prayed that he should be deemed to be continuing in service from 6-10-74 onwards and should be allowed to continue in service till 20-2-1980 and he should be treated on duty with full pay and allowances and all other monetary and non-monetary benefits after 6-10-74 and re-instated on duty with continuity of service.

3. The management raised a preliminary objection that there was no proper and valid demand raised by the workman/union. On merits it was stated that the date of birth of Shri Misra as recorded in the service, leave record register and provident fund records of the Bank is 7-10-1914. It was further stated that the workman had been rightly and lawfully retired from the service of the Bank with effect from 6-10-74 on the basis of the records of the Bank and the workman had attained the age of 60 years on 6-10-74. It was, therefore, prayed that the workman was not entitled to any relief

4 The workman filed a rejoinder and re-iterated his claim.

5. On these pleadings the following issues were framed :—

Issues :

1. Whether the dispute has been validly and properly espoused ; if not, its effect.

2. Whether a proper and valid notice of demand was served by the workman on the management raising an industrial dispute.

3. As in the term of reference.

ISSUE NO 1

6. The burden of proof of this issue was on the management. If, however, failed to prove or adduce any evidence in support of it. The issue is, therefore, decided against the management.

ISSUE NO : 2 and 3

7. The burden of proof of these issues was on the workman. He, however, failed to prove that there was a valid and proper demand notice served on the management. He, even, did not adduce any evidence in support of these issues. The issues are, therefore, decided against the workman.

8. The total result is that there being no proper and valid notice of demand the reference is incompetent. An award is made accordingly.

10th November, 1976

[F. No. L-12012/53/75-D. II. A]

D. D. GUPTA, Presiding Officer

S.O. 198.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-12-76.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID. No. 81 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Sector 17-B, Chandigarh.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana (Regd.), 146-A, Lal Kurti, Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H. L Chhibber—for the management.

S/Shri R. K. Joshi & A. L. Chopra—for the workman.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/35/75/DII-A dated the 29th May, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the action of the Central Bank of India, Chandigarh in not informing Shri G. S. Gulati, Stenographer-cum-clerk about the All India Service Test held on the 2nd December, 1974, was a bonafide commission or an act of victimisation and unfair labour practice ? In either case to what relief is Shri Gulati entitled ?"

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L. Chhibbr on behalf of the management and by S/shri R. K. Joshi & A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976.

D. D. GUPTA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/35/75-D. II. A]

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 6th January, 1977

S.O. 199.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Central Bank of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th December, 1976.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID No. 64 of 1976

BETWEEN

The Zonal Manager, Central Bank of India, Sector-17B, Chandigarh.

AND

Its workman as represented by CBIEU Haryana Regd. 146A, Lal Kurti Ambala Cantt.

PRESENT :

Shri H. L. Chhibber for the management.

S/Shri H. K. Joshi & A. L. Chopra for the workman.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/106/73/LRIII dated the 11th September, 1974 with the following terms of reference :—

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Chandigarh in not treating Shri C. L. Chopra of Jagraon branch of the Bank as Head Cashier with effect from the 25th January, 1969 is an act of discrimination and unfair labour practice ? If so, to what relief is he entitled ?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri H. L. Chhibber on behalf of the management and by S/shri R. K. Joshi & A. L. Chopra on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement and prayed that a no dispute award might be passed in this case. In view of this, I have no alternative but to pass a no dispute award which is passed accordingly.

4th December, 1976

[F. No. L-12012/106/73-LR.III/D.II.A]

D. D. GUPTA, Prisding Officer

S.O. 200.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-1976.

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS
(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 14th December, 1976

Industrial Dispute No. 87 of 1975

(In the matter of the Industrial Dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of The Bank of Madurai Limited, Madurai).

BETWEEN

The workmen represented by
The General Secretary,
Bank of Madurai Employees Union,
135, Moore Street, Madras-1.

AND

The Chairman, The Bank of Madurai Limited, 33-North Chithrai Street, Madurai.

REFERENCE :

Order No. L. 12011/30/75/DII/A, dated 15-12-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute having advanced to this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiru R. Jamal Nazeem for Thiruvalargal Aiyar and Dolia, Advocates for the workmen and of Thiru N. R. Narayanaswami advocate for the Management and the counsel for the workmen having filed a memorandum for withdrawing the dispute and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India, by their Order No. L. 12011/30/75/DII/A, dated 15-12-1975 of the Ministry of Labour, referred an Industrial Dispute between the employers, the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen in respect of the following matters :

1. Whether the functioning of the Chit Fund Department of the Bank of Madurai Limited forms part of the normal business of the said Bank and, if so, whether the Clerks employed in that Department are entitled to get the regular scale of pay and allowances and other benefits admissible to the regular employees of that bank ?

2. Whether the personal peons/personal servants engaged by some of the Branch Officer of the Bank of Madurai Limited, Madurai and by some Officers at the Central Office of the said Bank at Madurai were utilised for doing normal attender's work in the Bank and, if they were so utilised, to what relief, if any, are they entitled and from what date ?

2. The parties were served with summons.

3. The workmen, represented by the Joint Secretary, Bank of Madurai Employees Union, Madras filed a claim statement on 25-3-1976 puttingforth the claims of the workmen. The Bank filed counter statement on 11-10-1976 repudiating the claims of the workmen.

4. Parties took several adjournments, to settle dispute.

5. After several adjournments when the dispute was taken up today, learned counsel for the workmen presented a memorandum stating that the dispute has been settled between the parties and that the workmen have withdrawn the dispute pending before this Tribunal.

6. I have perused the memorandum and recorded the same The result is the dispute is withdrawn by the workmen as not pressed. Each party will bear his or its cost.

7. An award is passed accordingly.

Dated, this 14th day of December, 1976.

[No. L-12011/30/75-D.II.A]

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

S.O. 201.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-76.

BEFORE THIRU T. N SINGARAVELU, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS
(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 14th day of December, 1976.

Industrial Dispute No. 51 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Bank of Madurai Limited, Madurai.)

BETWEEN

The workmen represented by the Secretary, Bank of Madurai Employees' Union, 135 Moore Street, Madras-1.

AND

The Chairman, the Bank of Madurai (Limited), Central Office, 33-North Chitrai Street, Madurai-1.

REFERENCE :

Order No. L. 12011/14/75/DII/A, dated 21-7-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiru R. Jamal Naseem for Thiruvalargal Aiyar and Dolia, Advocates for the workmen and of Thiru N. R. Narayanaswami, advocate for the Management and the counsel for the Union having filed a memorandum for withdrawing the dispute and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India, by their Order No. L. 12011/14/75/DII/A, dated 21-7-1975 of the Ministry of Labour, referred an Industrial Dispute between the employers, the Bank of Madurai Limited, Central Office, Madurai and their workmen in respect of the following matters :

Whether the action of the Management of the Bank of Madurai Limited in granting Cash awards to some of their workmen is discriminatory or is unfair Labour practice or both ? If so, to what reliefs are the other workmen entitled ?

2 The parties were served with summons The workmen, represented by the Joint Secretary, Bank of Madura Employees' Union, Madras filed a claim statement on 16-9-1975 puttingforth the claims of the workmen. The Bank filed counter statement on 15-10-1975 repudiating the claims of the workmen.

3 Parties took several adjournments, to settle the disute.

4. After several adjournments, when the dispute was taken up today, learned counsel for the workmen presented a memorandum stating that the dispute has been settled between the parties and that the workmen have withdrawn the dispute pending before this Tribunal.

5. I have perused the memorandum and recorded the same.

6. The result is the dispute is withdrawn by the workmen as not pressed. Each party will bear his or its cost.

7 An award is passed accordingly.

Dated this 14th day of December, 1976

[No. L-12011/14/75-DII/A]

T. N SINGARAVELU Presiding Officer

S.O. 202.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-76.

BEFORE THIRU T. N SINGARAVELU, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 14th day of December, 1976.

Industrial Dispute No. 52 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Bank of Madurai Limited, Madurai)

BETWEEN

The workmen represented by the Joint Secretary, the Bank of Madurai Employees' Union, 135-Moore Street, Madras.

Vs.

The Chairman, the Bank of Madurai Limited, 33-North Chitrai Street, Madurai-1.

REFERENCE:

Order No. L. 12012/68/75/DII/A, dated 22-7-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiru R. Jamal Nazeem for Thiruvalargal Aiyar and Dolia and A. L. Somayaji, Advocates for the workmen and of Thiru M. R. Narayanaswami, advocate for the Management and the counsel for the Union having filed a memo for withdrawing the dispute and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India, by their Order No. L. 12012/68/75/DII/A, dated 22-7-1975 of the Ministry of Labour, referred an Industrial Dispute between the employers, the Bank of Madura Limited, Madurai and their workmen in respect of the following matters:

Whether the management of the Bank of Madurai Limited is justified in not allowing Shri A. R. Kalayappan, to work as Cashier at the Coimbatore Branch of the Bank and in not paying him Cashier's allowance with effect from the 16th January, 1975? If not, to what relief is the said workman entitled?

2 The parties were served with summons.

3. The workmen, represented by the Joint Secretary, The Bank of Madura Employees Union, Madras filed a claim statement on 6-9-1975 putting forth the claims of the workmen. The Bank filed counter statement on 28-11-1975 repudiating the claims of the workmen

4. Parties took several adjournments, to settle the dispute.

5 After several adjournments, when the dispute was taken up today, learned counsel for the workmen presented a memorandum stating that the dispute has been settled between the parties and that the workmen have withdrawn the dispute pending before this Tribunal.

6 I have perused the memorandum and recorded the same. The result is the dispute is withdrawn by the workmen as not pressed Each party will bear his or its cost.

7. An award is passed accordingly.

Dated, this 14th day of December, 1976.

[No. L-12012/68/75-DIIA.]

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

S.O. 203.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Madurai Limited, Madurai and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-76.

BEFORE THIRU T. N SINGARAVELU, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 14th day of December, 1976.

Industrial Dispute No. 28 of 1975

(In the matter of the dispute between the workmen and the Management of The Bank of Madurai Limited, Madurai for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947).

BETWEEN

The workmen represented by the General Secretary, Tamil Nadu Bank Employee's Federation, 135, Moore Street, Madras-1.

AND

The Chairman, Bank of Madurai Limited, Central Office, Madurai (Tamil Nadu).

REFERENCE:

Order No L-12025/32/73-LR.III, dated 24-3-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing of Thiru R. Jamal Nazeem for Thiruvalargal Aiyar and Dolia, Advocates for the workmen and of Thiruvalargal M. R. Narayanaswami and S Jayaraman, advocates for the Management and the counsel for the Union having filed a memorandum for withdrawing the dispute and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India, by their Order No. L. 12025/32/73-LR.III, dated 24-3-1975 of the Ministry of Labour, referred an Industrial Dispute between the employers, the Bank of Madurai Limited, Central Office, Madurai and their workmen in respect of the following matters:

1. Whether the suspension of Shri S Sundaram, an employee of the Bank of Madurai Limited and Joint Secretary of the Bank of Madurai Employees Union

with effect from 30th September, 1972 and his subsequent dismissal from service from 11th April, 1973 by the management of Bank of Madurai Limited were acts of victimisation. If so, to what relief Shri Sundaram is entitled and from what date.

2. Whether the suspension of Shri G Srinivasan, an attendant of the Bank of Madurai Limited and an active member of the Bank of Madurai Employees Union from 3rd November, 1972 and his subsequent dismissal from service by the Management of Bank of Madurai Limited were acts of victimisation. If so, to what relief Shri Srinivasan is entitled to and from what date.

2. The parties were served with summons.

3. The workmen, represented by the General Secretary, Tamil Nadu Bank Employees Federation filed a claim statement on 18-8-1975 putting-forth the claims of the workmen. The Bank filed counter statement on 25-10-1975 repudiating the claims of the workmen.

4. Parties took several adjournments to settle the dispute.

5. After several adjournments, when the dispute was taken up today, learned counsel for the workmen presented a memorandum stating that the dispute has been settled between the parties and that the workmen have withdrawn the dispute pending before this Tribunal.

6. I have perused the memorandum and recorded the same. The result is the dispute is withdrawn by the workmen as not pressed. Each party will bear his or its cost.

7. An award is passed accordingly.

Dated, this 14th day of December, 1976.

[No. F. 12025/32/73-LRIII/DIIA]

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

S.O. 204.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to he management of Punjab Naational Bank, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-12-76.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 15 of 1976

PARTIES :

Employers in relation to the Punjab National Bank,

AND

Their workman.

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Sri G. S. Varma. Senior Personel Officer.

On behalf of Workman.—Shri D. L. Sen Gupta, Sr. Advocate, with Shri H. L. Roy, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

AWARD

By Order No. L-12012/152/75/DII/A, dated the 28th February, 1976, the Government of India, Ministry of Labour, referred an industrial dispute existing between the management of the Punjab National Bank and its alleged employee for adjudication. The reference reads :

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank is justified in terminating the services of Shri Golam Dastagir, Driver of the said Bank with effect from the 27th May, 1975 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the workman Sri Golam Dastagir was that he had in the service of the Punjab National Bank, Calcutta, for more than two and half years as a driver of the Jeep WMA 9264 drawing a monthly salary of Rs. 200; that on 27-5-75 he went on 20 days' leave on receipt of a telegram that his wife was seriously ill; that after availing of the leave he reported for duty on 16th June, 1975 but he was denied the job which he was doing eversince he joined the service. The workman was reported to have sent a notice, Ext. W-3 dated 23-6-75 demanding the Bank for restoration of his job but the bank did not take any step. There was an attempt at conciliation but due to the non-cooperation of the bank the conciliation failed with the result the reference has been made to this Tribunal.

3. The Bank denied the allegation of the workman. They stated that the workman concerned has never been in the employment of the bank. On the other hand, he was said to be employed by one Sri K. P. Sharma who was the Area Manager of the Bank and that he was employed by him as his private driver to drive the Bank's jeep. They denied that the workman was ever appointed by them as their driver. However, they admitted that a sum of Rs. 200/- was being paid to Sri K. P. Sharma as salary to be paid to his driver every month on the basis of a circular letter dated 10-3-73. On these grounds they state that the workman is not entitled to any relief.

4. The question for consideration is whether the workman Sri Golam Dastagir was an employee of the bank or that he was an employee of Sri K. P. Sharma, Area Manager of the Bank. In support of the workman's case the workman himself was examined as WW-1 and Sri K. P. Sharma was examained as MW-1. It is nobody's case that any letter of appointment was given to the workman when he entered the service as a driver. The fact that the jeep in question was owned and maintained by the Bank had not been disputed. The Bank had to meet the day to day running cost of the jeep as well as repairs and all other connected expenses on account of the running of the jeep. Once the driver was fined for violating the traffic rules and the fine was alleged to be paid by the Bank. That is the evidence of WW-1 and that evidence has not been controverted. Ext. W-1 is the fine receipt dated 12-7-73. Exts. W-2 series are the petrol bills and repair charge bills in respect of the jeep in question. Payment on those receipts had been made by the Bank.

5. There is evidence that Sri K. P. Sharma was paid a sum of Rs. 200/- per mensem by cheque at the instance of the bank and that Sri Sharma endorsed the same cheque to Sri Dastagir towards his monthly salary. He used to encash the cheque at the bank counter and receive his salary every month. It is also relevant in this regard to refer to the evidence of Shri Sharma himself. He said even in his examination-in-chief, "As per Bank perquisite the Bank was to provide me with a driver but as the bank could not provide as such I had engaged a driver personally as per my own choice....." This statement of MW-1 was an indication that bank was obliged to give Sri Sharma a driver. If that be so, the bank alone could have employed Sri Dastagir as the driver of the jeep. The evidence of WW-1 is that he was introduced to the General Manager and that he was appointed as the driver of the jeep at his instance. It is also in evidence that Sri Dastagir was employed as the driver of the General Manager for sometime before he went on leave. The payment of salary through cheque directly to Shri Sharma and he in his turn to the driver every month was an indication that the bank had been paying the salary of the workman as its employee. The jeep had been in use for the purpose of the bank. It had to visit all the branch offices of the bank in the States of West Bengal, Orissa and Assam. A log book was maintained as to the number of trips which the jeep had taken in the course of its use but that log book was not produced by the management. WW-1 stated that if that log book was produced it would indicate that the jeep was beng used not only by Sri K. P. Sharma but also by other officers of the bank as and when required. The driver had also sent Ext. W-3 notice to the bank but they never cared to send a reply to this notice. The evidence of WW-1 together with other circumstances in the case makes it abundantly clear that Sri Dastagir was employed at the bank, that he was sent away from service after his return from leave. Ext. W-3 indicated that he had been on leave from 27th May, 1975 to 16th June, 1975.

MW-1 did not dispute the fact that he went on leave The termination of service of WW 1 in the circumstances of the case was unjustified On an analysis of the evidence in the case and other circumstances, I am of opinion that it has been established beyond dispute that Sri Dastagir was employed by the bank and that he had beer a bank employee as its accredited driver of the jeep referred to above

6 An attempt was made however to show that there was a general circular fixing the remuneration to be paid to Shri K P Sharma towards meeting the cost of driver's allowance That circular is said to be Ext M 1, but no attempt was made to produce the original of Ext M-1 or to prove the authenticity of the recital made in it In the absence of valid evidence the authenticity in words of mouth by MW-1 that allowance was based upon a circular could not be accepted The fact that the driver had been paid his salary by a cheque through MW-1 was a clinching circumstance to show that the bank was paying the driver's salary every month and that he had been treated as their driver The conclusion is therefore that Sri Dastagir is a driver-employee of the Bank and he shall be treated in future as such with regard to his remuneration and other amenities

7 It has to be held that the workman concerned will draw salary at the rate of Rs 200 per month from 17th June, 1975 upto the date of his re-employment towards back wages and thereafter the pay and other remuneration due to the workman shall be fixed by the bank in accordance with the bank rules

8 In the result the reference is answered in favour of the workmar Sri Golam Dasagir holding that the management of Punjab National Bank is not justified in terminating the services of Shri Golam Dastagir He shall be reinstated as a driver of the jeep which is still under the control and management of the bank He shall be paid the back wages at the rate of Rs 200/- per month with effect from 17th June, 1975 The bank shall fix his future remuneration under the Bank rules

Dated, Calcutta,
the 20th December, 1976

[No F L-12012/152/75-DIIA]

F K MOIDU, Presiding Officer

S.O. 205—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Bank of Baroda Pilibhit Branch and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-12-76

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID No 17 of 1976

BETWEEN

The management of Bank of Baroda through their Regional Manager, Bank of Baroda, 4 Park Road, Lucknow

AND

Its workman Shri Narindera Singh, Accounts-cum clerk, Bank of Baroda, Pilibhit

PRESENT

Shri R C Bhatnagar —for the management

Shri Tarachand—for the workman

AWARD

The Central Government on consideration of a report submitted by the Conciliation Officer that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No L 12012/135/73/LRIII dated the 11th August, 1975 with the following terms of reference —

"Whether the management of the Bank of Baroda was justified in terminating the services of Shri Narinder Singh, Accounts-cum cash clerk, Pilibhit, with effect from the 18th April, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled?

2 The applicant averred that he was appointed as an Accounts-cum Cash Clerk in the service of the respondent with effect from 28-10-72 on 6 months' probation On 18 4 73 when he had completed more than 5-1/2 months of his service, the management abruptly and without any cause terminated his services It was pleaded that the termination of the services of the workman was illegal and unjustified It was, therefore, prayed that he be re-instated with full back wages and continuity of service

3 The respondent admitted that the applicant was appointed on a probation of six months It was stated that since the work and conduct of the workman during the probationary period had not been found satisfactory, his services were terminated with immediate effect by its letter dated 18 4 73 He was even, offered one months salary in lieu of notice It was pleaded that the action of the management was legal and justified It was therefore, prayed that the workman was not entitled to any relief

4 The workman filed a rejoinder and re-iterated his claim

5 On these pleadings the following issue was framed —

ISSUE

1 As in the term of reference

6 In oral evidence the management examined Shri S R Bajpai—MW1—agent Bank of Baroda In rebuttal the workman Shri Narendra Singh examined himself as WW1

7 Arguments were, then, heard

ISSUE No : 1

8 The case set up by the workman, herein, was that his services were terminated by the management abruptly and without any cause when he had almost completed the period of his probation

9 The management put-forth a defence that the work and conduct of the workman, herein, was not found satisfactory during the period of probation, therefore, his services were terminated In addition, Shri R C Bhatnagar appearing for the management contended that it was entirely for the management to satisfy itself about the satisfactoryness of the workman's services, work and conduct, and any action taken by the workman on the basis of such satisfaction could not be questioned by anyone else

10 The first question, therefore, is whether the right of the management to terminate the services of its workman was absolute and could not be challenged at all

11 On consideration, I am of the opinion that the dictum of the Hon'ble Supreme Court of India in L Michael & Anr. Vs M/s Johnson Pumps Ltd answers the contention well enough It was held therein that,

"The Tribunal has the power and, indeed, the duty to X ray the order and discover its true nature, if the object and effect, if the attendant circumstances and the ulterior purpose be to dismiss the employee because he is an evil to be eliminated But if the management, to cover up the inability to establish by an enquiry, illegitimately but ingeniously passes an innocent looking order of termination simpliciter such action is bad and is liable to be set aside" ( )

12 In Murugan Mills case (1965 2 SCR 148) It was also held,

"The right of the employer to terminate the services of his workman under a standing order like cl 17(a) in the present case, which amounts to a claim to 'hire and fire' an employee as the employer pleases and thus completely negatives security of service which has been secured to industrial employees through industrial adjudication came up for consideration before the Labour Appellate Tribunal in Buckingham & Carnatic Co Ltd v Workers of the

Company (1952 L.A.C. 490) The matter then came up before this Court also in Chartered Bank v Chartered Bank Employees Union (1960 3 SCR 441) and the Management of U B Dutt & Co v Workmen of U B Dutt & Co (1962 Supp 2 SCR 822) wherein the view taken by the Labour Appellate Tribunal was approved and it was held that even in a case like the present the requirement of bona fides was essential and if the termination of service was a colourable exercise of the power or as a result of victimisation or unfair labour practice, The Industrial Tribunal would have the jurisdiction to interfere and set aside such termination The form of the order in such a case is not conclusive and the tribunal can go behind the order to find the reasons which led to the order and then consider for itself whether the termination was colourable exercise of unfair labour practice If it came to the conclusion that the termination was a colourable exercise of the power or was a result of victimisation or unfair labour practice it would have the jurisdiction to intervene and set aside such termination '

13. There is a chain of further rulings, also in which the contention of the management has been answered It is, therefore, well established that a belief of the employer, that the services work and conduct of an employee were unsatisfactory, could not be a mere whim or fancy It should be bona fide and reasonable It must rest on some tangible basis and the power has to be exercised by the employer objectively in good faith which means honestly with due care and prudence

14 The second question is whether the work and conduct of the employee herein, were unsatisfactory Shri S R Bajpai—MW1 -agent of the Bank of Baroda who found the work of the employee, herein, unsatisfactory gave evidence as WM1 He said he found the work of the employee unsatisfactory He sent reports regarding his work to the Regional Manager Lucknow One such report was Ex M/2 and another was Ex M/3 In Ex M/2, the report was as follows —

1. "That Mr Narendra Singh joined this Bank on 28 10 72 and is still on probation which will be completed on 28-4-73

2 That before joining this Bank, Mr Singh had worked in P N Bank as temporary for about 1 1/2 years"

3 That he is local man and his father has photography shop at Pilibhit proper

4 As for the integrity is concerned, I never found any thing wrong about him

5 As for the work is concerned, he is slow worker and tried to shirk the work and also a not paying more attention towards work rather than other activities In one or two cases he had done some gross negligence and not attended the work properly '

In view of the above facts and in the interest of the Bank, I am of the opinion that he should not be confirmed in the Bank's service

15 His report in Ex M/3 was as follows —

"Please refer to this office D O letter No D O /12 of 16th instant and write to advise you that looking the incidents and gross negligence that Mr Singh did in the past, and he always shirks work in the office, we are of opinion that his services should immediately be terminated from our Bank This action of termination is urgently required in the interest of the Bank and prestige of the Bank '

16 Thus the grounds for saying that the work and conduct of the workman, herein, were unsatisfactory, were that (a) he was a slow worker and tried to shirk work, (b) that he did not pay more attention to work rather he paid more attention to other activities, (c) that in one or two cases he had been grossly negligent and not attended the work properly, and (d) that he being a local man might create some disturbances if he was not confirmed

17. Now, there was nothing in the evidence of Shri S R Bajpai MW1 showing any instance in which the workman, herein was found to have been a slow worker No instances were given, also, in which he tried to shirk work or where he did not pay attention or more attention or the required attention Referring to the other activities the witness said that what he meant by the expression was that the workman paid attention to cultural and social activities and activities pertaining to local persons who used to visit him in the Bank Firstly, there was no evidence about these activities, that the workman indulged in them The workman himself said in his statement WW1 that he never took part in any cultural activities, social or otherwise Secondly, the mere taking part in cultural or social activities will not be enough to show that the work and conduct of the workman was unsatisfactory in his office It lay heavily on the management to show that the social and cultural activities of the workman interfered with his legitimate work which he was required to do for the management Since there is no such evidence there can be no hesitation in holding that the management failed to prove that the work and conduct of the workman, herein, were unsatisfactory Similarly, there were no instances of gross negligence of the workman Rather Shri S R Bajpai-MW1 said that what he meant by gross negligence was that certain outsiders were allowed by the workman to sit inside the cash cabin I fail to understand as to how merely allowing outsiders to sit inside the cash cabin would amount to gross-negligence The management failed to show that there was any rule of conduct in which an outsider could not be allowed to sit inside the cash cabin, and secondly without something more merely sitting inside the cash cabin would not make it a mis-conduct of gross-negligence Lastly, the suspicion of the agent that the workman may create some disturbances or gherao him and create trouble for him Afterall, it was a mere suspicion No incidents actually happened as admitted by Shri Vajpai himself This suspicion was, therefore, nothing but a camouflage and unfair labour practice It appears as stated by the workman himself that Shri Bajpai on whose report the termination took place got prejudiced for certain reasons like the shortage of Rs 3 000 and had a heated argument with him Subsequently, out of his anger he made the reports Ex M/2 and Ex M 3 without there being any grounds for them The management has, then,tried to use the words like unsatisfactory conduct and work without there being any evidence to prove them As already observed above, the suspicion of the employer could not be a mere whim or a fancy It should be bonafide and reasonable Here in this case there is no tangible evidence to show that the reports of Shri Bajpai were made objectively in good faith, honestly and with due care and prudence The management did not even disclose in the Court the grounds for harbouring the feeling that the conduct and work of the workman were unsatisfactory It was therefore manifest that the action of the management was not justified and not even bona-fide The issue is, accordingly decided against the management

18 The results that the workman, herein is entitled to be re-instated with full back wages The management is accordingly directed to re instate the workman forthwith and pay him his back wages ever since 18th April 1973 at the rate he was paid last, and treat him continuous An award is made accordingly

2nd November, 1976

D D GUPTA, Presiding Officer

[F No 12012/135/73-IR III/D IIA]

R P NARULA Under Secy

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1977

का० आ० 206—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जनवरी, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० जी० बोस संयुक्त वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को नियुक्त करती है और निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में नामित करती है —

1 निदेशक, निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2 महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली ।

3 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार ।

4 महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी संकलन, कलकत्ता ।

5 संयुक्त सचिव (एगमार्क के कार्यभारी), कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।

6 सचिव, तकनीकी विकास, नई दिल्ली ।

7 सदस्य, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड ।

8 उप-महानिदेशक (निरीक्षण) सभरण तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली ।

9 अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ का फेडरेशन ।

10 अध्यक्ष, समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातक संघ, कोचीन ।

11 विकास आयुक्त, लघु उद्योग ।

12 अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ ।

13 श्री वी० एच० पंचोली, फिल्को प्राइवेट लि०, सेवरी, बम्बई ।

14 श्री के० वी० गोपीनाथ, मैसर्स मैसोडेट (प्रा०) लि०, बंगलौर-25।

15 श्री एम० एन० दस्तूर, मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।

[फा० सं० 3(94)/75-ई आई एण्ड ई पी)]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st January, 1977

S O. 206.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri S G Bose Mullick, Commerce Secretary, Ministry of Commerce, as Chairman and nominates the following as Members of the Export Inspection Council for a period of one year with effect from 1st January 1977 —

1 Director of Inspection and Quality Control, Ministry of Commerce, New Delhi

2 Director General of Indian Standards Institution, New Delhi.

3 Agricultural Marketing Adviser to the Government of India

4 Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta

5 Joint Secretary (In-charge of Agmark), Ministry of Agriculture, New Delhi

6 Secretary, Technical Developmert, New Delhi

7 Member, Central Board of Excise and Customs

8 Deputy Director General (Inspection), D G S &D, New Delhi

9 President, Federation of Association of Small Industries.

10 President, Seafood Exporters Association, Cochin

11 Development Commissioner for Small Scale Industries.

12 Chairman, Federation of Indian Exports Organisations

13 Shri V H. Pancholi of Filco Pvt, Sewri, Bombay

14 Shri K V. Gopinath, M/s Mysodet Pvt Ltd, Bangalore-25.

15 Shri M N Dastur, M/s Dastur & Co. Pvt Ltd, Calcutta

[No 3(94)/75-EI&EP]

125 GI/76—8

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1977

का० आ० 207—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ;

अत , अब, उक्त उपनियम के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना स० का० आ० 2376, तारीख 6 अगस्त, 1966 को अतिष्ठित करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए, जिनके उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है ।

2 इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे मे कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की आशा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(i) यह अधिसूचित करना कि पी० वी० सी०, लैदर-क्लाथ का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा;

(ii) इस आदेश के उपाबंध-1 मे दिए गए पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप मे विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ पर निर्यात से पूर्व लागू होगा ।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ अभिकरण द्वारा पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के अनुसार जारी किया गया प्रमाण-पत्र न हो,

(iv) (क) इस आदेश के उपाबंध-2 मे दिए गए पी० वी० सी लैदर-क्लाथ के लिए विनिर्देशों को,

(ख) निर्यात संविदा के विनिर्देशों को, पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के लिए मानक विनिर्देशों के रूप मे मान्यता देना परन्तु यह तब जब ऐसे विनिर्देश उक्त उपाबंध मे निर्धारित अपेक्षाओं से नीचे के न हो ।

3 इस आदेश की कोई भी बात पी० वी० सी लैदर-क्लाथ के उन नमूनों के जल, थल या वायु-मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नही होगी जिनका भावी क्रेता के लिए पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य 125 रु० मात्र से अधिक नही है ।

4 इस आदेश मे पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ से कपास, पटसन, रेयन, नायलोन या अन्य किसी फैब्रिक से बना वह कपड़ा अभिप्रेत है जिस पर पालिविनयल क्लोराइड पालिमर या विनयल कोपालिमर, जिसका मुख्य संघटक पालिविनयल क्लोराइड है, एक ओर या दोनो ओर इस ढंग से लगाया गया है कि कोटिंग, कोट किए गए कुल फैब्रिक का कम से कम 40 प्रतिशत हो ।

उपाबन्ध-1

(पैरा 2 का उप-पैरा (ii) देखिए)

[निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित नियमों का प्रारूप]

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—इन नियमों का नाम पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ निर्यात (निरीक्षण नियम,) 1977 है।

2 परिभाषा —इन नियमों मे, जब तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कोचीन में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है।

(ग) "पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ" से कपास, पटसन, रेयन, नायलोन या अन्य किसी फैब्रिक से बना वह कपड़ा अभिप्रेत है जिस पर पालिविनयल क्लोराइड पालिमर या विनयल कोपालिमर, जिसका मुख्य संघटक पालिविनयल क्लोराइड है, एक ओर या दोनों ओर इस ढंग से लगाया गया है कि कोटिंग, कोट किए गए कुल फैब्रिक का कम से कम 40 प्रतिशत हो।

3. निरीक्षण का आधार :—पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि निर्यात के लिए आशयित पी० वी० सी लैदर-क्लाथ का परेषण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—

1.(क) पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, पोत-लदान की संभावित तारीख से कम से कम पांच दिन पहले, अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा और प्रार्थना-पत्र के साथ पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ की जिस क्वालिटी और डिजाइन का निर्यात किया जाना है, उसका नमूना (निर्यात संविदा मे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार) उस अभिकरण को देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उत्पादन-कर्ता का परिसर या वह स्थान आता है जहां पर निरीक्षण के लिए माल प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(ख) प्रार्थना-पत्र में—

(i) कपड़े तथा कोटिंग के भार,

(ii) विमाओं, चौड़ाई, नग की बुनावट, क्वालिटी और रंग-आभा या रंग, की बाबत नमूनों के विनिर्देश भी होंगे।

2. उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा नमूने सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अभिकरण पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के परेषण का, नियम 3 के अनुसार, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, निरीक्षण करेगा।

3. निरीक्षण के पश्चात् यदि अभिकरण संतुष्ट हो जाता है कि पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का परेषण, परेषण संबंधी घोषणा के अनुरूप है तो वह पांच दिनों के भीतर परेषण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त पांच दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा निर्यात कर्ताओं को इसके कारण बताते हुए ऐसे इंकार की सूचना देगा।

5 निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो—

(i) माल के उत्पादन-कर्ता के परिसर, पर, या

(ii) उस स्थान पर, जहा कि माल निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि निरीक्षण की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6 निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए प्रत्येक परेषण के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर तीस पैसे प्रति सौ रुपये की दर से निरीक्षण फीस दी जाएगी जो कम से कम 15 रुपए और अधिक से अधिक 200 रुपए होगी।

7. अपील :—

(1) नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन से अन्यून और सात से अधिक विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल में कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपाबंध-2

[पैरा 2 का उप-पैरा (iv) देखिए]

पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के लिए मानक विनिर्देश

1. सामग्री तथा उत्पादन :—

(1) कोटिंग :—

(क) पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ का उत्पादन आधारी फैब्रिक पर एक या दोनों ओर भली प्रकार प्लास्टिकृत तथा रंजित पोलिविनयल क्लोराइड या विनयल कोपालिमर सम्मिश्रण, पी० वी० सी० जिसका मुख्य संघटक होगा, की एकसार कोटिंग करके किया जाएगा।

(ख) कोटिंग सम्मिश्रण का मिश्रण तैयार माल को अपेक्षित रूप तथा दृढ़ता देने के लिए होगा। इस प्रकार की गई कोटिंग कुल कोट किए गए फैब्रिक भार का न्यूनतम 40 प्रतिशत होगी।

(ग) कोटिंग फफोल पिन-छिद्रों और अन्य यांत्रिकी दोषों से रहित होगी। यह चिपचिपी नहीं होगी और इसमें कोई बुरी लगने वाली गंध नही होगी।

(2) बेसिक फैब्रिक :—

इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधारी फैब्रिक अच्छी क्वालिटी, बनावट और मजबूती का होगा। यह साफ और बनाई या उत्पादन संबंधी दोषों से मुक्त होगी। जिस रंग की कोटिंग है, उसी रंग का पक्का रंग हुआ आधारी फैब्रिक प्रयोग किया जाएगा।

(3) रूप सज्जा :—

(i) कोटिंग या आधारी फैब्रिक का रंग या रंग आभा।

(ii) कोटिंग का डिजाइन, धारियां या प्रिंट; और

(iii) सतह फिनिश, पूरी तरह क्रेता द्वारा लिखित विनिर्देशों या स्वीकृत नमूनों के अनुसार होंगे।

(4) विमाएं —

पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ के रोलों या टैबिग-क्लाथ की विमाएं क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी। तथापि, संविदा के विनिर्देशों पर रोलों की चौड़ाई/टैबिग क्लाथ के साइज में $\pm$5 प्रतिशत की सहायता अनुमत होगी।

2 प्रति यूनिट क्षेत्र पी० वी० सी० कोटिंग और बेसिक फैब्रिक का भार

(1) पी० वी० सी० कोटिंग —

पी० वी० सी० कोटिंग के घोषित भार पर $\pm$15 प्रतिशत सहायता अनुमत होगी। 5 प्रतिशत

(2) आधारी फैब्रिक का भार निर्यात संविदा में दिए न्यूनतम के —5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3 टूटन सामर्थ्य —

तैयार लैदर क्लाथ की टूटन सामर्थ्य निम्नलिखित के अनुसार होगी

(क) ताने की दिशा में —5 5 कि०ग्रा० 1 से०मी० चौड़ाई।

(ख) बाने की दिशा में —5 5 कि०ग्रा० 1से०मी० चौड़ाई।

4 फ्लैक्स क्रेकिंग के लिए सहायता —

फ्लैक्सिंग घुमावों की न्यूनतम संख्या 2,000 होगी।

5 सूखे तथा गीले रगड़े जाने पर रंग का पक्कापन —

पी० वी० सी० लैदर-क्लाथ को रंग के पक्केपन की परख करने के लिए क्रोक मीटर का प्रयोग करते हुए (निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा दी गई प्रक्रिया के अनुसार) सूखे तथा गीले रगड़े जाने पर धब्बे की गहराई ज्योमेटिक ग्रे स्केल (सदर्भ -ब्रिटिश-मानक 2663) की श्रेणी 4 से अधिक की नहीं होगी।

6 पैकिंग —

पैकिंग का ढंग क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा। पी० वी०सी० लैदर क्लाथ के रोलों को बीच के डण्डे सिरे पर लगने वाली प्लेटों जैसे गद्देदार साधनों से प्रबलित किया जाएगा। रोलों को समाविष्ट करने हुए पैकेज बंडल भली प्रकार बंद किए जाएंगे तथा आकार को बनाए रखने में तथा उसमें रखे माल को वातावरणिक खतरों से सुरक्षित रखने के लिए काफी मजबूत होंगे। भज-पोत को समाविष्ट करने वाले पैकेज कार्ड-बोर्ड आदि के साथ पर्याप्त रूप से प्रबलित किए होंगे जिससे भण्डारकरण में या अन्तिम पैकिंग करने से पूर्व आपत्तिजनक सिकुड़न तथा सड़े रहे आने से बचाने के लिए पैकेज जल सुरक्षित पालिथीलीन आदि से ढके होंगे।

[सं० 6(42)/72-नि०नि० तथा नि०उ०]

ORDER

New Delhi, the 15th January, 1977

S.O. 207—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963), the PVC Leather cloth should be subject to quality control and inspection prior to export,

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964,

Now, therefore, in pursuance of the said sub rule, the Central Government, in supersession of the notification No S O 2376 dated the 6th August, 1966, hereby published the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby

2 Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1

PROPOSALS

(i) To notify that PVC leather cloth shall be subject to quality control and inspection prior to export,

(ii) To specify the type of Quality control and inspection in accordance with the draft Export of PVC Leather Cloth (Inspection) Rules, 1976 set out in Annexure I this order as the type of inspection which shall be applied to such PVC Leather cloth prior to export,

(iii) To prohibit the export, in the course of international trade of PVC leather cloth, unless the same is accompanied by a certificate of inspection issued by the agency in accordance with the Export of PVC leather Cloth (Inspection) Rules, 1977,

(iv) To recognise .

(a) the specifications for PVC leather cloth as set out in Annexure II to this order,

(b) specifications in the export contract, provided that such specifications do not fall below the requirements prescribed in the said Annexure as the standard specifications for PVC leather cloth,

3 Nothing in this order shall apply to the export by sea, land or air of samples of PVC leather cloth not exceeding Rs 125 only in F O B value to the prospective buyer

4 In this notification 'PVC leather cloth' means cloth made of cotton jute, rayon, nylon or any other fabric to which a layer of polyvinyl chloride polymer or vinyl copolymer of which polyvinyl chloride is the major constituent has been applied either on one or on both sides in a manner that the coating forms at least 40 per cent of the total coated fabric weight

ANNEXURE-I

(See sub paragraph (ii) of paragraph 2)

(Draft rules proposed to be made under Section 17 of Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1 Short title and commencement—These rules may be called the Export of P/V/C Leather Cloth (Inspection) Rules, 1977

(2)

2 Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

(b) 'Agency means any one of the agencies established at Calcutta, Bombay, Delhi, Madras and Cochin under Section 7 of the Act,

(c) PVC Leather Cloth' means cloth made of cotton, jute, rayon, nylon or any other fabric to which a layer of polyvinyl chloride polymer or vinyl copolymer of which polyvinyl chloride is the major constituent has been applied either on one or on both sides in a manner that the coating forms at least 40 per cent of the total coated fabric weight

3 Bases of Inspection—Inspection of PVC Leather Cloth

shall be carried out with a view to seeing that the consignment of P/V/C Leather Cloth intended for export conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of Inspection.—(1) (a) An exporter intending to export P/V/C Leather Cloth shall, not less than five days before the expected date of shipment, give information in writing of his intention so to do and submit an application along with the sample of P/V/C Leather Cloth of the same quality and design as is intended to be exported in accordance with the specifications stipulated in the export contract to the agency within whose jurisdiction the premises of the manufacturer or the premises where the goods are offered for inspection are situated in order to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(b) The application shall also indicate the specifications of the sample in respect of—

(i) the weight of the cloth and coating,

(ii) the dimensions, width, texture of piece, quality and colour or shade.

(2) On receipt of the intimation and application alongwith the sample under sub-rule (1) the agency shall inspect the consignment of P/V/C Leather Cloth as per the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time in accordance with rule 3.

(3) If after inspection, the agency is satisfied that the consignment of P/V/C Leather Cloth conforms to the declaration relating to the consignment, it shall, within five days issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.

Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of five days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporters along with reasons therefor.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either—

(i) at the premises of the manufacturer of the goods, or

(ii) at the premises at which the goods are offered by the exporter for inspection, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 15 and a maximum of Rs. 200 for each consignment, a fee at the rate of thirty paise for every one hundred rupees of the FOB value for each such consignment shall be paid as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (3) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE-II

(See sub-paragraph (iv) of paragraph 2)

Standard Specifications for PVC Leather Cloth

1. Materials and Manufacture.—(1) Coating.—(a) PVC Leather Cloth shall be manufactured coating uniformly one or both sides of the basic fabric suitably plasticized and pigmented polyvinyl chloride or vinyl copolymer compound of which PVC shall be the major constituent.

(b) The composition of the coating compound shall be to impart the finished product the desired appearance and strength. The coating so applied shall form at least 40 per cent of the total coated fabric weight.

(c) The coating shall be non-blooming, free from pin-hole and other mechanical defects. It shall not be tacky and shall not have disagreeable odour.

(2) Basic fabric.—The basic fabric used for this purpose shall be of good quality, construction and strength. It shall be clean and free from weaving or manufacturing defects. Fast dyed basic fabrics of the same colour as that of the coating shall be used.

(3) Appearance.—The material shall conform strictly to the buyers written down specifications or approved samples, in respect of :

(i) Colour or shade of the coating or basic fabric ;

(ii) Design, grain or print of the coating; and

(iii) Surface finish.

(4) Dimensions.—Dimensions of PVC leather cloth rolls or table cloths shall be as specified by the buyer. A tolerance upto ± 5 per cent, shall, however, be permitted on the contractual specifications, in respect of the width of the rolls or size of the table cloth.

2. Weights of PVC coating and Basic fabric per unit area.—(1) PVC Coating.—A tolerance of $\pm\frac{15}{5}$ per cent chall be allowed on the declared PVC coating weight.

(2) The weight of the basic fabric shall be not less than —5 per cent of the minimum stipulated in the export contract.

3. Breaking strength.—The breaking strength of the Finished Leather Cloth shall be as follows :—

(a) Warp direction	—5.5 Kg/cm width
(b) Weft direction	—5.5Kg/cm width

4. Resistance to Flex Cracking.—The minimum number of flexing cycles shall be 20,000.

5. Colour fastness to Dry and Wet Rubbing.—The degree of staining shall be not more than rating 4 of the Geometric Grey Scale (Ref. BS : 2663) when PVC leather cloth in subjected to the test for colour fastness to dry and wet rubbing by using a crockmeter (as per the procedure prescribed by the Export Inspection Council).

6. Packing.—Mode of packing shall be as specified by the buyer. The rolls of PVC leather cloth shall be reinforced with cushioning aids such as centro-cores and end discs. The packages or bundles containing the rolls shall be well closed and sturdy enough to retain shape and to protect the contents from environmental hazards. The packets containing table cloths shall be reinforced adequately with card board etc. so as to prevent occurrence of objectionable curls and folds on storage and before final packing the packets shall be covered with waterproof paper or polythene etc.

[No. 6(42)/72/EI&MEP]

आदेश

का० आ० 208.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हों;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्न विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण)

नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा-अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अत: अब उक्त उप-नियम के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार उन लोगो की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है;

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावो के बारे मे कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनो के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि साइकिल के टायरों व ट्यूबों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा:

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस आदेश के उपाबन्ध में दिए गए साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारुप के अनुसार निरीक्षण के उस प्रकार के रुप मे विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से पूर्व ऐसे साइकिल के टायरों व ट्यूबो पर लागू होगा.

(3) (क) साइकिल के टायरो तथा साइकिल की ट्यूबों के लिए निर्यात संविदा मे विनिर्देशों को निर्यात-कर्ता द्वारा घोषित स्वीकृत विनिर्देशों के रुप में मान्यता देना।

(ख) साइकिल के टायरों तथा साइकिल की ट्यूबों के लिए विनिर्देशों को उत्पाद की विशेषताओं सहित ब्राण्ड नाम के अनुसार मान्यता देना :

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे साइकिल के टायरो तथा साइकिल की ट्यूबों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो हो कि ऐसे साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबे मानक विनिर्देशों के अनुरुप है तथा निर्यात योग्य है।

3. इस आदेश की कोई बात, स्थल, समुद्र या हवाई रास्ते द्वारा साईकिल टायरो और साईकिल ट्यूबों के नमूनो के क्रेताओ को निर्यात करने पर लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में, --

(1) "साइकिल के टायरो" से साइकिल तथा रिक्शा में प्रयुक्त होने वाले टायर अभिप्रेत है जो दो स्टील बीड वायर बीड रिंगो को घेरकर रबड़ कोर्ड की फैब्रिक केसिंग से तथा उपयुक्त मिश्रित रबड़ की धारियो से युक्त होंगे।

(2) "साइकिल की ट्यूबों" से साइकिल तथा रिक्शा के लिए बनी रबड़ की ट्यूबो अभिप्रेत है जो उपयुक्तत: मिश्रित तथा वल्कनीकृत प्राकृतिक तथा/या संश्लिष्ट रबड़ से युक्त होंगे।

उपाबन्ध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारुप

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमो का नाम साइकिल टायर तथा साइकिल साइकिल ट्यूब निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 है।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.--इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "साइकिल के टायरों" से साइकिल तथा रिक्शा में प्रयोग होने वाले टायर अभिप्रेत हैं जो दो स्टील बीड वायर बीड रिंगो को घेरकर रबड़ कोर्ड की फेब्रिक केसिंग से युक्त होंगे तथा उपयुक्त मिश्रित रबड़ की धारियों से युक्त होंगे।

(घ) "साइकिल की ट्यूबों" से साइकिल तथा रिक्शा के लिए बनी रबड़ की ट्यूबे अभिप्रेत है जो उपयुक्तत: वल्कनीकृत और मिश्रित प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ से युक्त होगे।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण.--

(1) साइकिल के टायरों तथा साइकिल की ट्यूबों का क्वालिटी नियंत्रण विनिर्माता द्वारा उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा, नीचे दिया गया--

(i) क्रय तथा कच्चा माल नियंत्रण--

(क) प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल के गुण धर्मों को सम्मिलित करते हुए, विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषण या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करने वाले प्रदाय-कर्ता के परीक्षण तथा निरीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ होंगे उस दशा में क्रेता द्वारा इस परेषणों में से कम से कम एक बार, यदा कदा होने वाली जांच पड़ताल विशिष्ट प्रदाय कर्ता के लिए पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाणपत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए क जाएगी या क्रय किए गए माल का या तो कारखाने के भीतर प्रयोगशाला मे या बाह्य प्रयोगशाला या परीक्षण गृह मे नियमित रुप से परीक्षण और निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना लेखबद्ध किए गए अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए माल को पृथक् करने में तथा अस्वीकृत माल के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) विनिर्माता द्वारा ऊपर वर्णित नियंत्रणों के संबध मे पर्याप्त अभिलेख नियमित व व्यवस्थित रुप से अपनाए जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण—

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों मे यथा अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर एवं साधनों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माता द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान किए गए नियंत्रणों के सत्यापन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख रखे जाएंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण

(क) यह जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुसार है, विनिर्माता के पास परीक्षण करने के लिए या तो स्वयं के पास परख सुविधाएं होंगी या परख सुविधाएं उसकी पहुंच के भीतर होनी चाहिएं;

(ख) परीक्षण और निरीक्षण के लिए नमूनों का लेना लेख बद्ध किए अन्वेषण पर आधारित होगा;

(ग) नमूने लेने और किए गए परीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे;

(घ) उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तरमान अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण

भंडारीकरण तथा अभिवहन के दौरान उत्पाद अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण

उत्पादों की पैकिंग के लिए अनुसूची 2 में वर्णित नियंत्रणों को पूरा करने के लिए पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(2) निर्यात के लिए आशयित साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि उप-नियम (1) के अनुसार क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग सुसंगत स्तरों पर समाधानप्रद रूप से किया गया है तथा साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबें इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :

(1) साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में परिषद् के नजदीक ही के कार्यालय को देगा। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर विनिर्माण एकक का निरीक्षण सबसे पहले परिषद् के अधिकारी करेंगे और उनकी सिफारिश पर इस प्रयोजन के लिए, अनुसूची 1 तथा 2 में दी गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता जांचने के लिए परिषद् द्वारा बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल के जाने का प्रबंध किया जाएगा। विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश पर यह स्थापित किया जाएगा कि एकक के पास उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों की पर्याप्तता है।

विनिर्माण एकक इस प्रयोजन के लिए परिषद् के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों को सभी सुविधाएं देगा।

(2) साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण को देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा देगा कि साइकिल के टायर तथा साइकिल की ट्यूबों का परेषण नियम 3 में दिए गए क्वालिटी नियंत्रण उपायों को प्रयुक्त कराके विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण अपना यह समाधान कर लेने पर कि एकक द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 में दिए गए पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का योग किया गया है तो यह परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परेषण का निरीक्षण करेगा।

(4) निर्यात कर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाया जाने वाला पहचान चिन्ह भी देगा।

(5) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा को विनिर्माता के यहां से परेषण के भेजे जाने से कम-से-कम सात दिन पहले अभिकरण के कार्यालय में पहुंचना चाहिए।

(6) यदि अभिकरण ने अपना यह समाधान कर लिया है कि निर्यात किया जाने वाला साइकिल के टायरों तथा साइकिल की ट्यूबों का परेषण उप-नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो यह उप-नियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए निर्यात कर्ता को प्रमाण-पत्र दे देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देगा और ऐसे इन्कार की सूचना उसके कारणों सहित देगा।

(7) उन एककों में जिनमें उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों की पर्याप्तता है, उसके पश्चात् उनके द्वारा अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता की जांच करने के लिए परिषद् के अधिकारी नियमित अन्तरालों पर जाएंगे। यदि किसी भी विनिर्माण एकक में यह पाया जाता है कि उसने विनिर्माण के किसी भी स्तर पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण परिमाप नहीं अपनाए हैं तो परिषद् के अधिकारियों की सिफारिशों पर घोषित कर दिया जाएगा कि उसके पास उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों की पर्याप्तता नहीं है। उस दशा में एकक पुनः आवेदन करेगा जिससे कि उसी के अनुसार विशेषज्ञों के पैनल द्वारा निरीक्षण करने का प्रबंध किया जाएगा।

5 निरीक्षण फीस :

इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए, ऐसे प्रत्येक परेषण के पोस पर्यन्त निशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए पर तीस पैसे की दर से निरीक्षण फीस निर्यात कर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी। यह फीस कम-से-कम बीस रुपए होगी।

6 अपील :

(1) नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देने से व्यथित व्यक्ति ऐसे इन्कार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम-से-कम तीन और अधिकतम सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) ऐसे पैनल में विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से-कम दो-तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील को उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा।

अनुसूची 1

(नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए)

(साइकिल के टायर)

क्रम सं०	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की सं०	आवृत्ति	टिप्पणी
1.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	1 प्रतिशत	प्रति बैच (1,000 से 10,000 टुकड़े)	—
2.	विमाएं	—		-वही-	भा०भा० 2414 के अनुसार
3.	बनावट			-वही-	-वही-
4.	सम्पूर्ण मोटाई			-वही-	-वही-
5.	कोर्ड की मजबूती			-वही-	-वही-
6.	केस की मजबूती			-वही-	-वही-
7.	मनकेदार तार का टूटने भार		2 टुकड़े	-वही-	-वही-
8.	बीडतार का सुझाव सामर्थ्य			-वही-	-वही-
9.	मिश्रित रबड़ की तनन सामर्थ्य			-वही-	-वही-
10.	दीर्घीकरण तनन सैट			-वही-	-वही-
11.	मिश्रित रबड़ के टूटने पर दीर्घीकरण			-वही-	-वही-
12.	त्वरित अवस्था			-वही-	-वही-

(साइकिल की ट्यूब)

1.	फिनिश		1 प्रतिशत	1,000 से 10,000 प्रति बैच	-वही-
2.	विमाएं		1 प्रतिशत	—	भा०भा० 2415 के अनुसार
3.	तनन सामर्थ्य तथा टूटने पर दीर्घीकरण (अवस्था के पहले)			प्रति बैच	-वही-
4.	तनन सैट		2 टुकड़े	-वही-	-वही-
5.	तनन सामर्थ्य तथा टूटने पर दीर्घीकरण (अवस्था के पश्चात्)			-वही-	-वही-
6.	संयुक्त आसंजन मजबूती			-वही-	-वही-
7.	नीक परख			-वही-	-वही-

अनुसूची 2

[नियम 3 का उप-नियम (1) देखिए]

पैकिंग के लिए नियंत्रण स्तर :

1. पैकेज देखने में सुन्दर होंगे और ये अभिवहन के दौरान उठाई धराई सहन करने योग्य होंगे।

2. प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) सामान्य आकार, वर्ग, विनिर्माता का नाम तथा व्यापार चिन्ह।

(ख) मूल देश।

(ग) माल की मात्रा।

(घ) पोत लदान चिन्ह (शिपिंग)।

[सं० 6(15)/76/नि०नि० तथा नि०उ०]

के० वी० बालसुब्रह्मण्यम, उप निदेशक

ORDER

S.O. 208.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for the development of the export trade of India that Cycle Tyres and Cycle Tubes should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this Order in the official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street, (7th Floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) to notify that cycle tyres and tubes shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) to specify the type of quality control and inspection in accordance with the Draft Export of Cycle Tyres and Cycle Tubes (Quality Control and Inspection) Rules, 1976 as set out in the Annexure to this order as the type of inspection which shall be applied to such cycle tyres and tubes prior to their export;

(3) to recognise

(a) the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications in the exports contracts for Cycle Tyres and Cycle Tubes;

(b) the specification for Cycle Tyres and Cycle Tubes as per brand name of the product with its characteristics;

(4) to prohibit the export in the course of international trade of such cycle tyres and cycle tubes unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an agency recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such cycle tyres and cycle tubes conform to be standard specifications and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air, of samples of cycle tyres and cycle tubes to prospective buyers.

4. In this order—

(1) "Cycle tyres" means tyres to be used for bicycle and rickshaws and shall consist of rubberized chord fabric casing enclosing two steel bead wire bead rings and tread strips of suitably compounded rubber.

(2) "Cycle tube" means rubber tubes meant for bicycle and rickshaw and shall consist of natural and/or synthetic rubber suitably compounded and vulcanised.

ANNEXURE

([Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)]

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Cycle Tyres and Cycle Tubes (Quality Control and Inspection) Rules, 1977;

(2) They shall come into force on.....

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the agencies, established under section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi,

(c) "Cycle tyres" means tyres to be used for bicycles and rickshaws and shall consist of rubberized cord fabric casing enclosing two steel bead wire bead rings and tread strips of suitably compounded rubber.

(d) "Cycle tubes" means rubber tubes meant for bicycles and rickshaw tyres and shall consist of natural or synthetic rubber suitably compounded and vulcanized.

(e) "Schedule means the schedule appended to these rules.

3. Quality Control and Inspection—

(1) The quality control of cycle tyres and cycle tubes shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product, set out below :—

(i) Purchase and raw material control—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process control—

(a) Detailed process specification shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the control exercised during the process of manufacture.

(iii) Product controls—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of control to check the products shall be as specified in Schedule I.

(iv) Preservation control—
The product shall be well preserved both during the storage and the transit.

(v) Packing control—
Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying controls mentioned in Schedule II for packing of the products.

(2) The inspection of cycle tyres and cycle tubes intended for exports shall be carried out with a view to ensuring that the quality control in accordance with sub-rule (1) has been exercised at the relevant levels satisfactorily and the cycle tyres and cycle tubes conform to the specifications recognised for the purpose.

4. Procedure of Inspection—

(1) An exported intending to export cycle tyres and cycle tubes shall inform his intention to do so in writing to the nearest office of the Council. On receipt of such information, the manufacturing units shall be first visited by the officers of Council and on their recommendation, the visit of the panel of experts constituted by the Council for this purpose shall be arranged to adjudge the adequacy of inprocess quality control system as prescribed in Schedule I and II or otherwise adopted by the unit. On recommendation of the panel of experts, the unit shall be declared as having adequate inprocess quality control drills.

The manufacturing unit shall provide all facilities to the officers of the Council and the members of the panel of experts for this purpose.

(2) The exporter intending to export a consignment of cycle tyres and cycle tubes shall give intimation in writing of his intention to do so to the agency and submit along with such intimation, a declaration to the effect that the consignment of cycle tyres and cycle tubes has been or is being manufactured by exercising quality control measures laid down in rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the agency, after satisfying itself that during the process of manufacture adequate quality control, as provided in rule 3, has been exercised by the units duly, shall carry out the inspection of consignment in accordance with the instructions issued by the Council from time to time.

(4) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(5) Every intimation and declaration under sub-rule (2) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(6) If the agency is satisfied that the consignment of cycle tyres and cycle tubes to be exported complies with the requirements of sub-rule (3) it shall within seven days of receipt of intimation and declaration under sub-rule (2) issue a certificate to the exporter declaring the consignment as exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal along with the reasons therefor.

(7) The units having adequate in-process quality control drill shall be thereafter visited by the officers of the Council at a regular interval to adjudge the adequacy of in-process quality control system adopted by them. If any manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture, on the recommendations of the Council officer, the unit shall be declared not having adequate in-process quality control drills. In that case, the unit shall again apply afresh so that panel of experts visits shall be arranged accordingly.

5. Inspection fee—Subject to a minimum of rupees twenty for each consignment a fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of f.o.b. value of each such consignment, shall be paid by the exporter to the agency as 'Inspection fee' under these rules.

6. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of atleast two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE I

[See sub-rule (1) of rule 3]

(Cycle Tyres)

Sl. No.	Requirements	Reference	No. of samples	Frequency	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Finish	Standard specification recognised for the purpose	1%	(per batch) (1,000 to 10,000 Pcs)	—
2.	Dimension	—	1%	Do.	as per IS : 2414
3.	Construction	—		Do.	Do.
4.	Crown Thickness	—		Do.	Do.
5.	Cord strength	—		Do.	Do.
6.	Casing strength	—		Do.	Do.
7.	Breaking load of bead wire	—	2 Pcs	Do.	Do.
8.	Bonding strength of bead wire	—		Do.	Do.
9.	Tensile strength of rubber compound	—		Do.	Do.
10.	Elongation tension set	—		Do.	Do.
11.	Elongation at break of rubber compound	—		Do.	Do.
12.	Accelerated ageing	—		Do.	Do.

(Cycle Tubes)

1	2	3	4	5	6
1.	Finish	—	1%	1,000 to 10,000 per batch	As per IS : 2414
2.	Dimensions	—	1%		As per IS : 2415
3.	Tensile strength and elongation at break (before ageing)	—		per batch	Do.
4.	Tension set	—	2 Pcs	Do.	Do.
5.	Tensile strength and elongation at break (after ageing)	—		Do.	Do.
6.	Joint adhesion Strength	—		Do.	Do.
7.	Leak test	—		Do.	Do.

SCHEDULE II

[See sub-rule (i) of rule 3]

Levels of control for packing

1. The packages shall have a good presentability and sufficient strength to stand handling during transit.

2. The following information shall be given on each package, namely :—

(a) The nominal size, grade, the name of the manufacturer and trade mark.

(b) Country of origin.

(c) Quantity of the material.

(d) Shipping mark.

[No. 6(15)/76/EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Dir.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1976

का०आ० 209.—यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11-क के अन्तर्गत विभिन्न आयोजना मण्डलों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिल्ली की बृहत्त योजना के शहरी दिल्ली के भू उपयोग में उल्लिखित कुल रिहायशी घनत्व में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा दिल्ली विकास (बृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली 1959 के नियम 6 के अन्तर्गत 13 अक्तूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या एफ०-3(154)/67-एम० पी० द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित नोटिस की तारीख से 30 दिन के अन्तर्गत आक्षेपों और सुझाव को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और यत. केन्द्रीय सरकार ने अनुसूची में उल्लिखित उक्त संशोधन के सबध में आक्षेपो और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली की बृहत्त योजना में संशोधन करने का निश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिल्ली की बृहत्त योजना में उस तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है जिस तारीख को यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में छपेगी;

संशोधन

I (1) पृष्ठ 22 (अंग्रेजी) के बाहिनी ओर के स्थान के पैराग्राफ 3 पर "6 रिहायशी क्षेत्र" के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ होगा :—

"6 रिहायशी क्षेत्र :

योजना का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ निवास हेतु संतुलित शहरी संरचना बनाना है तथा रिहायशी क्षेत्रों को सरकारी कार्यालयों, उद्योगों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों मे रोजगार के केन्द्रो के निकट रखना है ताकि आने जाने की दूरी कम से कम हो। इसे दृष्टि मे रखते हुए रिहायशी घनत्व का अपेक्षाकृत अधिक युक्तियुक्त पद्धति का प्रस्ताव है। कुछ केन्द्रीय क्षेत्रों मे जहां घनत्व बहुत अधिक था, कुछ कम कर दिया गया है ताकि रहने के लिए अच्छा वातावरण बन सके। चूंकि शहर का विस्तार अपनी बाहरी सीमा क्षेत्र की ओर हो रहा है, अतः प्रस्तावित घनत्व की क्रमबद्ध मान पर व्यवस्था की गई है ताकि भू-उपयोग के नक्शे में ध्यान में रखे गये खाके के अनुसार बहुग्रंहध्रिम/बहु केन्द्रीय घनत्व प्रभावित हो",

(ii) पृष्ठ 21 पर दायें तरफ वाले कालम, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा लगाया जायेगा :—

"इन्नर रिंग रोड और रिंग रोड के बीच, वर्तमान घनत्व लगभग 75 से 100 व्यक्ति प्रति एकड़ है तथा इसे इसी प्रकार रखा जाये। रिंग रोड के दक्षिण में बदरपुर रोड तक 75 से 100 व्यक्ति प्रति एकड़ की पद्धति की सिफारिश की जाती है। तथापि, कालकाजी के नजदीक 100 से 150 व्यक्ति प्रति एकड़ के उच्चतर घनत्व का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि यह ओखला औद्योगिक क्षेत्र के निकटतम है। मथुरा रोड के पश्चिम में फ्रेंड्स कालोनी में 25 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व रखने का प्रस्ताव है जबकि मथुरा रोड के पूर्व में स्थित क्षेत्रों के लिए 50 व्यक्ति प्रति एकड़ के घनत्व का प्रस्ताव किया गया है। ओखला सीवेज फार्म के दक्षिण में कोई रिहायशी विकास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहां रिहायशी क्षेत्र रखना आपत्तिजनक है।"

(iii) पृष्ठ 24 पर पैरा 2 में दायें तरफ वाले कालम, लाईन 21 में आगे की लाइनों के स्थान पर निम्नलिखित लाइने रखी जाएंगी :—

"माल रोड के उत्तर तथा जी०टी०रोड के पूर्व में स्थित अन्य सभी क्षेत्रों का राष्ट्रीय राजमार्ग बाई पास तक 100 व्यक्ति प्रति एकड़ के हिसाब से विकास करने का प्रस्ताव है। इसके उत्तरी भाग में पानी इकट्ठा होने की संभावना है तथा इसका विकास नालियों की पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद ही किया जाना चाहिए।"

(iv) पृष्ठ 24 पर दायें तरफ वाले कालम में पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आयेगा :—

"उत्तर-पश्चिम मे, इस समय अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण किस्म का है और उसमे कुछ फल के बगीचे है। यह प्रस्ताव है कि शहर के निकटतम क्षेत्रों का व्यापक विकास किया जाए क्योंकि ये क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाली पुरानी दिल्ली से चार मील से ज्यादा दूर नहीं है और वहां भीड़भाड़ कम करने में सहायक होंगे। अन्धा मुगल के नजदीक 150 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व और रिंग रोड के दोनों ओर तथा प्रस्तावित नगरीकरण योग्य सीमाओं की बाह्य परिधि तक और रोहतक अम्बाला को जाने वाली रेलवे लाइनों के साथ-साथ 150 से 100 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व रखने का प्रस्ताव है ताकि काम पर आने के लिए अधिकतम लोगों को कम से कम दूरी तय करनी पड़े। वर्तमान काल के अधिकांश बागों को डिस्ट्रिक्ट पार्कों के रूप में रखा गया है तथा पब्लिक एजेंसियों या सहकारिताओं व व्यक्तियों द्वारा पट्टे के आधार पर फलों के बागों के रूप मे सुरक्षित और अनुरक्षित किए जाए। विस्तृत ले-आऊट प्लान तैयार करते समय फलों के वर्तमान बागों को यथासंभव स्थानीय पार्कों के लिए शामिल किया जाये। चूंकि किसी पार्क में पेड़ उगाने में कई वर्ष लग जाते है, अतः यह आवश्यक है कि इन पेड़ों का अच्छे से अच्छा प्रयोग किया जाये।"

(v) पृष्ठ 25 पर, बायें तरफ वाले कालम, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आयेगा :—

"दिल्ली-जयपुर रेलवे लाईन के पश्चिम तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 100 से 150 व्यक्ति प्रति एकड़ का घनत्व है। नजफगढ़ रोड के समीप तथा कार्य केन्द्रों के समीपस्थ अधिक घनत्व वाली शहरी सीमाओं के बाहर क्षेत्रों मे भी 100 से 150 व्यक्ति प्रति एकड़ के घनत्व का ही प्रस्ताव है।"

(vi) पृष्ठ 25 पर, बायी तरफ वाले कालम मे पैरा 4, लाईन 27 व 28 के स्थान पर निम्नलिखित लाईन्स आएगी :—

"यमुना के पार शाहदरा को लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले एक पूर्ण नगर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।"

(vi) पृष्ठ 25 के बाईं तरफ के स्थान के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा होगा :—

"प्रस्तावित औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के निकट दक्षिण शाहदरा में 125 से 150 तक के व्यक्तियों के उच्च घनत्व का प्रस्ताव है। अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सीमा और उत्तरी राजपथ के उप पथ तक प्रति एकड़ 125 से 75 तक व्यक्तियों के घनत्व का प्रस्ताव है। कार्य स्थानों से निकट संपर्क स्थापित करने के लिए तथा निम्न आय वर्गों के आवास के लिए अपेक्षाकृत अधिक घनत्वों का प्रस्ताव है।"

(viii) दिल्ली की बृहत योजना के पृष्ठ 26 (अंग्रेजी) पर, "7-विकास क्षेत्र" शीर्षक के ऊपर उल्लिखित 1981 तक प्रत्येक डिवीजन के रिहायशी क्षेत्रों तथा जनसंख्या की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायें :—

योजना मण्डल	1981 की प्रस्तावित जनसंख्या	रिहायशी क्षेत्र (एकड़)
क पुरानी दिल्ली	3,22,600	1,370
ख. सिटी एक्सटेंशन	3,98,200	2,590
ग. सिविल लाईन	3,87,685	3,480
घ. नई दिल्ली	6,34,100	6,963
ङ. शाहदरा	9,69,570	7,890
च. दक्षिण दिल्ली	8,27,125	9,400
छ. पश्चिम दिल्ली*	8,03,175	8,240
ज. पश्चिम यमुना नहर अथवा उत्तर पश्चिम	9,20,485	7,460
कुल**	52,62,900	47,360

II: दिल्ली की बृहत योजना से संलग्न शहरी दिल्ली के भू-उपयोग नक्शे मे उल्लिखित उपर्युक्त योजना मण्डलों के विभिन्न क्षेत्रों के कुल रिहायशी घनत्वों का संशोधन किया गया है जैसे कि इस अधिसूचना से संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है।

[सं० के० 12016(1)/76-(भाग 2)]

के० बिस्वास, निदेशक (नगर विकास)

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 22nd December, 1976

S.O. 209.—Whereas the Central Government propose to make certain modifications to the gross residential densities indicated in the Land Use Plan for Urban Delhi of the Master Plan for Delhi, for different zones under various planning divisions, under Section II-A of the Delhi Development Act, 1967, and published in the manner as prescribed under rule 6 of the Delhi Development (Master Plan & Zonal Development Plan) Rules, 1959 vide Notice No. F. 3 (154)/67-M.P. dated the 13th October, 1972, for inviting objections and suggestions within a period of 30 days from the date of notice as required by sub-section (3) of Section II-A of the said Act ;

And whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modification mentioned in the Schedule, have decided to modify the Master Plan for Delhi ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section II(A) of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification to the Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India namely:—

Modifications

1. (i) On page 22, right hand column, paragraph 3 on "6 Residential Areas" shall be substituted by the following paragraph :—

"6 Residential Areas :

The main objectives of the plan are to obtain a balanced city structure for healthy living and to relate residential areas to the centres of employment in government offices, industrial and commercial areas so that the journey to work and back is kept to the minimum. With this in view, a more rational pattern of residential densities is proposed. Densities have been lowered in some central areas where they were too high so as to provide better living environment. As the city extends towards its outer limits, the densities proposed have been provided on a graded scale to effectuate a polynodal/polycentric form envisaged in the Land Use Plan."

(ii) On page 24, left hand column, paragraph 3 shall be substituted by the following paragraph:—

"Between the Inner Ring Road and the Ring Road, the existing densities are about 75 to 100 persons per acre and should be so maintain. South of the Ring Road upto Badarpur Road the same pattern of 75 to 100 persons per acre is recommended. Near Kalkaji, however, higher densities of 100 to 150 persons per acre have been proposed since it is nearest to the Okhla Industrial Area. It is proposed to keep the 25 persons per acre density west of Mathura Road in Friend's Colony, whereas for the areas east of Mathura Road, a density of 50 persons per acre is proposed. No residential development should take place sought of Okhla Sewage Farm since it is undesirable to have a residential area there."

(iii) On page 24, right hand column in para 2, the lines from line 21, shall be substituted as follows :—

"All other areas north of Mall Road and the east of G.T Road are proposed to be developed at 100 persons per acre upto the National Highway Bypass. The northern portion of this is subject to water logging and should be developed only after adequate drainage arrangements have been carried out."

(iv) On page 24, right hand column, paragraph 3 shall be substituted by the following paragraph:—

"In the north-west, at present almost the entire area is rural in character with some good orchards. It is proposed to have intensive development for areas that are nearest to the city as they are not more than 4 miles from the densely populated Old Delhi and should help in relieving some of the congestion there. The densities proposed are 150 persons per acre near Andha Mughal and from 150 to 100 persons on both sides of the Ring Road and upto the outer periphery of the proposed urbanisable limits and along the railway lines to Rohtak and Ambala, so that the maximum number of people will travel minimum distance to get to work. Many of the large existing orchards have been retained as District Parks and may be preserved and maintained as orchards by public agencies or leased to cooperatives and individuals. Also in making detailed land plans care should be taken to include as much as possible of the Exits orchards for local parks. Since it takes many years to land scape a pass with trees, it is essential to make the best use of these trees."

(v) On page 25, left hand column, paragraph 3 shall be substituted by the following paragraph:—

"The density is between 100 to 150 persons per acre west of Delhi Jaipur Railway line and near the industrial areas. The same density range from 100 to 150 persons per acre has been proposed along the Najafgarh Road and on the periphery of urban limits with high densities close to the work centres."

(vi) On page 25, left hand column, in paragraph 4, lines 27 and 28 shall be substituted by the line, as follows:—

"Across the Yamuna, Shahdara is proposed to be developed as a complete city of about one-million population."

(vii) On page 25, right hand column, paragraph 2 shall be substitution by the following paragraph:—

"High densities of 125 to 150 persons are proposed in South Shahdara in proximity to the proposed industrial and commercial areas. In other areas densities ranging from 125 to 75 persons per acre are proposed towards the UP Border and upto northern Highway Bypass. Higher densities are proposed in this area establish relationship with the work centres and housing for low-income groups."

(viii) On page 26 of the Master Plan for Delhi, for the table indicating the population and residential areas for each Division by appearing above the heading "7-Development Zone", the following Table shall be substituted:—

Planning Divisions	Proposed 1981 population	Residential area(acres)
A. Old City	3,22,600	1,370
B. City Extension	3,98,200	2,590
C. Civil Lines	3,87,685	3,480
D. New Delhi	6,34,100	6,963
E. Shahdara	9,69,570	7,890
F. South Delhi	8,27,125	9,400

1	2	3
G. West Delhi* . .	8,03,175	8,240
H. West Yamuna Canal or North West . .	9,20,485	7,460
TOTAL .	52,62,800	47,360

II. Gross Residential Densities for various zones in the above mentioned Planning Divisions indicated in the Land use Plan for Urban Delhi appended to the Master Plan for Delhi are revised as shown in map appended to this notification

[No K-12016(1)/76-(Part-II)]

K BISWAS, Director (UD)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1977

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 210.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्यारहवी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

संशोधन :—

2.7 हैक्टयर का क्षेत्र जो मुख्य योजना में आवासीय प्रयोग हेतु निर्धारित है तथा जिसके दक्षिण में आसफ अली रोड़, पूर्व में सीताराम बाजार और तुर्कमान गेट खेनो ओर से समीप 'आवासीय क्षेत्र' से घिरा हुआ है। इसे अब 400 एफ.ए.आर. "व्यापारिक (सामान्य वाणिज्य और व्यापार)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनो में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता।

[सं एफ 20(8)/76-एम पी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 15th January, 1977

PUBLIC NOTICE

S.O 210.—The following modification, which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi, is hereby published for public information Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice The person making the objection or suggestion should also give his name and address

MODIFICATION

The land use of an area, measuring about 2 7 hectares, earmarked for residential use in the Master Plan, surrounded by Asaf Ali Road in the south, existing lane connecting Sita Ram Bazar in the east and residential area on the remaining two sides, near Turkman Gate is proposed to be changed to "commercial (general business and commercial)" with 400 F.A R

2 The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days, except Saturdays, within the period referred to above

[No F 20(8)/76 M P]

का० आ० 211—दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट, 1957 (1957 की सख्या-61) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम तैयार किये है।

संक्षिप्त शीर्षक भूमिका तथा व्याख्या

1 (1) ये नियम "होटल्स, बोर्डिंग हाऊसिज, गैस्ट हाऊसिज, हास्टल्स, लाजिंग हाऊसिज तथा मोटल्स (बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स) नियम, 1977 कहलाएगें।

(2) ये तुरन्त लागू होगें।

(3) इन नियमो मे सभी शब्द तथा अर्थ एव अभिप्राय यद्यपि उपयोग मे लाये जाते है यदि उनकी परिभाषा नही की गई है तो उनके अर्थ दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट, 1957 अथवा उक्त एक्ट के अन्तर्गत तैयार तथा स्वीकृत मुख्य योजना अथवा दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 तथा जो विषय हो, के अन्तर्गत उल्लिखित होगे।

(4) इन नियमो की व्यवस्थाओ की व्याख्या करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

परिभाषा

2 विषय अथवा सदर्भ मे किसी प्रकार के विरोध के बिना ये नियम निम्न प्रकार है :—

(1) एक्ट का तात्पर्य दिल्ली डवैल्पमेंट एक्ट, 1957 (1957 की सख्या-61) से है।

(2) प्राधिकरण का अभिप्राय उक्त एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

(3) बोर्डिंग हाऊस का अभिप्राय एक भवन से है जिसमे होटल्स की तुलना मे कमरे लम्बी अवधि हेतु किराये पर दिये जाते है।

(4) विस्तृत योजना का अभिप्राय मुख्य योजना उचित क्षेत्रीय विकास योजना अथवा योजनाओ के अन्तर्गत क्षेत्र के लिये तैयार किये गये योजना चित्र से है।

(5) 'समान कार स्थल' का अभिप्राय गाड़ियो एव साइकिल तथा कार स्थल हेतु प्रक्रिया नियमो के अनुसार उनमे उचित रूप से रख-रखाव तथा वाहनो के प्रवेश तथा विकास सुविधा सहित आवश्यक स्थान से है। सामान्यत भवनो मे प्रत्येक ऐसा स्थान 32 52 वर्ग मीटर (350 व० फु०) तथा भवनो से बाहर 23 23 वर्ग मीटर (250 वर्ग फुट) है।

(6) 'गैस्ट हाऊस' का अभिप्राय सरकारी अर्ध सरकारी अथवा सार्वजनिक निकायो के कर्मचारियो को कम अवधि के लिए प्रदान करने के लिए भवन से है।

(7) 'होस्टल' का अभिप्राय एक भवन से है जिनमें कमरे संस्थानों से संलग्न होते है अथवा जो लम्बी अवधि के लिए किराये पर दिये जाते है ।

(8) होटल का अभिप्राय एक भवन से है जो 15 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के रहने के लिए हो जिसके लिये भुगतान किया जाता है तथा जहां पर खाना प्रदान किया जाता है अथवा नही ।

(9) 'लाजिंग हाऊस' का अभिप्राय आवासीय क्षेत्र से है जो आवासीय क्षेत्र 15 से कम व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था से सम्बन्धित हो ।

(10) 'मुख्य योजना' का अभिप्राय दिल्ली के लिए मुख्य योजना से जिसे इस एक्ट के अन्तर्गत तैयार तथा स्वीकार किया गया था ।

(11) 'मोटल' का अभिप्राय उस होटल से है जो वाहनों/गाड़ियों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ठहरने हेतु मुख्य उच्च मार्गों के निकट स्थित हो ।

(12) 'क्षेत्रीय विकास योजना' चित्र का अभिप्राय उक्त एक्ट की धारा 8 के विकास क्षेत्र के लिए तैयार योजना से है ।

होटल्स

3 (1) होटल्स को निम्नलिखित स्थानों में अनुमति दी जाती है :

(ए) मुख्य योजना में इस उपयोग के लिए विशेष रूप से दिखलाये गये स्थानों में ;

(बी) सामान्य व्यवसाय एंव व्यवसायिक उपयोग तथा जिला केन्द्रो एंव उप-जिला केन्द्रों के लिए मुख्य योजना में दिखलाये गये क्षेत्रों में; तथा

(सी) सामुदायिक केन्द्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना चित्रो में दिखलाये गये क्षेत्रों में ।

(2) निम्नलिखित क्षेत्रीय नियम होटल्स पर लागू होंगे :

(ए) मुख्य योजना में इस उपयोग हेतु विशेष रूप से दिखलाये गये स्थानों में :—

(1) भूमितल क्षेत्र अनुपात 150 से अधिक न हो, किन्तु मुख्य योजना में विशाल रूप से मनोरंजन क्षेत्रों में भूमितल क्षेत्र अनुपात 200 से अधिक न हो ।

(2) प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक भू खण्ड के 25% से अधिकतम पटाव क्षेत्र न हो ।

(3) सामने न्यूनतम सैटबैक्स 15.24 मी० (50 फुट) अन्य दिशाओं मे 4.57 मी० (15 फुट) तथा पिछली ओर 6.10 मी० (20 फुट) हो

(4) सड़क से भवन की ऊपरी मंजिल तक अधिकतम ऊंचाई 36.60 मी (120') (लिफ्ट रुम तथा भवन की ऊपरी छत पर संयन्त्र इत्यादि के क्षेत्रो को छोड़कर) अन्यथा प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर ललित कला आयोग या हवाई अड्डा नियमों के अनुसार जो भी आवश्यक समझा जाए ।

(5) न्यूनतम सैटबैक्स लाइन्स मे बेसमेंटस बशर्ते कि ये केवल वाहनों के पार्किंग अथवा भवन के रख-रखाव इत्यादि के लिये प्रयोग में लाये जाते है, यदि बेसमैंट का एक भाग रसोई सुविधाओं के लिये उपयोग मे लाया जाना हो, इसे भी भूमितल क्षेत्र में मिलाया जाए ।

(6) शापिंग रेस्टोरैंट, बैंक तथा अन्य संबन्धित सुविधाओं जिनमें सरकुलेशन हेतु क्षेत्र, रसोई, स्टोरेज तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के उपयोग हेतु न्यूनतम भूतल क्षेत्र का 1.95 प्रति 92.90 वर्गमीटर (1000 वर्ग फुट) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पार्किंग हो, तथा न्यूनतम 0.85 प्रति 92.90 व० मी० (1000वर्ग फुट के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पार्किंग शेष होटल के लिये है (इसमें वहां कमी की जा सकती है जहां सार्वजनिक पार्किंग हो तथा जिसको होटल द्वारा उपयोग में लाया जाता तथापि इसकी सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो)

(बी) ऐसे क्षेत्रों में जो मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना चित्रों में सामान्य व्यापार एंव व्यवसायिक उपयोग जिला केन्द्र तथा उप-जिला केन्द्र तथा सामुदायिक सुविधाओं हेतु निर्दिष्ट हो :—

(1) मुख्य योजना तथा विस्तृत योजना चित्र तथा क्षेत्रीय विकास विकास योजना तथा जो भी विषय हो, के अनुसार क्षेत्रों में अधिकतम भूमितल क्षेत्र अनुपात प्रत्येक अधिकतम पटाव क्षेत्र (कवरेज) तथा न्यूनतम सैटबैक्स तथा बेसमैंट नियमों का विशेष रूप से विवरण हो ।

(2) अधिकतम ऊंचाई उक्त मद III-2ए(4) के अनुसार हो ।

(3) पार्किंग व्यवस्था उक्त मद III-2ए(4) के अनुसार हो ।

(4) बोर्डिंग हाऊसिज, गैस्ट हाऊसिज तथा होस्टल्स :

1 बोर्डिंग हाऊसिज, गैस्ट हाऊसिज तथा होस्टल्स को निम्न प्रकार अनुमति प्रदान की जाती है :

(ए) सामान्य व्यापार एवं व्यावसायिक उपयोग, जिला केन्द्रों तथा उप जिला केन्द्रों के लिये मुख्य योजना में दिखलाये गये क्षेत्रो में ।

(बी) सामुदायिक केन्द्रो के लिये क्षेत्रीय विकास योजना चित्रो मे दिखलाये गये क्षेत्रों में ।

(सी) विस्तृत योजना हेतु क्षेत्रीय विकास योजना चित्रो मे आवासीय उपयोग हेतु क्षेत्रों में तथा विशेष अपील के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अनुमति दिये जाने पर बशर्ते कि ऐसा कोई भी भूखण्ड 1,005 वर्ग मीटर (1200 वर्ग फुट) से कम न हो । इसके अतिरिक्त होस्टल्स सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं की श्रेणी के अन्तर्गत संस्थान उपयोग हेतु दिखलाये गये क्षेत्रो में अनुमति प्रदान की जाती है तथा मुख्य योजना तथा/अथवा क्षेत्रीय विकास योजना योजना चित्रों एवं मुख्य योजना के ग्रामीण क्षेत्र में इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि प्रत्येक विषय में होस्टल एक संस्थान के साथ संलग्न हो तथा इसका कुल भूमितल क्षेत्र कुल भू-तल क्षेत्र से 25% से अधिक न हो जो मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजना जो भी विषय हो के अनुसार संस्थान भूखण्ड पर प्राप्त हो ।

(2) निम्नलिखित क्षेत्रीय नियम बोर्डिंग हाऊसिज, गैस्ट हाउसिज तथा होस्टल्स जो संस्थान से लगे हुए न हो, पर लागू होंगे:—

(ए) सामान्य व्यापार तथा व्यवसायिक उपयोग जिला केन्द्र तथा उप जिला केन्द्र हेतु मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में सामुदायिक केन्द्रों के लिये दिखलाये गये क्षेत्रो में ।

(1) अधिकतम भूमितल अनुपात प्रत्येक मंजिल का अधिकतम पटाव क्षेत्र, न्यूनतम सैटबैक्स तथा बेसमैन्ट नियम मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजना तथा विस्तृत योजना चित्रों जो भी विषय हो, जो इन क्षेत्रों के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार हो।

(2) सड़क से भवन की ऊपरी मंजिल तक अधिकतम ऊंचाई 36.60 मी० (120') (लिफ्ट रूम तथा भवन की छत पर सयंत्र इत्यादि के क्षेत्रों को छोड़कर) हो अन्यथा प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर ललित कला आयोग अथवा हवाई अड्डा नियमों के अनुसार आवश्यक समझा जाये।

(3) भूमि तल क्षेत्र के 92.90 व० मी० (1000 व० फुट) में न्यूनतम 0.85 व० मी० के कार स्थल के बराबर पार्किंग हो। (इसे वहां कम भी किया जा सकता है जहां पर सार्वजनिक पार्किंग हो तथा इसे बोर्डिंग हाउस, गैस्ट हाउस अथवा होस्टल द्वारा उपयोग में लाया जाता हो तथापि इसकी सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो।

(बी) क्षेत्रीय विकास योजनाओं अथवा विस्तृत योजनाओं में आवासीय उपयोग हेतु दिखलाये गये क्षेत्रों में जहां ग्रुप हाऊसिंग की निम्न प्रकार अनुमति प्रदान की जाती है :—

(1) अधिकतम भूमितल अनुपात तथा मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं तथा विस्तृत योजनाएं भी जो विषय हो, में विशेषतः आवासीय क्षेत्र में अधिकतम भूमि तल अनुपातः एवं अधिकतम कवरेज प्रति फ्लोर हो।

(2) अन्यथा विस्तृत योजना में विशेष रूप से उल्लिखित सामने की ओर न्यूनतम 15.24 मी० (50') तथा अन्य ओर 4.57 मी० (15') तथा पिछली ओर 6.10(20') का सैटबैक्स हो।

(3) अन्यथा विस्तृत योजना में विशेष रूप से उल्लिखित बैसमैंट्स न्यूनतम सैटबैक्स लाइन्स में हों, लेकिन वे केवल वाहनों के खड़ा करने तथा/अथवा भवन को सर्विस, एवं रखरखाव हेतु उपयोग में लाये जाते हों।

(4) सड़क से भवन की ऊपरी मंजिल तक अधिकतम ऊँचाई 24.38 मी० (80') (लिफ्ट रूम तथा भवन की ऊपरी मंजिल पर संयंत्र इत्यादि के क्षेत्रों को छोड़कर) हो तथा जो भी प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर ललित कला आयोग अथवा हवाई अड्डा नियमों के अनुसार आवश्यक समझा जाये।

(5) उक्त मद-IV-2ए (iii) के अनुसार पार्किंग व्यवस्था।

(सी) क्षेत्रीय विकास योजनाओं अथवा विस्तृत योजनाओं में आवासीय उपयोग हेतु दिखलाये गये भूखंडों में हो तथा जो ग्रुपहाउसिंग हेतु उपयुक्त न हों.—

ये नियम वही होंगे जो मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं तथा विस्तृत योजनाओं जो भी विषय हो, में आवासीय भूखंडों के लिए निर्धारित है।

(3) निम्नलिखित क्षेत्रीय नियम संस्थान से लगे होस्टल्स पर लागू होंगे.—

(ए) सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत संस्थानीय उपयोग तथा मुख्य योजना तथा/अथवा क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए दिखलाये गये क्षेत्रों में कुल भूखण्ड के लिए नियम निम्न प्रकार होंगे:—

(1) न्यूनतम सैटबैक्स तथा बेसमैन्ट वही होंगे जो मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं एवं विस्तृत योजनाओं जो भी विषय हो, में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं तथा सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत संस्थानीय उपयोग के लिए है।

(2) सड़क से भवन की छत तक अधिकतम ऊंचाई 36.60 मी० (120') (लिफ्ट रूम तथा भवन की ऊपरी मंजिल पर संयंत्र इत्यादि के क्षेत्रों को छोड़कर) हो अन्यथा प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर ललित कला आयोग अथवा हवाई अड्डा नियमों के अनुसार आवश्यक समझा जाए।

(3) पार्किंग व्यवस्था उक्त मद IV-2ए (iii) के अनुसार हो।

(बी) विशेष अपील के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा कुल संस्थानीय भूखंड निम्न प्रकार होंगे :—

(1) सामने 15.24 मी० (50') का न्यूनतम सैटबैक्स अन्य ओर 4.57 मी० (15') तथा पिछली ओर 6.10 मी० (20') हो अथवा कृषि-हरी पट्टी/ग्रामीण क्षेत्र, जो भी अधिक हो, के विषय में मुख्य योजना क्षेत्रीय नियमों के अनुसार हो।

(2) सड़क से भवन की छत तक अधिकतम ऊंचाई 7.62 मी० (25') है।

(3) भूमितल क्षेत्र के 92.90 व० मी० (1000 व० फुट) के प्रति न्यूनतम 0.85 कार स्थल के समान पार्किंग हो।

5. लॉजिंग हाऊसिज

(1) लॉजिंग हाऊसिज को क्षेत्रीय विकास योजनाओं अथवा विस्तृत योजनाओं जो भी विषय हो में आवासीय उपयोग में आवासीय उपयोग के लिये दिखलाये गये क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2) लॉजिंग हाऊसिज पर निम्नलिखित क्षेत्रीय नियम लागू होंगे :—

(1) भूखण्ड का आकार 1254 व० मी० (1500 व० गज) के कुल क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

(2) अन्य नियम वही होंगे जो मुख्य योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, तथा विस्तृत योजनाओं में आवासीय विकास के भूखण्डों के लिये निर्धारित है।

6. मोटल्स

(1) मोटल्स को कृषि हरी पट्टी तथा मुख्य योजना के ग्रामीण क्षेत्र में अनुमति दी जाती है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विशेष अपील के पश्चात् इस शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है कि:—

(1) मोटल उन सड़कों के साथ-साथ स्थित हो जिन्हें राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किया गया है तथा उन भवनों के साथ-साथ जिनका उच्च मार्ग के मार्गाधिकार से न्यूनतम सैटबैक 400 मी० (1320') है।

(2) मोटल दिल्ली की शहरी सीमा से 1 किलो मीटर (3281') के बीच में न हो तथा (3) एक दूसरे से 1 कि०मी० (3281/) की दूरी पर भी दो मोटल न हो।

(2) मोटल्स के लिये निम्नलिखित नियम लागू होंगे :—

(1) अधिकतम भूखण्ड आकार 1.21 है० (3.00 एकड़) हो।

(2) अधिकतम भूमितल क्षेत्र 1,858 मी० (20,000 व० फुट) हो।

(3) सामने की ओर न्यूनतम सैटबैक 15.24 मी० (50') अन्य ओर 1.57 (15') तथा पिछली ओर 6.10 (20') हो।

(4) भूमितल क्षेत्र के 92.90 व० मी० (1000 व० फुट) के प्रति न्यूनतम 0.85 कार स्थल के समान पार्किंग हो।

[सं० एफ० 1(17)/74-एम० पी०]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

S.O. 211.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :—

1. *Short title commencement and Interpretation.*—(1) These regulations shall be called "The Hotels, Boarding Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging Houses and Motels (Building Standards), Regulations, 1977

(2) They shall come into force with immediate effect;

(3) All words and expressions used in these regulations but not defined shall have the meanings assigned to them in the Delhi Development Act, 1957 or the Master Plan Prepared and approved under the said Act or the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as the case may be;

(4) In interpreting the provisions of these regulations, the decision of the Delhi Development Authority shall be final.

2. **Definition.**—In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(1) 'Act' means the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957);

(2) 'Authority' means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act;

(3) 'Boarding House' means a building in which rooms are let out on a long term basis as compared to Hotels;

(4) 'Detailed Plan' means a plan prepared for an area within the framework of the Master plan and the relevant Zonal Development Plan or Plans;

(5) 'Equivalent Car Space' means the space required for the parking of mechanically-propelled vehicles and bicycles inclusive of ingress and egress to such spaces, expressed in terms of car spaces. Each such space is normally 32.52 sqpare metres (350 sq. feet) within buildings and 23.23 square metres (250 sq. feet) outside buildings;

(6) 'Guest House' means a building for housing the staff of Government Semi-Government or Public Undertakings for short durations;

(7) 'Hostel' means a building in which rooms attached to Institutions or otherwise are let out on a long-term basis;

(8) 'Hotel' means a building used for the lodging of 15 persons or more on payment with or without meals;

(9) 'Lodging House' means a house in a residential area used for the lodging of less than 15 persons;

(10) 'Master Plan' means the Master Plan for Delhi prepared and approved under the Act;

(11) 'Motel' means a Hotel located near to main highways for catering to the convenience of persons travelling in mechanically-propelled vehicles;

(12) 'Zonal Development Plan' means a plan prepared for a Development Zone under section 8 of the Act.

3. **Hotels.**—(1) Hotels are permitted,—

(a) on sites specifically shown for this use in the Master Plan;

(b) within areas shown in the Master Plan for General Business and Commercial use, District Centres and Sub-District Centres; and

(c) within areas shown in the Zonal Development Plans for Community Centres.

(2). The following Zoning Regulations shall apply to Hotels .—

(a) for sites specifically shown for this use in the Master Plan :—

(i) a floor area ratio not exceeding 150; however for sites in the vicinity of large recreational areas shown on the Master Plan, the floor area ratio should not exceed 200;

(ii) a maximum coverage per floor not exceeding 25 per cent of the net plot;

(iii) minimum set-backs of 15.24 metres (50 feet) in the front, 4.57 metres (15 feet) at the sides and 6.10 metres (20 feet) in the rear;

(iv) a maximum height of 36.60 metres (120 feet) from road level to the top of the building (excluding the lift room and other mechanical equipment areas on the top of the building), unless otherwise specified by the Authority or by the Delhi Urban Art Commission or as required by Airport regulations;

(v) basements within minimum set-back lines and provided they are used only for the parking of vehicles and or the servicing and maintenance of the building; in case part of the basement is used for providing kitchen facilities, the same be taken into floor area ratio calculations;

(vi) parking at an equivalent car space of at least 1.95 per 92.90 square metres (1,000 sq. feet) of floor area for uses like shopping, restaurants, banqueting and convention facilities inclusive of areas for circulation, kitchens, storage and the like; and parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 sq. metres (1,000 square feet) of floor area for the rest of the Hotel. (This can be reduced where a public form of pooled parking exists to be availed of by the Hotel and if the extent of this is determined by the Authority).

(b) within areas earmarked in the Master Plan for General Business and Commercial use, District Centres and Sub-District Centres and for Community Centres in the Zonal Development Plans :—

(i) a maximum floor area ratio, a maximum coverage per floor, minimum set-backs and basement regulations as specified for these areas in the Master Plan, Zonal Development Plan and the Detailed Plan as the case may be;

(ii) a maximum height as per item III. 2(a)(iv) above;

(iii) parking provision as per item III-2(a)(vi) above.

4. **Boarding Houses, Guest Houses and Hostels.**—(1) Boarding Houses, Guest Houses and Hostels are permitted :—

(a) within areas shown in the Master Plan for General Business and Commercial use, District Centres and Sub-District Centres;

(b) within areas shown in the Zonal Development Plans for Community Centres;

(c) Within areas shown for Residential use in the Zonal Development Plans or Detailed Plans and if allowed by the Authority after special appeal and provided no such plot is less than 1,005 sq. metres (1,200 sq. yards.) in net area.

In addition, Hostels are permitted within areas shown for Institutional use under the category of Public and Semi-public facilities and for Government Offices in the Master Plan and or the Zonal Development Plans and in the Rural Zone of the Master Plan, provided that in each case the Hostel is attached to an Institution and its total floor area does not exceed 25 per cent of the total floor area achieved on the institutional plot as per the Master Plan, Zonal Development Plans and Detailed Plans as the case may be.

(2) The following zoning regulations shall apply to Boarding Houses, Guest Houses and Hostels not attached to Institutions :—

(a) within areas shown in the Master Plan for General Business and Commercial use, District Centres and Sub-District Centres; and for Community Centres in the Zonal Development Plan :—

(i) a maximum floor area ratio, a maximum coverage per floor, minimum set-backs and basement regulations as specified for these areas in the Master Plan, Zonal Development Plans and Detailed Plans as the case may be;

(ii) a maximum height of 36.60 metres (120 feet) from road level to the top of the building (excluding the lift room and other mechanical equipment areas on the top of the building) unless otherwise specified by the Authority or by the Delhi Urban Art Commission or as required by Airport regulations;

(iii) parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 sq. metres (1,000 sq. feet) of floor area. (This can be reduced where a public form of pooled parking exists to be availed of by the Boarding House, Guest House or Hostel and if the extent of this is determined by the Authority).

(b) Within areas shown for Residential use in the Zonal Development Plans or Detailed Plans and wherein Group Housing is permitted :—

(i) a maximum floor area ratio and a maximum coverage per floor as specified for Group Housing in the particular residential area in the Master Plan, Zonal Development Plans and Detailed Plans as the case may be;

(ii) unless otherwise specified in the Detailed Plan, minimum set-backs of 15.24 metres (50 feet) in the front, 4.57 metres (15 feet) at the sides and 6.10 metres (20 feet) in the rear;

(iii) unless otherwise specified in the Detailed Plan, basements with minimum set-back lines and provided they are used only for the parking of vehicles and or the servicing and maintenance of the building;

(iv) a maximum height of 24.38 metres (80 feet) from road level to the top of the building (excluding the lift room and other mechanical equipment areas on the top of the building), unless otherwise specified by the authority or by the Delhi Urban Art Commission or as required by Airport regulations;

(v) parking provision as per item IV-2a(iii) above.

(c) Within plots shown for Residential use in the Zonal Development Plans or Detailed Plans and not qualifying for Group Housing :—

Regulations shall be as specified for plotted residential development in the Master Plan, the Zonal Development Plans and Detailed Plans as the case may be.

(3) The following zoning regulations shall apply to Hostels attached to Institutions :—

(a) for the total net plot within areas shown for institutional use under Public and Semi-Public facilities and for Government Offices in the Master Plan and/or Zonal Development Plans :—

(i) the minimum set-backs and basement shall be as specified for the institutional use under the categories of public and semi-public facilities and Government offices in the Master Plan, Zonal Development Plans and Detailed Plan as the case may be.

(ii) a maximum height of 36.60 metres (120 feet) from road level to the top of the building (excluding the lift room and other mechanical equipment areas on the top of the building), unless otherwise specified by the Authority or by the Delhi Urban Art Commission or as required by Airport regulations;

(iii) parking provision as per item IV-2A(iii) above.

(b) for the total Institutional plot as approved by the Authority in the Rural Zone of the Master Plan after special appeal :—

(i) minimum set-backs of 15.24 metres (50 feet) in the front, 4.57 metres (15 feet) at the sides and 6.10 meters (20 feet) in the rear or as specified in the Master Plan Zoning Regulations in case of agricultural green belt/rural zone whichever is more;

(ii) a maximum height of 7.62 metres (25 feet) from road level to the top of the building;

(iii) parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 square metres (1,000 sq. feet) of floor area.

5. Lodging Houses.—(1) Lodging Houses are permitted on plots within areas shown for Residential use in the Zonal Development Plans or Detailed Plans as the case may be.

(2) The following zoning regulations shall apply to Lodging Houses :—

(i) plots shall not exceed 1,254 square metres (1,500 sq. yds.) in net area;

(ii) other regulations shall be as specified for plotted residential development in the Master Plan, the Zonal Development Plans and Detailed Plans as the case may be.

6. **Motels.**—(1) Motels are permitted within the Agricultural Green Belt and the Rural Zone of the Master Plan and if allowed by the Authority after special appeal; provided that—

(i) the Motel is located along roads declared as National Highways and the building is set-back by at least 400 metres (1,320 feet) from the right-of-way of such a highway;

(ii) the motel is not within 1 K.m. (3,281 feet) from the urbanisable limits of Delhi and (iii) no two motels are within 1 k.m. (3,281 feet) from each other.

(2) The following Zoning Regulations shall apply to Motels :—

(i) a maximum plot size of 1.21 hectares (3.00 acres);

(ii) a maximum floor area of 1,858 square metres (20,000 sq. feet);

(iii) minimum set-backs of 15.24 metres (50 feet) in the front, 4.57 metres (15 feet) at the sides and 6.10 metres (20 feet) in the real;

(iv) parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 square metres (1,000 sq. feet) of floor area.

[No. F. 1(17)/74-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1976

का०आ० 212.—भारत के उपराष्ट्रपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति के नाते पंजाब विश्व-विद्यालय अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (1) (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 1-11-1976 से 4 साल की अवधि के लिए साधारण पार्षद मनोनीत करते हैं :—

(1) श्री श्याम चन्द, एक्साइज एण्ड टेक्शेसन, मिनिस्टर, हरियाणा प्राइवेट कोठी नं०-40, सेक्टर-2, चण्डीगढ़ ।

(2) श्री जी० सी जोशी, एम० एल० ए०, 582, माडल कालोनी, यमुना नगर, डिस्ट्रिक्ट-अम्बाला ।

[संख्या-10-वी०सी०/डी० एस०]

वि० फड़के,

भारत के उपराष्ट्रपति एवं पंजाब विश्व-विद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd January, 1977

S.O. 212.—The Vice-President of India, in his capacity as Chancellor of the Punjab University, Chandigarh, in exercise of his powers under Sub-section 1(j) of Section 13 of the Punjab University Act, is pleased to nominate the following as Ordinary Fellows of the Punjab University for the term commencing November 1, 1976, for a period of four years :—

1. Shri Shyam Chand, Excise & Taxation Minister, Haryana, Private Kothi No. 40, Sector 2, Chandigarh, and
2. Shri G. C. Joshi, M.L.A., 582, Model Colony, Yamunanagar, District Ambala.

[No. 10-VC/DS]

V. PHADKE,

Secy. to the Vice President of India and Chancellor of the Punjab University.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1977

सीमा शुल्क

का०आ० 213.—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 104-सी० शु० तारीख 26 अगस्त, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारिणी में क्रम सं० 50-क और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

[सं० 6/फा० सं० 541/4/73—एल सी आई]

यू० के० सेन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

New Delhi, the 15th January, 1977

CUSTOMS

S.O. 213.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government here makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 104-Customs, dated the 26th August, 1972, namely :—

In the Table appended to the said notification, Serial Number 50A and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 6/F. No. 541/4/73-I CI.]

U. K. SEN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977